रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24, 1983/पौष 3, 1905

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24, 1983/PAUSA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1983

आय-कर

का० आ० 4590.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, "श्री कोथान्डा रामस्वामी श्री अंजनेय स्वामी मन्दिर, अम्मापेट, जिला तंजावर, तमिलनाडु" को सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० 5480/फा० सं० 176/52/83-आ०क०नि-1]

वी० वी० श्रीनिवासन
निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 26th November, 1983

INCOME-TAX

S.O. 4590.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of section 80G of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Kothanda Ramaswami Sri Anjaneya Swami Temple, Ammapet, Thanjavur Dist., Tamil Nadu to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 5480/F. No. 176/52/83-IT(A1)]

आय-कर

का०आ० 4591.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा "श्री कृष्णस्वामी मन्दिर, रविपुरम, कोचिन" को समस्त केरल राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० 5481/फा०सं० 176/55/83-आ० क० (नि०-1)]

वी० वी० श्रीनिवासन, निदेशक

INCOME-TAX

S.O. 4591.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Sri Krishnaswamy Temple, Ravipuram Cochin' to be a pla-

of public worship of renown throughout the State of Kerala.

[No. 5481/F. No. 176/55/83-IT(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Director

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का० आ० 4592.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री आर० आर० खोसला को, जो पिछले दिनों नई दिल्ली में मुख्य आयुक्त (प्रशासन) और आयकर आयुक्त दिल्ली-1 के रूप में तैनात थे, 21 नवम्बर, 1983 पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० ए० 19011/20/83 प्रशा०-I]

जी० एस० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th November, 1983

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 4592.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri R. R. Khosla, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) and lately posted as Chief Commissioner (Admn.) and Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 21st November, 1983.

[F. No. A-19011/20/83-Ad. I]

G. S. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1983

आय-कर

का० आ० 4593.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड (iii) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में जारी की गई दिनांक 27-7-1983 की अधिसूचना सं० 5332 [फा० सं० 398/25/83-आ० का० (ब०)] को, जिनके अंतर्गत श्री भगवान दास तनेजा को कर वसूली अधिकारी नियुक्त किया गया था, एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

2. यह अधिसूचना, श्री भगवान दास तनेजा द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार सौंपे जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 5498/फा० सं० 398/25/83-आ० क०(ब०)]

New Delhi, the 6th December, 1983

INCOME-TAX

S.O. 4593.—The notification issued in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5332 [F. No. 398/25/83-IT(B)] date dthe 27th July, 1983, in pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) appointing Shri Bhagwan Dass Taneja as Tax Recovery Officer, is hereby cancelled.

2. This notification shall come into force with effect from the date Shri Bhagwan Dass Taneja hands over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5498/F. No. 398/25/83 IT(B)]

आय-कर

का०आ० 4594.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 31-12-1982 की अधिसूचना सं० 5051 [फा० सं० 398/4/82-आ०क०(ब०)] का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम० सी० रल्ह को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना, श्री एम० सी० रल्ह द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 5500/फा० सं० 398/25/83-आ०क०(ब०)]

बी० ई० अलैक्जेंडर, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 4594.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5051 [F. No. 398/4/82-IT(B)] dated 31-12-1982, the Central Government hereby authorises Shri M. C. Ralh, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri M. C. Ralh takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5500/F. No. 398/25/83-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली 30 नवम्बर, 1983

का० आ० 4595.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री मीर अमजद अली को अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 7 अक्तूबर, 1983 से प्रारम्भ होकर 31 अक्तूबर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री मीर अमजद अली अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 2-91/82 आर० आर० बी०]

एस०एस० हसूरकर उप सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 30th November, 1983

S.O. 4595.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Bank Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri Mir Amjad Ali as the Chairman of the Aligarh Gramin Bank, Aligarh and specifies the period commencing on the 7th October, 1983 and ending with the 31st October, 1986 as the period for which the said Shri Mir Amjad Ali shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-91/82-RRB]

S. S. HASURKAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4596.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के वास्ते सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इसका संबंध गिरवी-दार (प्लैजी) के रूप में मैसर्स इंडिया रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड प्रदत्त शेयर पूंजी में उनकी 30 प्रतिशत से अधिक की शेयर धारिता से है ।

[सं० 15/35/83-बी० ओ०-III]

एन० डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi; the 3rd December, 1983

S.O. 4596.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to the Central Bank of India, for a period of one year from the date of the notification in respect of its holding of shares in excess of 30 per cent of the paid-up share capital of M|s. India Re-construction Co. Ltd., as pledgee.

[No. 15|35|83-B.O.III]
N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4597.—निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 (1961 का 47) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बंबई के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एस० आर० बी० पुंजा को 1 जनवरी, 1984 से प्रारम्भ होने वाली और 14 दिसम्बर, 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के रूप में पुनः नामित करती है।

[सं० एफ० 6/1/83-बी० ओ०-I]
च० घा० मीरचन्दानी, उप सचिव

New Delhi, the 12th December, 1983

S.O. 4597.—In pursuance of the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby renominates Shri M. R. B. Punja, Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay as a Director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation for a further period commencing on the 1st January, 1984 and ending with the 14th December, 1985.

[No. F. 6/1/83-BO. I]
C. W. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय : कलकत्ता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिसूचना संख्या 6 के० उ०/1983

कलकत्ता, 2 नवम्बर, 1983

का० आ० 4598.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944, नियम 5 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए (यहां इसके बाद उल्लिखित "उपर्युक्त नियमावली") में, मैं० कु० बाजपेयी, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलकत्ता, इसके द्वारा इस समाहर्तालय की अधिसूचना सं०-1/के०उ०/81, दिनांक 27/2/81 में आगे निम्नलिखित संशोधन करता हूं :—

उपर्युक्त अधिसूचना में संलग्न विवरण के नियम 51क के समक्ष शब्दों, अंकों और कोष्टकों के लिए कालम (2) में आने वाली "स्व०नि० प० हस्त पुस्तिका के पैरा 15 के अन्तर्गत के मामलों की प्रकृति पढ़ें" (1) निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन सम्मिलित मामलों की प्रकृति :—

(क) कारखाने में अन्य वस्तुओं के निर्माण में व्यवहार के लिए प्राप्त/रोकी गई वस्तुएं, या

(ख) पुनः निर्माण, परिष्कार, नवीकरण, मरम्मत या कारखाने में इस प्रकार की अन्य प्रक्रिया हेतु वस्तुओं को कारखाने में वापस करना, या

(ग) शुल्क अदायगी के पश्चात् जब वस्तुएं ऐसी परिस्थितियों के कारण परिवहन नहीं की जा सकती जो निर्धारिती के नियंत्रण से परे हों जैसे रेलवे की बुकिंग का स्थगन, रेल वैगन का उपलब्ध न होना या वाहनों की खराबी, या

(घ) परीक्षण या डिजाइन अध्ययन या निर्माण पद्धति के लिए वस्तुओं की आवश्यकता, या

(ङ) खुदरा बिक्री या मानार्थ दान के रूप में देने के लिए या ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यक सुविधा अनुकूल कारखाना परिसर में वस्तुओं को संचित करने की आवश्यकता ।

(च) निर्माण या मरम्मत या ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए कारखाने में वस्तुओं की आवश्यकता जिसमें ऐसी वस्तुएं उपभोग की जाती हैं ।

[सी० सं० IV(8)1 के०उ०/82/एल०]

नरेन्द्र कुमार बाजपेयी, समाहर्ता

Collectorate of Central Excise : Calcutta

CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION NO. 6-CE|1983

Calcutta, the 2nd November, 1983

S.O. 4598.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rule, 1944 (hereinafter referred to as "the said Rules"), I, Sri N. K. Bajpai, Collector of C.E. Calcutta hereby make the following further amendment in this Collectorate Notification No. 1|CE|81 dated 27-2-81, namely :—

For the words, figure and brackets "(i) Types of cases covered by para 15 of SRP Hand Book" appearing in Col. (2) against Rule 51A in the statement appended to the said Notification read "(i) Types of cases covered under the following circumstance :—

(a) Goods received|retained for use in the mar of other goods in the factory; or

(b) Goods returned to the factory for being remade, refined, reconditioned, repaired or subjected to any other similar process in the factory; or

(c) When after payment of duty the goods cannot be transported due to circumstances beyond the assessee's control such as suspension of booking on Railways, non-availability of Railway wagon or brake-down of carriers; or

(d) Goods required for test or for studying design or method of construction; or

(e) Goods required to be stored in the factory premises for retail sale or for issue as complimentary gifts or for repacking into packages so as to suit the requirements of individual customers.

(f) Goods required in the factory for construction or repairs and/or for any other purpose for which such goods are normally consumed."

[C. No. IV(8) 1-CE/82/L]
N. K. BAJPAI, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4599.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का० आ० सं० 1909 तारीख 8 अप्रैल 1983 और का० आ० सं० 3071, तारीख 26 जुलाई 1983 द्वारा यथासंशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2234 तारीख 24 अप्रैल 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद 32 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"श्री मोहम्मद स्वालेह अंसारी मकान सं० 19/115, फातमां रोड, थाना शिवरामपुर के समीप, वाराणसी, उ० प्र०	}	अधिनियम की धारा 4 (3) (ञ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित।"।

[फा० सं० 25012/11/82-रेशम जिल्द I]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

New Delhi, the 5th December, 1983

S.O. 4599.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) S.O. No. 2234, dated the 24th April, 1982, as amended by the Notifications S.O. No. 1909, dated 8th April, 1983, and S.O. No. 3071 dated 26th July, 1983, namely:—

In the said notification, after item 32 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"33. Shri Mohd. Swaleh Ansari House No. 19/115, Fatman Road, Near Thana Shivrampur, Varanasi, U.P.		Nominated by the Central Government under section 4(3)(j) of the act."

[F.No. 25012/11/82-Silk Vol. I]

का० आ० 4600.—केन्द्रीय सरकार, यह अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता की अवधि 20-6-1983 को समाप्त हो गई है लोकसभा ने, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में लोकसभा के निम्नलिखित चार सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए 12 अगस्त, 1983 को अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सम्यक रूप से निर्वाचित किया है :—

1. श्री आर० पी० दास
2. श्री गंगाधर एस० कुचन
3. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
4. श्री समीनुद्दीन

[फा० सं० 25012/11/82-रेशम जिल्द I (i)]
के० चौधुरी, उप सचिव

S.O. 4600.—The Central Government hereby notify that the term of membership of the Members of Lok Sabha nominated as members of the Central Silk Board having expired on 20-6-83, the Lok Sabha has in pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), duly elected the following four Members of Lok Sabha, on 12th August, 1983 to serve as members of the Central Silk Board for a period of 3 years subject to the provisions of Act :—

1. Shri R. P. Das.
2. Shri Gangadhar S. Kuchan.
3. Shri V. Sreenivasa Prasad.
4. Shri Saminuddin.

[F. No. 25012/11/82-Silk Vol. I(i)]
K. CHAUDHURI, Dy. Secy.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात का कार्यालय
संख्या 3, विजय राघव रोड, टी० नगर, मद्रास-600017)

आदेश

मद्रास, 7 नवम्बर, 1983

का० आ० 4601.—सर्वश्री एस० डी० जी० मी० मेटल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड टी० एस० संख्या 30, गुड्स शेड रोड़, विरुदुनगर को अप्रैल-मार्च 1983 अवधि के लिए रुपए 36,00,000 तक टिनफ्री स्टील का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-डी०-2227700 सी/एक्सएक्स-86-82 दिनांक 28-3-1983 जारी किया गया था। उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराने और उसकी उपयोग करने के पहले खो जाने के कारण, उनकी अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए लाइसेंसधारी ने आवेदन किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्य पी/डी/2227700/सी/एक्सएक्स/86/82 दिनांक 28-3-83 की सीमशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों मूल प्रतियां खो दी गयी हैं और आदेश देता है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी किया जाये। लाइसेंस की मूल प्रतियां एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

मद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डी/2464826 दिनांक 31-10-83 तथा सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डी/2464827 दिनांक 31-10-83 अलग जारी किये जाते हैं।

[संख्या : आई०टी०सी०, डी०जी०टी०डी०-384-एएम 83-एयू-1]

सी० जी० फेरनान्डज, उप मुख्य नियंत्रक,
आयात तथा निर्यात

(Office of the Joint Chief Controller of Imports & Exports No. 3, Vijayaraghava Road, T. Nagar, Madras 17).

ORDER

Madras, the 7th November, 1983

S.O. 4601.—M/s. S.P.G.C. Metal Industries (P) Ltd., T. S. No. 30, Goods Shed Road, Virudhanagar were granted licence No. P|D|2227700|C|XX|86|82 dated 28-3-83 for Tinfree Steel for a value of Rs. 36,00,000 for the period March 82-April 83. They have requested us to issue a duplicate customs purpose copy and Exchange Control copy of above mentioned licence which have been lost without having been registered with any Customs authority and utilised at all.

In support of their contension the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that original copies of the licence No. P|D|2227700|C|XX|86|82 dated 28-3-83 (both customs purposes & Exchange control copies) have been lost and directs that a duplicate copy of the said licence. (Customs uurpose & Exchange control copies) should be issued to them. The original copies of the licence are hereby cancelled.

Duplicate licence No. D.2464826 dated 31-10-83 (Exchange control Copy) and No. D.2464827 dated 31-10-83 (customs purpose copy) have been issued separately.

[ITC|DGTD|384|AM83|AU I]

C. G. FERNANDEZ, Dy. Chief Controller
Imports & Exports.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर 1983,

का० आ० 4602.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 9 अगस्त, 1975 में प्रकाशित भारत सरकार भारी उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 2553 दिनांक 28 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में दी गई सारणी में, कालम (1) के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टि में "सहायक" शब्द के स्थान पर "वरिष्ठ" शब्द रखा जायेगा।

[फा० सं० 10-71/74-एच० ई० पी० II/एच० ई०पी० I]

एम० सिवम, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 3rd December, 1983

S.O. 4602.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Department of Heavy Industry No. S.O. 2553 dated 28th July, 1975 published in the Gaette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 9th August, 1975, namely :—

In the said notification, in the Table, in the entry under column (1), for the word "Assistant" the word 'Senior' shall be substituted.

[File No. 10-71|74-HEP-II|HEP-I]

M. SIVAM, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1983

का० आ० 4603.—केन्द्रीय सरकार, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, खनिज विकास बोर्ड के गैरपेंशनी कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित अंशदायी भविष्य निधि को लागू होंगे।

[सं० 10(9)/82 आर० एम० II]

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 24th October, 1983

S.O. 4603.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Contributory Provident Fund established for the benefit of non-pensionable employees of the Mineral Development Board.

[No. 10(9)/82-RM II]

का० आ० 4604.—केन्द्रीय सरकार, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में लौह अयस्क बोर्ड के स्थान पर खनिज विकास बोर्ड का नाम सार्वजनिक संस्था के रूप में जोड़ती है।

[सं० 10(9)/82-आर०एम० II]

ए० एन० खाले, अवर सचिव

S.O. 4604.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Fund Act 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the Mineral Development Board, as public institution, to the Schedule to the said Act in place of the Iron Ore Board.

[No. 10(9)/82-RM II]

A. N. KHALE, Under

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4605.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—सूरत तालुका—ओलपाड़

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टर	आरे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कीमामली	79	0	21	55
	80	0	12	14
	78	0	10	12
	कार्ट ट्रैक	0	03	04
	77	0	33	39
	76	0	49	56
	75	0	00	15
	69	0	52	61
	70	0	14	16
	68	0	27	31
	21	0	00	16
	67	0	04	05
	32/ए	0	46	54
	31	0	21	25
	30	0	02	02
	20	0	40	47
	19	0	14	16
	15/बी	0	03	04
	16	0	08	09
	17	0	12	14
	18/बी	0	01	01
	18/ए	0	20	23
	कार्ट ट्रैक	0	02	02
	4	0	20	23
	कार्ट ट्रैक	0	02	02
	3	0	01	01
	22/ए	0	00	35
	2	0	36	41

[सं० O-12016/145/83-प्रोड]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 8th December, 1983

S.O. 4605.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareily to Jagdishpur

State: Gujarat District : Surat Taluka : Olpad

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Kimamali	79	0	21	55
	80	0	12	14
	78	0	10	12
	Cart Track	0	03	04
	77	0	33	39
	76	0	49	56
	75	0	00	15
	69	0	52	61
	70	0	14	16
	68	0	27	31
	21	0	00	16
	67	0	04	05
	32/A	0	46	54
	31	0	21	25
	30	0	02	02
	20	0	40	47
	19	0	14	16
	15/B	0	03	04
	16	0	08	09
	17	0	12	14
	18/B	0	01	01
	18/A	0	20	23
	Cart Track	0	02	02
	4	0	20	23
	Cart Track	0	02	02
	3	0	01	01
	22/A	0	00	35
	2	0	36	41

[No. O-12016/145/83-Prod]

का० आ० 4606.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप संख्या जे० एल० एच० से जी० जी० एस० झालोरा-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० जे० एल० एच० से जी० जी० एस० झालोरा-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात   जिला—मेहसाना   तालुका—कड़ी

गांव	सर्वे० नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
करसनपुरा	83	0	15	68
	7	0	21	90
	8	0	03	15
	18	0	02	00

[सं० O-12016/141/83-प्रोड०]

S.O. 4606.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport port of petroleum from Well No. JLH to GGS Jhalora-1 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Auhority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. JLH to GGS Jhalora-1

State : Gujarat   District : Mehsana   Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centare
Karsanpura	85	0	15	68
	7	0	21	90
	8	0	03	15
	18	0	02	00

[No. O-12016/141/83-Prod]

का० आ० 4607.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार केअर्जित करना आवश्यक है ;

अत: अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी का मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात   जिला—सूरत   तालुका—ओलपाड़

गांव	ब्लाक नं	हेक्टर	आ-रे	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मुरत	172	0	53	70
	169	0	03	60
	168	0	34	20
	166	0	38	65
	184	0	06	50
	165	0	73	00
	कार्ट ट्रैक	0	19	50
	137	0	13	00
	140	0	53	49
	141	0	00	70
	142	0	40	40
	143	0	44	40

1	3	3	4	5
	109	0	64	50
	कार्ट ट्रैक	0	07	35
	104	0	04	30
	105	0	52	02
	102	0	14	08
	98	0	13	30
	99	0	15	75
	कार्ट ट्रैक	0	03	30
	100	0	00	60
	97/पी	0	24	30
	15	0	01	02
	16	0	17	35
	19	0	00	72
	18	10	03	04
	411	0	06	75
	412	0	00	15
	407	0	23	40
	404	0	18	40
	402	0	03	04
	416	0	00	30
	403	0	12	02
	400	0	02	70
	398	0	00	15
	399	0	08	09
	389	0	00	15
	390	0	09	80
	391	0	05	30
	383	0	30	15
	384	0	07	35
	385	0	19	50
	386	0	00	15
	379	0	10	50
	376	0	61	70
	377	0	44	50
	368	0	05	60
	कार्ट ट्रैक	0	06	00
	370	0	18	70
	369	0	31	15
	359	0	01	02
	353	0	25	30

[सं० O-12016/144/83-प्रोड]

S.O. 4607.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira To Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad

Village	Block No.	Hectare	Are	Centare
1	2	3	4	5
Mulad	172	0	53	70
	169	0	03	60
	168	0	34	20
	166	0	38	65
	184	0	06	50
	165	0	73	00
	Cart track	0	19	50
	137	0	13	00
	140	0	53	49
	141	0	00	70
	142	0	40	40
	143	0	44	40
	109	0	64	50
	Cart Track	0	07	35
	104	0	04	30
	105	0	52	02
	102	0	14	08
	98	0	13	30
	99	0	15	75
	Cart Track	0	03	30
	100	0	00	60
	97/P	0	24	30
	15	0	01	02
	16	0	17	35
	19	0	00	72
	18	0	03	04
	411	0	06	75
	412	0	00	15
	704	0	23	40
	404	0	18	40
	402	0	03	04
	416	0	00	30
	403	0	12	02
	400	0	02	70
	398	0	00	15
	399	0	08	09
	389	0	00	15
	390	0	09	80
	391	0	05	30
	383	0	30	15
	384	0	07	35
	385	0	19	50
	386	0	00	15
	379	0	10	50
	376	0	61	70
	377	0	44	50
	368	0	05	60
	Cart Track	0	06	00
	370	0	18	70
	369	0	31	15
	359	0	01	02
	353	0	25	30

[No. O-12016/144/83-Prod.]

का० आ० सं० 4608.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूचीत में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—सूरत तालुका—मांगरोल

गांव	ब्लोक नं०	हेक्टयर	आरे	सेन्टीयर
कुंवरबा	339	0	86	00
	340	0	22	26
	341	0	54	63
	353	0	19	22
	352	0	33	39
	351	0	00	48
	350	0	27	31
	347	0	23	27
	349	0	22	26
	348	0	00	68
	कार्टट्रेक	0	02	02
	236	0	35	41
	238	0	05	60
	237	0	05	60
	239	0	06	07
	कार्टट्रेक	0	06	07
	314	0	08	09
	309	0	63	74
	310	0	24	28
	306	0	08	09
	305	0	47	55
	304	0	00	32
	278/पी	0	56	66
	274/ए-बी	0	23	27
	279	0	47	55
	280	0	75	88
	287	0	32	37
	285	0	12	14

[सं० O-12016/135/83-प्रोड]

राजेन्द्र सिंह, निदेशक

1147 GI/83—2

S.O. 4608.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Auhority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly To Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen tare
Kuvarda	339	0	86	00
	340	0	22	26
	341	0	54	63
	353	0	19	22
	352	0	33	39
	351	0	00	48
	350	0	27	31
	347	0	23	27
	349	9	22	26
	348	0	00	68
	Cart track	0	02	02
	236	0	35	41
	238	0	05	60
	237	0	05	60
	239	0	06	07
	Carg track	0	06	07
	314	0	08	09
	309	0	63	74
	310	0	24	28
	306	0	08	09
	305	0	47	55
	304	0	00	32
	278/P	0	56	66
	274/A-B	0	23	27
	279	0	47	55
	280	0	75	88
	287	0	32	37
	285	0	12	14

[No. O-12016/135/83-Prod.]

RAJENDRA SINGH, Director

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4609.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की

अधिसूचना सं० का० आ० 228, दिनांक 26 अक्तूबर, 1982 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त, रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1010.00 एकड़ (लगभग) या 408.72 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 1010.00 एकड़ (लगभग) या 408.72, हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० रा०/14/83 दिनांक 7-4-1983 का निरीक्षण उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

उरीमेरी ब्लाक विस्तार-1 (बलरामपुर)
(दक्षिणी करनपुरा कोयला क्षेत्र)
जिला हजारीबाग (बिहार)

सभी अधिकार

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना सं	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	उरीमेरी	बरका गांव	155	हजारीबाग	610.01	भाग
2	जरजरा	बरका गांव	150	हजारीबाग	399.99	भाग
		कुल क्षेत्र	—		1010.00 एकड़ (लगभग) 408.72 हैक्टर (लगभग)	

ग्राम उरीमेरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :—

1 से 1 ?, 148 (भाग), 149 से 157, 158 (भाग), 159, 160 (भाग), 161, 162 (भाग), 163 (भाग), 181 (भाग), 194 (भाग), 195 (भाग), 196 (भाग), 197 से 271, 272 (भाग), 273 से 279, 280 (भाग), 281 (भाग), 287 (भाग), 288 (भाग), 313 (भाग), 439 (भाग) 440 से 520, 521 (भाग), 522, 544 (भाग), 545, 546 (भाग), 547 से 550, 551 (भाग), 552 (भाग), 554 से 556, 557 (भाग), 558 (भाग), 561, 562 (भाग), 563 (भाग), 564 से 619, 620 (भाग), 621 से 642, 643 (भाग), 644 (भाग), 645 (भाग), 646 (भाग), 732 (भाग), 733 से 751, 753, 754, 755 (भाग), 667, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 (भाग), 789 (भाग), 790 (भाग), 791 (भाग), 802 (भाग) और 803.

ग्राम जरजरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :—

61 (भाग), 65 (भाग), 70 (भाग), 71 (भाग), 72 से 76, 77 (भाग), 78 (भाग), 79 से 87, 88 (भाग), 89 (भाग), 196 (भाग), 197, 198 (भाग), 199 (भाग), 200 (भाग), 339 (भाग), 947 (भाग) 951 (भाग), 972 (भाग), 1031 (भाग), 1048 (भाग), 1050 (भाग), 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056 (भाग), 1059 (भाग), 1060 (भाग), 1061 (भाग) और 1075।

सीमा वर्णन

क-ख रेखा ग्राम उरीमेरी में प्लाट संख्यांक 788, 790, 789, 791 और 802 से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित उरीमेरी की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख–ग रेखा ग्राम उरीमेरी में प्लाट संख्यांक 802, 521, 439 से होकर प्लाट संख्यांक 438 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्यांक 313 से होकर फिर प्लाट संख्यांक 134, 140 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्यांक 148, 162, 163, 160, 158, 181, 194, 196, 195, 281, 280, 287, 288, 272, 620, 544, 546, 551, 552, 557, 558, 563, 562, 644, 645, 643, 646, 732 और 755 से होकर जाती है (जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित उरीमेरी ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग–घ रेखा ग्राम उरीमेरी में दामोदर नदी के भागतः बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ–ङ. रेखा ग्राम उरीमेरी और धरसुला की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ." पर मिलती है।

ङ.–च रेखा ग्राम जरजरा और धरसुला की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च–छ रेखा ग्राम जरजरा के प्लाट संख्यांक 1060, 947, 951, 1059, 1061, 1056, 1059, 972, 1081, 1048, 1031, 1050, 1031, 200, 199, 88, 199, और 200 से होकर प्लाट संख्यांक 339 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ-ज-झ रेखाएं ग्राम जरजरा में प्लाट संख्यांक 339, 196, 198, 89, 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 और 70 से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ–ण रेखा ग्राम जरजरा और पोटांगा की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है।

ण–क रेखा ग्राम उरीमेरी और पोटांगा की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा सं. 19/25/83-सी. एल.]
समय सिंह, अवर सचिव

(Department of Coal)

New Delhi, the 7th December, 1983

S.O. 4509.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 228 dated the 26th Oct., 1982, under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority, in persuance of section 8 of the said Act. has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid, and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 1010.00 acres (approximately) or 408.72 hectares (approximately), described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 1010.00 acres (approximately) or 408.72 hectares (approximately), described in the said Schedule, are hereby acquired.

The plans No. Rev/14/83 dt. 7-1-83 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Urimari Block Extension-I (Balrampur)
(South Karanpura Coalfield) Distt. Hazaribagh (Bihar)

All Rights

Serial number	Village	Thana	Thana number
1.	Urimari	Barkagaon	155
2.	Jarjara	,,	156

District	Area	Remarks
Hazaribagh	610.01	Part
,,	399.99	,,

Total area : 1010.00 acres (approximately)
or 403.72 hectares (approximately)

Plot numbers acquired in village Urimari :—

1 to 138, 148(Part), 149 to 157, 158(Part), 159, 160(Part) 161, 16 (Part), 163(Part), 181(Part), 194(Part), 195(Part), 196(Part), 197 to 271, 272(Part), 273 to 279, 280(Part), 281 (Part), 287(Part), 288(Part), 313(Part), 439(Part), 440 to 520, 521(Part), 522, 544(Part), 545, 546(Part), 547 to 560, 551 (Part), 552 (Part), 554 to 555, 557(Part), 558(Part), 561, 562(Part), 563(Part), 564 to 619, 620(Part), 621 to 642, 643(Part), 644 (Part), 645 (Part), 646(Part), 732 (Part), 733 to 751, 753 754, 755(Part), 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 736, 737, 738(Part), 789(Part), 790(Part), 791(Part), 802(Part), & 803.

Plot numbers acquired in village Jarjara :—

64(Part), 65(Part), 70(Part), 71(Part), 72 to 76, 77(Part), 78(Part), 79 to 87, 83(Part), 89(Part), 196(Part), 197, 198(Part), 199(Part), 200(Part), 339(Part), 947(Part), 951(Part), 972(Part), 1031(Part), 1048(Part), 1050(Part), 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056(Part), 1059(Part), 1060(Part), 1061(Part), and 1075.

Boundary Description :

A-B Line passes through plot numbers 788, 790, 789, 791, & 802 in village Urimari [which forms part common boundary of the Urimari Block acquired u/s 9(1) of the said Act and meets at point 'B'].

B-C Line passes through plot numbers 802, 521, 439, along the northern boundary of plot number 438 through plot number 313 then along the northern boundary of plot numbers 134, 146, through plot numbers 148, 162, 163, 160, 158, 181, 194, 296, 195, 281, 280, 287, 288, 272, 620, 544, 546, 551, 552 557, 558, 563, 562, 644, 645, 643, 646, 732 & 755 in village Urimari (which forms part common boundary of Urimari Block acquired u/s 9(1) of the said Act and meets at point 'C'].

C-D Line passes along the part left bank of Damodar River in village Urimari and meets at point 'D'.

D-E Line passes along the common boundary of villages Urimari and Garsula and meets at point 'E'.

E-F Line passes along the part common boundary of villages Jarjara and Garsula and meets at point 'F'.

F-G Line passes through plot numbers 1060, 947, 951, 1059, 1061, 1056, 1059, 972, 1031, 1048, 1031, 1050, 1031, 200, 199, 88, 199 & 200 eastern boundary of plot number 339 in village Jarjara and meets at point 'G'.

G-H-I Lines pass through plot numbers 339, 196, 198, 89, 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 & 70 in village Jarjara and meet at point 'I'.

I-J Line passes along the part common boundary of villages Jarjara and potanga and meets at point 'J'.

J-A Line passes along the part common boundary of villages Urimari & Potanga and meets at starting point 'A'.

[No. 19/25/83-CL.]
SAMAY SINGH, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4610.—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) तारीख 18 सितम्बर, 1982 में पृष्ठ 3352-3357 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग, की अधिसूचना का० आ० सं० 3297 तारीख 1 सितम्बर, 1982 में :—

अनुसूची में : —ग्राम—दुर्गापुर, जिला—चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) :—

(1) मामला सं 1क में "श्री चन्द्रपुर के स्थान पर "चन्द्रपुर" पढ़िए।
—"— " 2 में "श्री चन्द्रपुर" के स्थान पर "चन्द्रपुर" पढ़िए।
(2) —"— " 6 में "धना बाधामारे" के स्थान पर "गना बाधमारे" पढ़िए।
(3) —"— " 7 में "कावाडू टोउसे" के स्थान पर "कवडू मोडामे" पढ़िए। और "विठू ताम्णडे" के स्थान पर "विठू नलांडे" पढ़िए।
(4) —"— " 9 में "जेतपूरा बाडे" के स्थान पर "जेटपूरा वार्डे" पढ़िए।
(5) —"— " 10 में "शेख करीफ" के स्थान पर "शेख कारीफ" पढ़िए।
(6) —"— " 11 में "जिवाने" के स्थान पर "जिवने" पढ़िए।
(7) —"— " 12 में "जेतपुरा" के स्थान पर "जेटपूरा" पढ़िए।
(8) —"— " 14 में "पंगाणास्त्री" के स्थान पर "परिक्षती" पढ़िए।
(9) —"— " 15 में "नाथू रामपूरे का पुत्र श्री घटपतिनाथ" के स्थान पर "नथ्थू रायपूरे का पुत्र श्री चरपतिनाथ" पढ़िए।

(10) मामला सं. 16क में "मैश्राराम" के स्थान पर "मेश्राम" पढ़िए।
(11) —,,— ,, 16ख में "पायकाजी भोयेर" के स्थान पर "पैकाजी भोयर" पढ़िए।
(12) —,,— ,, 20 में "मलयस दुर्गा दुर्योधन" के स्थान पर "मलया दुर्गा दुर्योधन" पढ़िए।
(13) —,,— ,, 21 में कालम सं० 5 के खाली स्थान में "2, 10" दिखाइए।
(14) —,,— ,, 23 मे "सामेलिंग" के स्थान पर "सोमालिंगा" पढ़िए।
(15) —,,— ,, 24 में "नारेगे" के स्थान पर "नरांजे" पढ़िए, । "रामटेक" के स्थान पर "रामटेके" पढ़िए तथा "मेश्राराम" के स्थान पर "मेश्राम" पढ़िए ।
(16) —,,— ,, 26 में "केतकर" के स्थान पर "काटकर" पढ़िए।
(17) —,,— ,, 28 में "नानिमालिंग मुंजेवर" के स्थान पर "नानिग्या लिंगा मुंजेवार" पढ़िए ।
(18) —,,— ,, 29 में "जेकब मेश्राराम" के स्थान पर "जेकब मेश्राम" पढ़िए।
(19) —,,— ,, 30 में "आयाराम" के स्थान पर "आसाराम" पढ़िए और "श्रीमती सवार्ते" के स्थान पर "श्रीमती सावर्ता" पढ़िए।
(20) —,,— ,, 31 में "नारंगे" के स्थान पर "नरांजे" पढ़िए।
(21) —,,— ,, 32 और 33 में "मानकड" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए।
(22) —,,— ,, 35 में "गवांडे" के स्थान पर "गांवडे" पढ़िए ।
(23) —,,— ,, 36 में "मान्कड" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए, श्रीमती "छब्रगुना बाई" के स्थान पर "चांगुना बाई" पढ़िए तथा "शारदा मधुकर" के स्थान पर "शरद मधुकर (अवयस्क) संरक्षक माता श्रीमती शांता मधुकर" पढ़िए।
(24) —,,— ,, 41 में "पवमपूर" के स्थान पर "पवमापूर" पढ़िए।
(25) —,,— ,, 42 में "फाहिक" के स्थान पर "फईम" पढ़िए, । "कोलासिवाला" के स्थान पर "कोलसावाला" पढ़िए तथा "कोलासवाला" के स्थान पर "कोलसावाला" पढ़िए।
(26) —,,— ,, 43 में "पाखु रायपुर" के स्थान पर "पतु रायपुरे" पढ़िए।
(27) —,,— ,, 45 में "भादुनवले" के स्थान पर "मधु नाकले" पढ़िए।
(28) —,,— ,, 46 में "नागराले" के स्थान पर "नगराले" पढ़िए।
(29) —,,— ,, 47 में "जैतपूरा" के स्थान पर "जैटपूरा" पढ़िए।
"येनुरकर" के स्थान पर "येनुरकर" पढ़िए।
"सेखुबाई" के स्थान पर "सखुबाई" पढ़िए।
"भैयाजी", के स्थान पर "भय्याजी, पढ़िए तथा
"अनुरकर" के स्थान पर "येनुरकर" पढ़िए।
(30) —,,— ,, 47 में "येनुकर/येवुकर" के स्थान पर "येनुरकर" पढ़िए।
(31) —,,— ,, 48 में "मान्कड" के स्थान पर 'मानकर" पढ़िए।
(32) —,,— ,, 49 में "सलपुरे" के स्थान पर "सातपुते" पढ़िए।
(33) —,,— ,, 50 में "कटोरे" के स्थान पर "कातोरे" पढ़िए, "बाबन" के स्थान पर "बबन" पढ़िए तथा "सुभाले" के स्थान पर "सुमाले" पढ़िए।
(34) —,,— ,, 52 में "राम" के स्थान पर "रामू" पढ़िए।
(35) —,,— ,, 54 में "मानकड" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए।
(36) —,,— ,, 55 में "प्राणलाल" के स्थान पर "अजाबराव" पढ़िए, "बल्लारपुर" के स्थान पर "बल्लारपूर" पढ़िए तथा "ढांगे" के स्थान पर "ढगे" पढ़िए।
(37) —,,— ,, 59 में "पिटस" के स्थान पर "पिटर्स" पढ़िए।
(38) —,,— ,, 60 में "चन्देकर तथा चन्देकर" के स्थान पर "चांदेकर पढ़िए।
(39) —,,— ,, 61 में "काबाडू" के स्थान पर "कवडू" पढ़िए, "टोइसे" के स्थान पर "सोडासे" पढ़िए तथा "तालंडे" के स्थान पर "तन्नांडे" पढ़िए
(40) —,,— ,, 63 में "जूमादे" के स्थान पर "जुमडे" पढ़िए।
(41) —,,— ,, 65 मे "मान्कड" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए।
(42) मामला सं. 69 "सखाराम शेकर" के स्थान पर "सखाराम शंकर" पढ़िए।
(43) —,,— ,, 74 में "शिडे" के स्थान पर "शेन्डे" पढ़िए।
(44) —,,— ,, 75/76 में "टामेकर" के स्थान पर "टामटकर" पढ़िए।
(45) —,,— ,, 77 में "शिडे" के स्थान पर "शेंडे" पढ़िए।
(46) —,,— ,, 79 में "सत्याफुले" के स्थान पर "सत्यफुला" पढ़िए तथा "विजराव" के स्थान पर "विजयराव" पढ़िए।
(47) —,,— ,, 80 में "मान्कड्या" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए।
"रख्बोदास" के स्थान पर "रख्बेदास" पढ़िए।
"मेय्या" के स्थान पर "भय्या" पढ़िए।
"बायाबाई" के स्थान पर "बयाबाई" पढ़िए।
"एकनाथ उर्फे" के स्थान पर "एकनाथ ओर्के" पढ़िए तथा "बा-मारे" के स्थान पर "बाघ मारे" पढ़िए।
(48) —,,— ,, 82 में "मिकाजी" के स्थान पर "भिकाजी" पढ़िए।
(49) —,,— ,, 83 में "आम्दी" के स्थान पर "आमडी" पढ़िए।
(50) —,,— ,, 84 में "बिचोडे" के स्थान पर "बिचोडा" पढ़िए।
(51) —,,— ,, 89 में "मानाजी" के स्थान पर "मनाजी" पढ़िए।
(52) —,,— ,, 90 में "सम्मा खाटी" के स्थान पर "संभा खटी" पढ़िए।
(53) —,,— ,, 98 में "वादगांव" के स्थान पर "वडगांव" पढ़िए और "लाहु सम्भा" के स्थान पर "लहु संभा" पढ़िए।
(54) —,,— ,, 99 में "पटक" के स्थान पर "पतु" पढ़िए।
(55) —,,— ,, 101 में "टुकुम-टुकुम" के स्थान पर "तुकुंम" पढ़िए।
(56) —,,— ,, 102 में "मोहम्मद उमेर" के स्थान पर "मोहम्मद उमर" पढ़िए।
"उस्मल" के स्थान पर "उस्माल" पढ़िए तथा "फक" के स्थान पर "फक्कु" पढ़िए।
(57) —,,— ,, 115 में "जैतपुरा वार्ड" के स्थान पर "जेटपुरा वार्ड" पढ़िए तथा "ताबाजी येराले" के स्थान पर "तामबाजी येरणे" पढ़िए।
(58) ,, , 119 में "वाड" के स्थान पर "वार्ड" पढ़िए तथा "तिपाले" के स्थान 120 पर "टिपले" पढ़िए।
(59) —,,— ,, 123 में "जादे" के स्थान पर "झाडे" पढ़िए।
(60) —,,— ,, 124 में "वाड" के स्थान पर "वार्ड" पढ़िए और "तंपाले" के स्थान पर "टिपले" पढ़िए।
(61) —,,— ,, 126 में "बानौरा" के स्थान पर "बनौरा" पढ़िए तथा "तिपाले" के स्थान पर "टिपले" पढ़िए।
(62) —,,— ,, 128 में "जैतपूरा" के स्थान पर "जेटपूरा" पढ़िए।
(63) —,,— ,, 132 में "रामचन्द्र" के स्थान पर "रामचंद्र" पढ़िए।
(64) —,,— ,, 136 कालम सं० 6 में "22, 185.50" के स्थान पर "22, 186.50" पढ़िए।
(65) —,,— ,, 137 में कालम सं० 6 में "80, 630.55" के स्थान पर "80, 630.50" पढ़िए।
(66) —,,— ,, 138 में "उमेर" के स्थान पर "उमर" पढ़िए।
(67) —,,— ,, 139 में "गधर्वदास" के स्थान पर "गंधर्वदास" पढ़िए।
(68) —,,— ,, 148 में "जाम" के स्थान पर "झामा" पढ़िए।
(69) —,,— ,, 149 में "लिंग" के स्थान पर "लिंगा" पढ़िए।
(70) —,,— ,, 150 में "केटकर" के स्थान पर "काटकर" पढ़िए।
(71) —,,— ,, 151 में "जाडे" के स्थान पर "झाडे" पढ़िए।
(72) —,,— ,, 154 में "दामती" के स्थान पर "दयामती" पढ़िए।
(73) —,,— ,, 155 में "सोवल दास" के स्थान पर "सावलदास" "मान्कड" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए, "मेतराव" के स्थान पर "मेटराम" पढ़िए, "रतनपाल" के स्थान पर "रत्नमाला" पढ़िए तथा "छंगुना" के स्थान पर "चांगुना" पढ़िए।
(74) —,,— ,, 157 में "भडगांव" के स्थान पर "बडगांव" पढ़िए।
(75) —,,— ,, 158 में "चन्द्रा" के स्थान पर "चन्द्रपुर" पढ़िए।

(76) मामला सं० 159 में "टुकुम" के स्थान पर "तुकूम" पढ़िए और "दावमिया" के स्थान पर "दादामिया" पढ़िए।
(77) —"— " 160 में "राममूर्ती" के स्थान पर "राममुर्ती मायडू" पढ़िए।
(78) —"— " 162 में "ध्यमेश्वर" के स्थान पर "ज्ञानेश्वर" पढ़िए।
(79) —"— " 165 में "मान्काड" के स्थान पर "मानकर" पढ़िए।
(80) —"— " 166 में "भाजुजी" के स्थान पर "भदुजी" पढ़िए।
(81) —"— " 167 में "बाड" के स्थान पर "बार" पढ़िए तथा "बालीचन्द्र" के स्थान पर "बलीचन्द्र" पढ़िए।
(82) —"— " 170 में "बाडगांव" के स्थान पर "बडगांव" पढ़िए।
(83) —"— " 172 में "इतान्कर" के स्थान पर "ईटनकर" पढ़िए।
(84) —"— " 174 में "गोबिंदगार" के स्थान पर "गोविंदराव" पढ़िए।
(85) —"— " 56 में "का पुत्र" के स्थान पर "के पुत्र" पढ़िए तथा "लोनले" के स्थान पर "लोनाभे" पढ़िए।

अनुसूची में : —ग्राम देवई गोविंदपुर जिला—चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

1 मामला सं. 3 में "समुनबाई" के स्थान पर "सुमनबाई" पढ़िए।
2. मामला सं. 4 में "बाला बैरानेडे" के स्थान पर "बाला बैरागडे" पढ़िए।
3. मामला सं. 5 में "जैतपुर" के स्थान पर "जैटपूरा" पढ़िए।
4. मामला सं. 7 में "मानापेठ" के स्थान पर "भानापेठ" पढ़िए।
5. मामला सं. 9 में "ताजाने" के स्थान पर "ताजने" पढ़िए।
6. मामला सं. 10 में "उपागनल्लाकर" के स्थान पर "उपगनल्लावार" पढ़िए।
7. मामला सं. 12 में "टुकुम" के स्थान पर "तुकूम" पढ़िए, "गमा" के स्थान पर "गया" पढ़िए तथा "मेनाबाई" के स्थान पर "मैनाबाई" पढ़िए।
8. मामला सं. 13 में "कोलटे" के स्थान पर "कोमने" पढ़िए।
9. मामला सं. 14 में "गणपति सिंह सहूसिंह" के स्थान पर "गणपतसिंह सध्यू सिंह" पढ़िए।
10. मामला सं. 15 में "चन्द्रनगर" के स्थान पर "चंद्रपुर" पढ़िए।

ग्राम—सिन्हाला, जिला—चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

1. मामला सं. 1 में "विश्वया उरकुड" के स्थान पर "विठया उरकुडा" पढ़िए।
2. —"— " 5 में "बिटाऊ" के स्थान पर "बिटाऊ" पढ़िए।
3. —"— 9 में "जय" के स्थान पर "जाई" पढ़िए।

[सं. 13/3/82-सी. एल.]
समय सिंह, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1983

का०आ० 4611.—पशु आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 9) के खंड 3, उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 27-11-1983 से छः महीने की अवधि के लिए यू० के० आयरलैण्ड, अमेरिका, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी, बैलजियम, जापान, आस्ट्रीया, डेनमार्क और इटली, ब्राजील और यूगोस्लाविया से अश्वजातीय पशुओं के आयात पर एतद्द्वारा प्रतिबंध लगाती है। यह प्रतिबंध 4 वर्ष तक की आयु के अश्वकों और अश्व-शावकों (फोलीज) पर लागू नहीं होगा जिनका कभी मेल नहीं कराया गया है और जो प्रजनक स्टाफ के सम्पर्क में नहीं रहे हैं, बशर्ते कि :—

(क) अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त युवा अश्वजातीय पशुओं के साथ प्राधिकृत पशु-चिकित्सक का इस आशय का पशु चिकित्सा संबंध एक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हो कि पशु गत एक वर्ष के दौरान प्रजनक स्टाक के सम्पर्क में नहीं रहा है और इन पशुओं के शिश्नच्छद तथा मूत्रमार्ग (योनि और गर्भाशय में एकत्र की गई फुरेरी मानक संवर्धनिक और सीरम संबंधी पद्धतियों द्वारा व्याधि विषयक सूक्ष्म अणुओं, विशेषकर हिमोफिलियस इक्वीजेनीटैलिस के लिए निर्यात हेतु पोतारोहण के 30 दिनों के अन्दर निरन्तर तीन परीक्षण करने पर नकारात्मक पाई गई है।

(ख) भारत में प्राप्त किए जाने पर आयातित पशुओं को कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परिसर में 30 दिन तक अलग रखा जाएगा। संगरोध की अवधि के दौरान पशुओं का एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में साप्ताहिक अंतराल पर निरन्तर तीन बार जीवाणु और सीरम संबंधी संवर्धनिक जांच की जाएगी और संक्रामक अश्वजातीय मैट्रिईटिस (कान्टेजियेस इक्वाईज मैट्राइटस) रोग के लिए नकारात्मक घोषित किए जाने के बाद ही इन पशुओं को अन्य पशुओं के साथ मिलाया जाएगा।

[सं० 50-22/77-एल०डी०टी० (एल० एच०-ए० क्यू) खंड 2]
टी० आर० त्रेहन, अवर सचिव (पशुपालन)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 12th December, 1983

S.O. 4611.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) the Central Government hereby prohibit for a period of six months with effect from 27-11-1983 the import from U.K., Ireland, U.S.A., France, Australia, Federal Republic of Germany, Belgium, Japan, Austria, Denmark, Italy, Brazil and Yugoslavia of the equine species of animals except colts and follies upto 4 years of age which have never been mated and have not been in contact with breeding stock provided that :—

(a) In addition to the health requirements specified under the Act, the young equines are accompanied by a veterinary Health Certificate from an authorised veterinarian that the animals have not been in contact with the breeding stock during the last one year and that the swabs collected from prepuce Urethra|Vagina and Cervix of these animals were found negative for pathogenic micro-organisms specifically Haemophilus equigenitalis by standard culture and seralogical methods, on three consequtive testing within 30 days of embarkation for export.

(b) On the receipt in India such imported animals are kept in quarantine for a minimum period of 30 days at the permises approved by the Ministry of Agriculture. During the quarantine period, the animals shall be subjected to bacterioligical and serological examination by a recognised laboratory on three consecutive occassions conducted at weekly intervals and will be mixed with other stock only when declared negative for contagious equine metritis infection.

[No. 50-22/77/LDT(LH-AQ) Part II]
T. R. TREHAN, Under Secy.

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1983

का० आ० 4612.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम

(4) के अनुसरण में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :—

1. राष्ट्रीय शर्करा संस्था कानपुर (उ०प्र०)

[सं० ई०-11017/5/83-हिन्दी]

एन० के० एस० झाला निदेशक (विधायन)

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 29th November, 1983

S.O. 4612.—In pursuance of sub-rule 4 of rule 10 of Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following subordinate office of the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food), the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. National Sugar Institute, Kanpur (U.P.)

[No. F-11017/5/83-Hindi]

N. K. S. JHALA, Director (Processing)

(नागरिक पूर्ति विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 17 नवम्बर 1983

का०आ० 4613— समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में जिन 89 लाइसेंसों के ब्यौरे दिए गए है । लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार अक्तूबर 1980 में स्वीकृत किया गया है :

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या सीएम/एल	बैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी भारतीय पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीएम/एल—9037 1980-10-06	80-10-16	81-10-15	इंडियन ट्रेडर्स प्रा० लि० नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015	तांबे व एलुमिनियम के चालकों वाले कवचदार, कवचरहित 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता वाले, भारी कार्य के लिए पी०वी० सी० रोधित केबल— IS : 1554 (भाग-1)—1976
2.	सीएम/एल—9038 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	सरदार रोलिंग मिल्स न्यू कालोनी मंदसौर 458001 (मध्य प्रदेश)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226—1975
3.	सीएम/एल—9039 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	जैस्थ फोजिंग एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, 95-ए चितरंजन एवेन्यू० कलकत्ता-700073, (कार्यालय : 13, ब्रैबोर्न रोड कलकत्ता-700001)	फोर्ज किए सी०टी०सी० खंड IS : 8748—1978
4.	सीएम/एल—9040 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	बाम्बे प्रोटीन मैन्यु० कं० भालेज रोड, आनन्द-388001 (गुजरात)	लड़दार एलुमिनियम चालक व जस्तीकृत इस्पात से प्रबलित एलुमिनियम चालक— IS : 398 (भाग I व II)—1976
5.	सीएम/एल—9041 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	महाबीर इंडस्ट्रीज 1, बरौनी इंडस्ट्रीयल एरिया पो० आ० तिसरथ जिला बेगूसराय (बिहार)	लड़दार एलुमिनियम चालक व जस्तीकृत इस्पात से प्रबलित एलुमिनियम चालक— IS : 398 (भाग I व II)—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. सीएम/एल-9042 1980-10-10		80-10-16	81-10-15	जोधपुर केबल्स एंड कंडक्टर्स प्रा० लि० 17, साइट इंडस्ट्रीज एरिया, जोधपुर	लड़दार एलुमिनियम चालक व-जस्तीकृत इस्पात मे प्रबलित एलुमिनियम चालक— IS : 398(भाग I व II)—1976
7. सीएम/एल-9043 1980-10-10		80-10-16	81-10-15	गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा० लि० चेस्ट डीजिज अस्पताल के पास कैरंज बाग, प्रन्तीज रोड, नरोड़ा अहमदाबाद 382330 गुजरात (कार्यालय : श्वेत उद्योग भवन, नई कोर्ट के सामने, नवरंग पुरा, अहमदाबाद-380014 (गुजरात)	कारबेराइल धूलन चूर्ण— IS : 7127—1977
8. सीएम/एल-9043 1980-10-10		80-10-16	81-10-15	तारापुर कैमिकल्स एंड पैस्टिसाइड्स प्लाट नं० ई-47 तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया, बॉयसर- 401501 जिला थाना, महाराष्ट्र	डी० डी० टी० जल परिक्षेपी तेज पाउडर— IS : 565—1975
9. सीएम/एल-9045 1980-10-10		80-10-16	81-10-15	अरुणोदय मेटल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० सर्वे नं० 14, हिस्सा नं० 1 पिंगुली गांव पो० आ० ताल कुंडाल जिला रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	पिटवां एल्युमिनियम के बर्तन ग्रेड 1900 IS : 1660 (भाग I व II)— 1967
10. सीएम/एल-9046 1980-10-10		80-10-16	81-10-15	नेशनल एग्रो केमीकल्स सी-2 इंडस्ट्रीयल एरिया पटना-800013 (बिहार)	एल्डरीन पायसनीय सान्द्र— IS : 1307—1973
11. सीएम/एल-9047 1980-10-10		80-10-16	80-10-15	पेस्टीसाइड्स इंडिया उदयसागर-रोड उदयपुर-313001 (राजस्थान)	कार्बेराइल जल परिक्षेपी तेज पाउडर, केवल हवाई फुहार के लिए— IS : 7121—1973
12. सीएम/एल-9048 1980-10-10		80-10-16	81-10-15	मल्होत्रा स्टील कार्पोरेशन मल्होत्रा रोड, उधव अहमदाबाद-382410	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पात की छड़ें— साइज-सांकेतिक व्यास 25 मिमी— IS : 1786—1966
13. सीएम/एल-9049 1980-10-10		80-9-16	81-9-15	मशीनएज प्रा० लि०, नरोडा रोड अहमदाबाद-380025 (गुजरात)	कृषि प्रयोजनों के लिए साफ ठंडे ताजे पानी के मोनोसेट पम्प (केवल निम्नलिखित साइजों वाले)
	साइज 65 × 50 मिमी	मोटर 3.7 वर्ग ई	गति चक्कर प्रति मिनट 2880	टाइप/मॉडल ई एस	ड्यूटी पॉइंट 18 मीटर हैड पर निकासन 12.8 मिटर प्रति सेकेंड व समग्र क्षमता 47%
	62 × 50 मिमी	5.5 किवा वर्ग ई	2880	ई एस	3.5.0 मीटर हैड पर निष्कासन 9.01 लिटर प्रति सेकेंड व समग्र क्षमता 44% : IS : 6595—1972 व IS : 7538—1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	सीएम/एल- 9050 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	विजय कुमार शंकर मैच इंडस्ट्रीज 146 व 147 मुडंगनाडार स्ट्रीट शिवकासी (तमिलनाडु) (कार्यालय : 72 जुबलीकाडी स्ट्रीट शिवकासी 626123)	दियासलाई की डिब्बियां-- IS : 2653--1964
15.	सीएम/एल- 9051 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	विजयलक्ष्मी मैच इन्डस्ट्रीज 209/आईसी--4 विश्वनाथम शिवकासी 626123 (तमिलनाडु) (कार्यालय : 72 जबुलीकाडी स्ट्रीट शिवकासी 626123 (तमिलनाडु)	दियासलाई की डिब्बियां-- IS : 2653--1964
16.	सीएम/एल- 9052 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	दि मैजेस्टिक मैच इंडस्ट्रीज 1/210 ए०बी०सी० विश्वनाथम शिवकासी तमिलनाडु (कार्यालय 72, जबुलीकासी स्ट्रीट शिवकासी 626123 (तमिलनाडु)	दियासलाई की डिब्बियां-- IS : 2653--1964
17.	सीएम/एल- 9053 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	ब्लू पंक इंडस्ट्रीज 66/3 सी० आई० ई० सी० इस्टेट वधवां सिटी 363030 (कार्यालय : ब्लू पंक ट्रैडर्स 11, किल्न लेन, लेमिंग्टन रोड, बम्बई-7	वर्ग ई रोधन व 0.75 किवा० (1 हापा) वाली तीन फेजी प्रेरण मोटर IS : 325--1978
18.	सीएम/एल--9054 1980-10-10	80-10-16 81-10-15	81-10-15	मशीनएज प्रा० लि० नरोडा रोड अहमदाबाद 380025	निम्न साइजों की वर्ग ए रोधन वाली तीन फेजी प्रेरण मोटरें : 2.2 किवा (3 हा०पा०) 3.7 किव (5 हा० पा०) 5.6 किवा (7.5 हा० पा०) 7.5 किवा (15 हा० पा०) IS : 325--1978
19.	सीएम/एल--9055 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	मशीनएज प्रा० लि० नरोडा रोड अहमदाबाद-380025	कृषि उपयोगों के लिए उपकेन्द्री पम्पों के वास्ते, निम्न प्रकार की तीन फेजी क्विरेल केज प्रेरण मोटरें : वर्ग ई रोधन वाली 3.7 किवा (5 हा०पा०) एवं 2.2 किवा (3 हा० पा०) IS : 7538--1975
20.	सीएम/एल--9056 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	इंडोकेम, सी-2 ए० टाइप, शैड नं० 5 व 6 जी० आई०डी० सी० इंडस्ट्रियल इस्टेट वतवा-382445 जिला-- अहमदाबाद (गुजरात)	कारबेराइल धूलन चूर्ण--- IS: 7122-1973
21.	सीएम/एल- 9057 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	कल्पेश केबल इंडस्ट्रीज ए-1, इंडस्ट्रियल इस्टेट पोस्ट बॉक्स नं०-63, मालेगांव रोड धुलिया-424001 (महाराष्ट्र)	लड़दार एलुमिनियम चालक व जस्तीकृत इस्पात से प्रतिबलित एलुमिनियम चालक--- IS: 398 (भाग I व II)---1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. सी म/एल--9058 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	आर० सी० पुरी एंड संस एर्बी कैमल, 64 सी मोहम्मद अली रोड बम्बई-400003	अंग्रेजी टट्टियों के लिए प्लास्टिक सीटैव ढक्कन--टाइप ए० IS : 2548--1967
23. सीएम/एल—9059 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	भारत पल्वराइजिंग मिल्स प्लाट नं० IV, कामा इंडस्ट्रियल इस्टेट, वलमत रोड (निरलोन के नजदीक) गोरेगांव, बम्बई-400068 (कार्यालय : श्रीनिकेतन, 4, क्वीन्स रोड, बम्बई-400020)	मोनोक्रोटोफॉस जल में घुलनशील तेज पदार्थ (रिपैकिंग) IS : 8074—1976
24. सीएम/एल—9060 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	अशोक इंजीनियरिंग (बिहार) प्रा० लि०, महोसार, पो० आ० सोहसारी, नालन्दम जिला	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS: 226—1975
25. सीएम/एल—9061 1980-10-10	80-10-16	8110-15	अशोक इंजीनियरिंग (बिहार) प्रा० लि० महोसार, पो० आ० सोहसारी, नालन्दा जिला	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977—1975
26. सीएम/एल 9062 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	टेक्नीको (इंडिया) 3, बी० बी० गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-700012	फायर होज वितरण युग्मन शाखा पाइप व नोजल IS: 903—1975
27. सीएम/एल-9063 1980-10-10	80-10-01	81-09-30	एलमैक्स इंजीनियरिंग कं० ए-26/10, गली नं० 4, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 ड्यूटी पाइंट	कृषि प्रयोजनों के लिए साफ ठंडे ताजे पानी के लिए निम्न रेटिंग वाले मोनोसेट पम्प

क्र० सं०	पम्प साइज मिमी	मोटर कि०वा०	चक्कर प्रति मिनट	शीर्ष (मीटर)	निष्कासन लिटर प्रति मिनट	समग्र कुशलता	पम्प इनपुट किवा	टाइप	रोधन का वर्ग
1.	100×100	3.7	1440	12.5	1125	57	3.7 एल	100 डी 4 317	बी
2.	65×65	2.2	2850	17.5	430	51	2.7 एम	65 डी 2 2.2	बी
3.	65×65	3.7	1440	22.5	540	52	3.7 एम	65 डी 4 3.7	बी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. सीएम/एल-9064 1980-10-13	80-10-16	81-10-15	आरों स्टील इंडस्ट्रीज प्रा०लि० इंडस्ट्रियल इस्टेट पटना-800013 (कार्यालय : एक्जीबिशन रोड, पटना-800007)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS: 226–1975
29. सीएम/एल-9065 1980-10-13	81-10-01	81-09-30	फोर्ट ग्लास्टर इंडस्ट्रीज लि० (न्यू मिल) पोस्ट आफिस फोर्ट गलोस्टर 711310 जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) (कार्यालय : 21, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता-700001)	ए ट्विल जूट के बोरे— IS : 1943-1964

1	2	3	4	5	6
30.	सी एम/एल-9066 1980-10-13	80-11-01	81-10-31	दि एल्कली एंड कैमीकल्स कारपो० आफ इंडिया लि० (मैसर्स स्टर-लिंग पैस्टीसाइड्स के परिसर में) डी-3 डैवलेप्ड प्लाट इंडस्ट्रियल इस्टेट, थुंबाकुडी. तिरुचिरापल्लि-620015	जल परिक्षेपी तेज पाउडर जीरम की रीपैकिंग के लिये-- IS : 3901-1975
31.	सी एम/एल-9067 1980-10-14	80-11-01	81-10-31	वृन्दावन एलांय लि०, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया 1/फेज, तुमकर रोड, पीन्या बंगलौर-560058	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) ग्रेड एफई-410-0 IS : 1977-1975
32.	सी एम/एल-9068 1980-10-14	80-11-01	81-10-31	दि पंजाब डेरी डेवलेपमेंट कारपो० लि०, मिल्क प्लांट, बटाला रोड, बर्की, जिला अमृतसर (पंजाब)	बच्चों के लिये सूखा दूध आहार-- IS : 1547-1968
33.	सी एम/एल-9069 1980-10-14	80-11-04	81-10-31	दि पलानी अंडावर मिल्स लि० 236/1, ढल्ली रोड, उडामलपेटा-642126 (तमिलनाडु)	भूरा सूती धागा 80 एस कंघी किया, विशेष शंकु. धागा बी ग्रेड IS : 171-1973
34.	सी एम/एल-9070 1980-10-16	80-11-01	81-10-31	शरोफ इंडस्ट्रियल कैमीकल्स प्रा०लि० 3-10, जी०आई०डी०सी०एरिया वापी-396195	तकनीकी फिनाइल पारदीप एसीटेट IS : 2126-1973
35.	सी एम/एल-6071 1980-10-16	80-11-01	81-10-31	--वही--	मिथाक्सी इथायल पारदीप क्लोराइड IS: 2358-1963
36.	सी एम/एल-9072 1980-10-21	80-11-01	81-01-31	श्री गणेश स्टील रोलिंग मिल्स 14-ए, एन्नोर हाई रोड, मद्रास-600019	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी हुई विकृत इस्पात की छड़ें-- IS : 1786-1966
37.	सी एम/एल-9073 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	इंडीकेम, सी-2, एटाइप, शेड नं० 5-6, जी०आई०डी०सी० इस्टेट वतवा, अहमदाबाद-382445 गुजरात	मालाथियान पायसनीय सान्द्र-- IS: 2567-1978
38.	सी एम/एल-9074 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	कैप स्टील लि०, वाइटफील्ड रोड, माधवपुरा बंगलौर-560048	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी हुई विकृत इस्पात की छड़ें-- IS: 1786-1966
39.	सी एम/एल-9075 1980-10-21	80-11-01	83-10-31	शिमोगा स्टील लि०, के०आर०एस० रोड, मेटागल्लि. मैसूर-570016	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी हुई विकृत इस्पात की छड़ें-- IS: 1786-1966
40.	सी एम/एल-9076 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	शिमोगा स्टील लि०, के०आर०एस० रोड, मेटागल्लि मैसूर-570016	संरचना इस्पात (मानक किस्म)-- IS: 226-1975
41.	सी एम/एल-9077 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	शिमोगा स्टील्स लि०, के०आर०एस० रोड, मेटागल्लि, मैसूर-570016	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)-- IS: 1977-1975
42.	सी एम/एल-9078 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	फोर्ड केबल कंपनी (इंडिया) सी-51, मायापुरी फेज-II, नई दिल्ली-64	एलुमिनियम के चालकों वाले कवचदार व कवचरहित 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए पी वी सी रोधित (भारी कार्य के लिए) बिजली के केबल IS : 1554 (भाग I)—1976
43.	सी एम/एल-9079 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	यू०के० पेंट इंडस्ट्रीज सुलतानपुर गांव, महरौली-गुड़गांव रोड, नई दिल्ली-110030	आन्तरिक उपयोग के लिये प्लास्टिक पायस रंग रोगन -- IS: 5411 (भाग I)—1974

1	2	3	4	5	6
44.	सी एम/एल-9080 1980-10-24	80-11-01	81-10-31	सत्य व्यापार निर्यात प्रा०लि०, ए-127, रोड नं० 9, डी विश्वकर्म इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर-302013 (कार्यालय : जी-9/सी, कबीर मार्ग, मनी पार्क, जयपुर-302006	एलुमिनियम के लड़दार व जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एलुमिनियम के चालक-- IS: 398 (भाग 1 व 2)--1976
45.	सी एम/एल-9081 1980-10-24	80-01-01	81-10-31	भारत इलैक्ट्रीकल्स, जी टी रोड, छक्की पो०आ० कंदरोड़ी जिला कांगड़ा (हि०प्र०)	एलुमिनियम के लड़दार व जस्तीकृत प्रबलित एलुमिनियम के चालक-- IS: 398 (भाग 1 व 2)--1976
46.	सी एम/एल-9082 1980-10-24	80-01-01	81-10-31	न्यू स्टील वर्ड इंडस्ट्रीज, डब्ल्यू जैड-26-ए/2 गणेश नगर, नई दिल्ली-110018	औद्योगिक सुरक्षा के लिए हेलमेट मध्यम साइज, IS : 2925--1975
47.	सी एम/एल-9083 1980-10-27	80-11-16	81-11-15	दी भारत स्टील रोलिंग मिल्स 94/5 मंकरी मेन रोड, नेथीमेडु सलेम-636002 (तमिलनाडु)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)— IS : 1977-1975
48.	सी एम/एल-9084 1980-10-27	80-11-16	81-11-15	वाडीलाल डेरी फोजन फूड इंडस्ट्रीज, दूधेश्वर रोड जुपीटर मिल्स के पीछे अहमदाबाद-380001 (गुजरात)	केवल मादी आइसक्रीम-- IS: 2802-1964
49.	सी एम/एल-9085 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	नर्मदा इंडस्ट्रीज 6/1 इंडस्ट्रियल इस्टेट गोविन्दपुरा, भोपाल	बाहर व निम्न तापक्रमों पर प्रयुक्त होने वाले केबलों को छोड़कर एलुमिनियम चालकों वाले पी वी सी रोधित केबल--(1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए)-- IS : 694-1977
50.	सी एम/एल-9086 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	मेट्रो पेन्ट इंडस्ट्रीज बी-91-92, फेज 1, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली-110064 (कार्यालय : 260, कमला मार्किट, नई दिल्ली)	सीसा रहित, अम्ल एल्कली, जल व ताप सह्य सामान्य प्रयोजनों के लिये, बुश से लगने वाला, 'बिट्यूमिनी, काला तैयार मिश्रित रंग रोगन केवल टाइप-2— IS : 158-1968
51.	सी एम/एल-9087 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	भारत एग्रिको 66, इडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची (बिहार)	निम्न प्रकार के अकठोरीकृत फलक वाले फावड़े वैस्ट इंडिया फावड़ा 1.6 किलो, कृषि फावड़ा 1.8 किलो व ईस्ट इंडिया फावड़ा 1.8 किलो. IS : 1759-1961
52.	सी एम/एल-9088 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	किंग केमीकल्स 19/2 सातवां मील मैसूर रोड, बंगलौर 560039 कर्नाटक	पैराफिन मोम, टाइप-III— IS : 4654-1974
53.	सी एम/एल-9089 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	दी अम्बाला रोलिंग मिल्स एड फाउंड्री वर्क्स, नं० 177, एच एंड आई, इंडस्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़-160002	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) केवल 32 मिमी व्यास तक व बराबर साइज के सेक्शन IS : 1977-1975

1	2	3	4	5	6
54.	सी एम/एल-9090 1980-10-26	80-11-16	81-11-15	दी अम्बाला रोमिंग मिल्स एण्ड फाउंड्री वर्क्स, नं० 177, एच एण्ड आई, इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़-160002	कंक्रीट प्रबलन के लिये ठंडी मरोड़ी हुई विकृत इस्पात की छड़ें साइज 32 मिमी सांकेतिक व्यास IS : 1786-1966
55.	सी एम/एल-9091 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	,,	संरचना इस्पात (मानक किस्म) केवल 32 मिमी व्यास तक के बराबर साइज के सेक्शन IS : 226-1975
56.	सी एम/एल-9092 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	इलैक्ट्रीकल स्विच गियर्स प्रा०लि० बी-30, फेज 5, इंडस्ट्रीकलां इंडस्ट्रियल फोकल पाइंट लुधियाना (कार्यालय : नकोदर रोड, जालन्धर)	लघु एयर सर्किट ब्रेकर, टाइप एल-16 240/415 वोल्ट, 16 एम्पीयर, एच वर्ग का रोधन व एम-9 वर्ग IS : 8828-1978
57.	सी एम/एल-9023 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया भरतपुर-321001 राजस्थान	शिरेपरि प्रेषण प्रयोजनों के लिए जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चालकों के कोर के लिये इस्पात की तार— IS : 398 (भाग II) 1976
58.	सी एम/एल-9094 1980-10-28	80-11-01	81-10-31	नार्थलैण्ड रबड़ मिल्स 20वां मील, जी टी रोड, राई, जिला सोनीपत (हरियाणा)	सतही घर्षण वाली रबड़ की संचारण बैल्टिंग टाइप-34 (सख्त), 970 ग्राम (मीटर) 2 IS : 1370-1976
59.	सी एम/एल-9095 1980-10-28	80-11-01	81-10-31	पापुलर प्लास्टिक 11, गोल्डन पार्क, रोहतक रोड, दिल्ली-110035	स्कूटर व मोटर साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट साइज-580 मिमी— IS : 4151-1976
60.	सी एम/एल-9096 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	गंगा स्टील रोलिंग मिल कुम्हड़ी, जिला दुर्ग, (मध्य प्रदेश)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी हुई विकृत इस्पात की छड़ें IS : 1786-1966
61.	सी एम/एल-9097 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	रयालसीमा केबल कं० ई-7 से ई-10 इंडस्ट्रियल एस्टेट कुड्डप्पा (आंध्र प्रदेश) (कार्यालय : 6 नं०, कमर्शियल काम्पलेक्स कुड्डप्पा 516001)	शिरोपरि प्रेषण कार्यों के लिए एलुमिनियम के लड़दार चालक व जस्तीकृत इस्पात के प्रबलित एलुमिनियम चालक— IS : 398 (भाग I व II)-1976
62.	सी एम/एल-9098 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	बेल अर्थमूविंग प्रोडक्टस प्रा०लि० प्लाट नं० 4 ए-III मेन रोड इंडस्ट्रियल एस्टेट अम्बातूर मद्रास-58 (कार्यालय : 4, थ्यार साहिब स्ट्रीट मद्रास-600002)	ध्रार लोहे से ढले हुए पदार्थ ग्रेड एफ जी 220 व एफ जी 260— IS : 210-1978
63.	सी एम/एल-9099 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	श्री विजय दुर्गा पल्वराइजिंग मिल्स, अवम्मभावी, सिरुगुप्पा रोड, बेलाड़ी 583101 (कर्नाटक)	2 % मिथाइल पैराथियान धूलन पाउडर— IS : 8960-1978
64.	सी एम/एल-9100 1980-10-30	90-11-01	81-10-31	नार्दर्न मिनरल्स प्रा०लि०, दौलताबाद-रोड, गुड़गांव (हरियाणा)	डी डी टी जल परिक्षेपी नेज पाउडर IS : 565-1975
65.	सी एम/एल-9101 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	,,	एन्डोसल्फान पायसनीय सांद्र IS : 4323-1967

1	2	3	4	4	6
66.	सी एम/एल-9102 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	नार्दर्न मिनरल्स प्रा० लि०, दौलताबाद रोड़, गुड़गांव (हरियाणा)	डी डी टी पायसनीय सांद्र— IS : 633–1975
67.	सी एम/एल-9103 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	,,	मैलाथियान पायसनीय सान्द्र— IS : 2567–1978
68.	सी एम/एल-9104 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	अशोक इंजीनियरिंग (बिहार) प्रा० लि०, सहोखर, पो०आ० मोहसराय नालन्दा (बिहार)	कंक्रीट प्रबलन के लिए ठंडी मरोड़ी विकृत इस्पात की छड़ें— IS : 1786–1966
69.	सी एम/एल-9105 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	पलाई मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, नं० 4214, पलाई केरल	निम्न प्रकार का कच्चा प्राकृतिक रबड़, आईएसएनआर 10, आईएसएनआर 20 व आईएसएनआर-50 IS : 4588–1977
70.	सी एम/एल-9106 1980-10-30	80-10-16	81-10-15	टैस्टिक्स मिल्स लि० (कोयर एंड फैल्ट डिवीजन) 6/2 जी टी रोड, कोन्नार (कार्यालय : 14 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001)	गद्दों के लिये रबड़ चढ़ी हुई नारियल जटा की चद्दर, मध्यम ग्रेड— IS : 8391–1977
71.	सी एम/एल-9107 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	निर्मल लैमीनेटर्स 220, नस्करपाड़ा रोड (घुसूरी) हावड़ा-711107 (प० बंगाल)	परतदार जूट के बोरे— IS : 7406 (भाग 1)–1974
72.	सी एम/एल-9108 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	राजस्थान कोओपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० जोधपुर यूनिट 35 हैवी इंडस्ट्रियल एरिया जोधपुर-342003 (राजस्थान)	मखनिया दूध का पाउडर— IS : 1165–1975
73.	सी एम/एल-9109 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	हिन्दुस्तान पल्वराइजिंग मिल्स, 12 व 13, इंडस्ट्रियल एरिया गली-9 समेपुर, दिल्ली-110042 (कार्यालय : 278, कटरा पेरान, तिलक बाजार, दिल्ली-110006	डीडीटी धूलन पाउडर— IS : 564–1975
74.	सी एम/एल-9110 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	गुजरात पेस्टीकैम इंडस्ट्रीज, 111, नन्देसरी इंडस्ट्रियल इस्टेट नन्देसेरी 391340 जिला बड़ौदा, गुजरात	डीडीटी पायसनीय सांद्र IS : 633–1975
75.	सी एम/एल-9111 1980-11-31	80-11-16	81-11-15	गुजरात पेस्टीकैम इंडस्ट्रीज, 111, नन्देसेरी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नन्देसरी–391340 जिला बड़ौदा (गुजरात)	फैनीट्रोथीयान पायसनीय सान्द्र— IS : 5281–1969
76.	सी एम/एल-9112 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	प्रेम प्राडक्ट्स, दर्शन इंडस्ट्रियल इस्टेट, अनिल स्टार्च मिल के पीछे, अहमदाबाद-380025 (गुजरात)	केवल ग्लुकोज किस्म के बिस्कुट— IS : 1011–1968
77.	सी एम/एल-9113 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	हरिगंगा एलाय व स्टील लि०, 39, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, हींगना, नागपुर	संरचना इस्पात (मानक किस्म) में बेल्लन के लिए ढले हुए बिलेट व इंगट— IS : 6914–1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
78.	सी एम/एल-9114 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	हरिगंगा एलाय व स्टील लि०, 39, एमआइडीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, हींगना, नागपुर	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) में वेल्डन के लिए ढले हुए बिलेट व इंगट— IS : 6915–1978
79.	सी एम/एल-9115 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	भूमि सुधार केमिकल इंडस्ट्रीज, 7-ए, फोकल पाइंट इंडस्ट्रियल एरिया, मंगरूर-148001 (पंजाब)	कृषि ग्रेड का जिंक सल्फेट— IS : 8249–1976
80.	सी एम/एल-9116 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	लोटस पेस्टीसाइड्स मदरी-306702 जिला पाली (राजस्थान)	मालाथिया पायसनीय सान्द्र— IS : 2567–1978
81.	सी एम/एल-9117 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	हिन्दुस्तान, पल्वराइजिंग मिल्स, 12 व 13, इंडस्ट्रीयल एरिया, गली नं० 9 सामेपुर, दिल्ली-110042, इनका कार्यालय 278, कटरा पेड़ान, तिलक बाजार, दिल्ली-110006	बी एच सी (एच सी एच) धूलन पाउडर— IS : 561—1978
82.	सी एम/एल-8118 1980-10-31	80-11-01	81-10-31	स्पेन इंडस्ट्रीज, 1, राजेन्द्र नगर, पो० आ० मोहन नगर, गाजियाबाद (यू० पी०) इनका कार्यालय 2880 सिरकीवालान हौजकाजी, दिल्ली-110006	ई आर डब्ल्यू सादे सिरों वाली काली, हल्की श्रेणी की संरचना प्रयोजनों के लिए इस्पात की तलियां, ग्रेड वाई एस टी 210, साइज 50 मिमी से ज्यादा से लेकर 100 मिमी एन बी तक— IS : 1161–1979
83.	सी एम/एल-9119 1980-10-31	80-11-01	81-10-31	साहनी मंस मैन्यु० क०, 3482, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002	हथकरघे की सूती अवशोषी जाली— IS : 758–1975
84.	सी एम/एल-9120 1980-10-31	80-11-01	81-10-31	जौहर सेल्स (इंडिया) 73-ए, रशीद मारकेट एक्सटेन्शन, भगतसिंह रोड, खुरेजी खास, दिल्ली-110057	हथकरघे की सूती अवशोषी जाली— IS : 758–1975
85.	सी एम/एल-9121 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	उत्तर भारत मेटल प्राडक्ट्स, 11-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, यमुनानगर-135001 (हरियाणा)	क्रीम ग्रेड का जिंक सल्फेट— IS : 8249–1976
86.	सी एम/एल-9122 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	बीर इंजीनियरिंग वर्क्स, जी० टी० रोड, मकसूदन, जलन्धर-144004	गन मेटल के श्रेणी 1 वाले, गेट व ग्लोब वाल्व, साइज 15 से लेकर 50 मिमी तक— IS : 778-1971

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
87.	सी एम/एल-9123 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	पारीख केबल्स प्रा० लि०, ए-1/71, जी० आई० डी० सी० इस्टेट, अंकलेश्वर-393002	बाह्य प्रयोग के लिए व निम्न तापक्रमों पर प्रयुक्त होने वाले केबलों को छोड़कर 1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए तांबे व एल्यूमिनियम के चालकों वाले एक कोर के पी वी सी रोधित (कवच रहित) केबल— IS : 694—1977
88.	सी एम/एल-9124 1980-10-31	80-11-16	81-11-15		1100 वोल्ट तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए तांबे व एल्यूमिनियम के चालकों वाले कवचदार व कवचरहित (भारी कार्य के लिए) पी वी सी रोधित केबल— IS : 1554 (भाग 1)—1976
89.	सी एम/एल-9125 1080-10-31	80-11-16	81-11-15	यूनियन पेस्टोमाइड्स, श्रीराम नगर, विदिशा-464001 (मध्य प्रदेश)	मालाथियान पायसनीय सान्द्र— IS : 2567—1978

[सं० सी एम डी /13:11]

(Department of Civil Supplies)

(INDIAN STANDARDS INSTITUTION)

New Delhi, the 17th November, 1983

S.O. 4613.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended from time time, the Indian Standards Institution, hereby, notified that eightynine licences, particulars of which are given in the following schedule, have been granted during the month of October 1980 authorizing the licensees to use the Standard Marks :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Period of Validity From	To	Name and Address of the Licensee	Article/Process covered by the Licensee and the Relevant IS : Design.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L-9037 1980-10-06	80-10-16	81-10-15	Indian Traders Pvt. Ltd., Najafgarh Road, New Delhi-110015	PUC insulated (heavy duty) electric cablees for working voltages upto and including 1100 volts armoured and unarmoured with copper and aluminium conductors— IS : 1554 (Part I)—1976
2.	CM/L-9038 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	Sardar Rolling Mills, New Colony, Mandsaur-458001 (M.P.)	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
3.	CM/L-9039 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	Gem Forging & Engineering Industries, 95-A, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700073 (Office : 31, Barbourne Road, Calcutta-700001)	Forged CTC segments— IS : 8748—1978
4.	CM/L-9040 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	Bombay Protein Mfg. Co., Bhalej Road, Anand-388001 (Gujarat State)	Aluminium standared conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced— IS : 398 (Part I & II)—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	CM/L-9041 1980-10-07	80-10-16	81-10-15	Mahabir Industries, 1, Barauni Industrial Area, P.O. Tilrath, Distt. Begusarai (Bihar)	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced— IS : 398 (Part I & II)—1976
6.	CM/L-9042 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Jodhpur Cables & Conductors Pvt. Ltd., 17 Light Industrial Area, Jodhpur	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced. IS : 398 (Part I & II)—1976
7.	CM/L-9043 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Gujarat Agro Industries Corporation Ltd., Near Chest Disease Hospital, Karanj Baug, Prantij Road, Naroda, Ahmedabad-382330 (Gujarat) [Office : Khet Udyog Bhavan, Opp. High Court, Navrangpura, Ahmedabad-380014 (Gujarat)]	Carbaryl DP— IS : 7122—1973
8.	CM/L-9044 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Tarapur Chemicals & Pesticides, Plot No. E-47, Tarapur Industrial Area, Boisar-401501 Distt. Thane (Maharashtra)	DDT WDPC— IS : 565—1975
9.	CM/L-9045 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Arunodaya Metal Industries Pvt. Ltd., Survey No. 14, Hissa No. 1, Village Pinguli, P.O. & Tal Kundal, Dist. Ratnagiri (Maharashtra)	Wrought aluminium utensils grade 19000— IS : 1660 (Part I & IV) —1967
0.	CM/L-9046 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	National Agro Chemicals, C-2 Industrial Area, Patna-800013 (Bihar)	Aldrin EC— IS : 1307—1973
11.	CM/L-9047 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Pesticides India, Udaisagar Road, Udaipur-313001 (Rajasthan)	Carbaryl WDPC, aerial spray grade only— IS : 7121—1973
12.	CM/L-9048 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Malhotra Steel Corporation, Malhotra Road, Odhav, Ahmedabad-382410	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement Size : upto 25mm nominal dia— IS : 1786—1966
13.	CM/L-9049 1980-10-10	80-09-16	81-09-15	Machineage Pvt. Ltd., Naroda Road, Ahmedabad -380025 (Gujarat)	Monoset pumps for clear, cold, fresh water for agricultural purposes of the following sizes— Size — Motor — Speed 65x50mm — 3.7, Class 'E' — 2880 RPM 62x50mm — 5.5kW Class 'E' 2880 RPM Type/Model — Duty Point Es — At 18m head, discharges 12.81ps and overall efficiency 47% Type/Model — Duty/Point ES — At 35.0m head, discharge 9.01 ps and overall efficiency 44% IS : 6595—1972 & IS : 7538—1975
14.	CM/L-9050 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Vijayakumar Sankar Match Industries, 146 & 147 Mundaganadar Street, Sivakasi (Tamil Nadu) (Off : 72 Javulikadai Street, Sbivakasi-626123]	Safety matches in boxes— IS : 2653—1964

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. CM/L-9051 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Vijayalakshmi Match Industries, 209/1C-4, Viswanatham Village, Sivakasi-626123 (Tamil Nadu) [Office : 72 Javalikadai Street, Sivakasi-626123 (Tamil Nadu)]	Safety matches in boxes IS : 2653—1964
16. CM/L-9052 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	The Majestic Match Industries, 1/210, A.B.C. Viswanatham Village, Sivakasi (Tamil Nadu) [Office : 72 Javulikadai Street, Sivakasi-626123 (Tamil Nadu)]	Safety matches in boxes— IS : 2653—1964
17. CM/L-9053 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Blue Punk Industries, 66/3, C.I.D.C. Estate, Wadhwan City-363030 (Office : Blue Punk Traders, 11 Kiln Lane, Lamington Road, Bombay-7)	Three phase induction motors 0.75 kW (1HP) with Class 'E' insulation— IS : 325—1978
18. CM/L-9054 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Machineage Pvt Ltd., Naroda Road, Ahmedabad-380025	Three phase induction motors 2.2 kW (3HP); 3.7 kW (5HP); 5.6 kW(7.5HP); 7.5 kW(10HP) with Class 'A' insulation— IS : 325—1978
CM/L-9055 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	-do-	Three phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application 3.7 kW (5HP) and 2.2 kW (3HP) with Class 'E' insulation— IS : 7538—1975
20. CM/L-9056 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Indichem, C-2 A Type, Shed No. 5 & 6, G.I.D.C. Industrial Estate, Vatva-382445 Dist. Ahmedabad (Gujarat).	Carbaryl DP— IS : 7122-1973
21. CM/L-9057 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Kalpesh Cable Inds., A-1, Industrial Estate, P.B. No. 63, Malegaon Road, Dhullia-424001 (M.S.)	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced— IS : 398(Part I &II)—1976
22. CM/L-9058 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	R.C. Puri & Sons, Eby Castle, 64-C, Mohd. Ali Road, Bombay-400003	Plastic water-closet seats and covers Typ A— IS : 2548—1967
23. CM/L-9059 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Bharat Pulverising Mills, Plot No. VI, Cama Industrial Estate, Balbhat Road, (Near Nirlon), Goregaon Bombay-400068 (Maharashtra) (Office : Shriniketan, 14 Queens Road, Bombay-400020)	Monocrotophos WSC (Repacking) — IS : 8074—1976
24. CM/L-9060 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Ashok Engineering (Bihar) Pvt. Ltd., Sahokhar, P.O. Sohsari, Nalanda Distt.	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
25. CM/L-9061 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	-do-	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
26. CM/L-9062 1980-10-10	80-10-16	81-10-15	Technico (India), 3 B.B. Ganguli Street, Calcutta-700012	Fire those delivery couplings branch pipe, and nozzle— IS : 903-1975
27. CM/L-9063 1980-10-10	80-10-01	81-09-30	Elmex Engineering Co., A-26/0, Gali No. 4, Anand Parbat Industrial Area, New Rohtak Road, New Delhi-110005	Monoset pumps for clear, cold fresh water for agricultural purposes of the following ratings :

Sl. No.	Size of pump mm	Motor —KW	Duty Point			Overall Efficiency	Pump input KW	Type	Class of insulation
			Speed RPM	Head M	Discharge LPM				
1.	100×100	3.7	1440	12.5	1125	57	3.7	L 100D4 3.7	B
2.	65×65	2.2	2850	17.5	430	51	2.7	M 65D2—2.2	B
3.	65×65	3.7	1440	22.5	540	52	3.7	M 65D4—3.7	B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	CM/L-9064 1980-10-13	80-10-16	81-10-15	Aaron Steel Industries Pvt Ltd., Industrial Estate, Panta-800013 (Office : Exhibition Road, Patna-800001)	Structural steel (standard quality)— IS : 226 —1975
29.	CM/L-9065 1980-10-13	80-10-01	81-09-30	Fort Gloster Industries Ltd., (New Mill), P.O. Fort Gloster-711310 Distt. Howrah (West Bengal) (Office : 21 Strand Road, Calcutta-700001).	A-twill jute bags— IS : 1943 —1964
30.	CM/L-9066 1980-10-13	80-11-01	81-10-31	The Alkali and Chemical Corporation of India Ltd., Under the premises of M/s. Sterling Pesticides, D-3, Develop Plots, Industrial Estate, Thuvakudy, Tiruchirapalli-620015	Repacking of ziram WDPC— IS : 3901 —1975
31.	CM/L-9067 1980-10-14	80-11-01	81-10-31	Brindavan Alloys Ltd., Peenya Industrial Area, IV Phase, Off Tumkur Road, Peenya, Bangalore-560058	Structural steel (ordinary quality)— Grade Fe 410-0 IS : 1977—1975
32.	CM/L-9068 1980-10-14	80-11-01	81-10-31	The Punjab Dairy Development Corpn. Ltd., Milk Plant, Batala Road, Verka, Distt. Amritsar (Punjab)	Infant milk foods— IS : 1547 —1968
33.	CM/L-9069 1980-10-14	80-11-01	81-10-31	The Palani Andavar Mills Ltd., 236/1, Dhally Road, Udamalpet-642126 (Tamil Nadu).	Grey cotton yarn, 80s combed special cone yarn-B-Grade — IS : 171— 1973
34.	CM/L-9070 1980-10-16	80-11-01	81-10-31	Shroffs Industrial Chemicals Pvt Ltd., 3-10, G.I.D.C. Area, Vapi-396195 (Gujarat)	Phenyl mercury acetate, technical— IS : 2126 1973
35.	CM/L-9071 1980-10-16	80-11-01	81-10-31	-do-	Methoxy ethyl mercuric chloride— IS : 2358—1963
36.	CM/L-9072 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	Shree Ganesh Steel Rolling Mill, 14-A. Ennore High Road, Madras-600019	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement IS : 1786—1966
37.	CM/L-9073 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	Indichem, C-2, A Type, Shed No. 5-6 G.I.D.C. Estate, Vatva; Ahmedabad-382445 (Gujarat).	Malathion EC— IS : 2567— 1978
38.	CM/L-9074 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	Kap Steel Ltd., Whitefield Road, Mahadavpura Post, Bangalore-560048	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1966
39.	CM/L-9075 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	Shimoga Steels Ltd., K.R.S. Road, Metagally, Mysore-570016	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1966
40.	CM/L-9076 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	Shimoga Steels Ltd., K.R.S. Road, Metagally, Mysore-570016	Structural steel (standard quality) IS : 226— 1975
41.	CM/L-9077 1980-10-21	80-11-01		81-10-31	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
42.	CM/L-9078 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	Ford Cable Company (India), C-51, Mayapuri, Phase-II, New Delhi, 110064	PVC insulated (heavy duty) electric cables for working voltages upto and including 1100 volts, armoured and unarmoured with aluminium conductor only:— IS : 1554 (Part I) —1976
43.	CM/L-9079 1980-10-21	80-11-01	81-10-31	U.K. Paint Industries, Village Sultanpur, Mehrauli-Gurgaon Road, New Delhi-110030	Plastic emulsion paint, for interior use— IS : 5411(Part I)—1974
44.	CM/L-9080 1980-10-24	80-11-01	81-10-31	Satya Vyapar Niryat Pvt Ltd., A-127, Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013 (Office : G-9/C, Kabir Marg, Bani Park, Jaipur-302006)	Aljuminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced IS : 398(Part I &II)—1976

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45. CM/L-9081 1980-10-24	80-11-01	81-10-31	Bharat Electricals, G.T. Road, Chhanni, P.O. Kandori, Distt. Kangra (H.P.)	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanizded steel reinforced— IS : 398(Part I & II)—1976
46. CM/L-9082 1980-10-24	80-11-01	81-10-31	New Steel Bird Industries, WZ-26-A/2, Ganesh Nagar, New Delhi-110018	Industrial Safety helmets—Medium size IS : 2925—1975
47. CM/L-9083 1980-10-27	80-11-16	81-11-15	The Bharath Steel Rolling Mills, 94/5, Sankari Main Road, Nethimedu Salem-636002, (Tamil Nadu)	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
48. CM/L-9084 1980-10-27	80-11-16	81-11-15	Vadilal Dairy Frozen Food Industries, Dudheshwar Road, Behind Jupitor Mills Ahmedabad-380001 (Gujarat)	Plain ice-cream only— IS : 2802—1964
49. CM/L-9085 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	Narmada Industries, 6/1, Industrial, Estate Govindpura, Bhopal.	PVC insulated cables with aluminium conductors for working voltage upto and including 1100 Volts excluding cables for outdoor use and low temperature applications— IS-694-1977
50. CM/L-9086 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	Metro Paint Industries, B-91-92, Phase-I, Mayapuri Industrial Area, New Delhi-110064 (Office : 260, Kamla Market, New Delhi.)	Ready mixed paint brushing bituminous black, lead-free acid alkali water and heat resisting for general purposes Type-2 only— IS : 158—1968
51. CM/L-9087 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	Bharat Agrico., 66, Industrial Area, Kokar, Ranchi (Bihar)	Porwah, blades only of unhardened quality of the following types : West India Powrah 1.6 kg, Agri Powrah 1.8 kg and East India Powrah 1.8 kg— IS : 1759—1961
52. CM/L-9088 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	King Chemicals, 19/2, 7th Mile, Mysore Road, Bangalore-560039 (Karnataka)	Paraffin wax, type 3— IS : 4654—1974
53. CM/L-9089 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	The Ambala Rolling Mills & Foundry Works, No. 177, H & I, Industrial Area, Chandigarh-160002	Structural steel (ordinary quality) Size: upto & including 32mm dia or equivalent section— IS : 1977—1975
54. CM/L-9090 1980-10-28	80-11-16	81-11-16	-do-	Cold twisted deformed steel bars for concerete reinforcement Size: upto and including 32 mm (Nominal dia)— IS : 1786—1966
55. CM/L-9091 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	-do-	Structural steel (standard quality) Size : upto & including 32 mm dia or equivalent section— IS : 226—1975
56. CM/L-9092 1980-10-28	80-11-16	81-11-15	Electrical Switchgears (P) Ltd., B-30, Phase V, Dhandari Kalan, Industrial Focal Point, Ludhiana (Office : Nakodar Road Jullundur).	Miniature air-circuit breaker, type L-16, 240/415 V, 16A Class of insulation 'H' M-9 category— IS : 8828—1978
57. CM/L-9093 1980-10-28	80-11-01	81-10-31	General Engineering Works, Industrial Area, Bhartapur-321001 (Rajasthan)	Steel wire for the core of galvanized steel reinforced aluminium conductors for overhead transmission prposes— IS : 398 (Part II)—1976
58. CM/L-9094 1980-10-28	80-11-01	81-10-31	Northland Rubber Mills, 20th Mileston, G.T. Road, Rai, Distt. Sonepat (Haryana)	Friction surface rubber transmission belting; type-34 (Hard); 970g/m2— IS : 1370—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59.	CM/L-9095 1980-10-28	80-11-01	81-10-31	Popular Plastics, 11, Golden Park, Rohtak Road, Delhi-110035	Protective helmets for scooter and motor-cycle riders; Size—580 mm— IS : 4151—1976
60.	CM/L-9096 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	Ganga Steel Rolling Mill, Kumhari, Distt. Durg (M.P.)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1966
61.	CM/L-9097 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	Rayalaseema Cable Corpn., E-7 to E-10, Industrial Estate, Cuddapah, (A.P.) (Office : No. 6, Commercial Complex, Cuddaph-516001)	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes— IS : 398 (Part I & II)—1976
62.	CM/L-9098 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	Vel Earthmoving Products Pvt. Ltd., Plot No. 4A, III, Main Road, Industrial Estate, Ambattur, Madras-600058 (Office : 4 Thayar Sahib Street, Mardras-600002)	Gray iron castings Grade : FG 220 and FG 260— IS : 210—1978
63.	CM/L-9099 1980-10-29	80-11-16	81-11-15	Sri Vijayadurga Pulverising Mills, Avammabhavi, Siruguppa Road, Bellary-583101 (Karnataka)	Methyl parathion DP 2 per cent— IS : 8960—1978
64.	CM/L-9100 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	Northern Minerals (P) Ltd., Daulatabad Road, Gurgaon (Haryana)	DDT water dispersible powder concentrates— IS : 565—1975
65.	CM/L-9101 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	-do-	Endosulfan EC— IS : 4323—1967
66.	CM/L-9102 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	-do-	DDT emulsifiable concentrates— IS : 633—1975
67.	CM/L-9103 1980-10-30	80-11-01	81-10-31	-do-	Malathion EC— IS : 2567—1978
68.	CM/L-9104 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	Ashok Enginerring (Bihar) Pvt. Ltd., Sahokhar, P.O. Sohsarai Nalanda (Bihar)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement— IS : 1786—1966
69.	CM/L-9105 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	Palai Marketing Co-operative Society Ltd., No. 4214, Palai-Kerala.	Rubber raw natural INSR 10; INSR 20; and INSR 50 — IS : 4588—1977
70.	CM/L-9106 1980-10-30	80-10-16	81-10-15	Hastings Mills Ltd., (Coir & Felt Division) 6/2 G.T. Road, Konnagar (Office : 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001)	Rubberized coir sheets for cushioning, 'medium' grade— IS : 8391—1977
71.	CM/L-9107 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	Nirmal Laminators, 220 Naskarpara Road, (Ghusuri) Howrah-711107 (West Bengal)	Laminated jute bags— IS : 7406 (Part I)—1974
72.	CM/L-9108 1980-10-30	80-11-16	81-11-15	Rajasthan Co-op. Dairy Federation Ltd., Jodhpur Unit 35, Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003 (Rajasthan)	Skim milk powder — IS : 1165- 1975
73.	CM/L-9109 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Hindustan Pulverising Mills, 12 & 13, Industrial Area, Street No. 9, Samepur, Delhi-110042 (Office : 278, Katra Paran, Tilak Bazar, Delhi-110006)	DDT dusting powder— IS : 564—1975
74.	CM/L-9110 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Gujarat Pestichem Inds., 111, Nandesari Ind istrial Estate, Nandesari-391340, Dist. Baroda (Gujarat)	DDT EC - IS : 633—1975
75.	CM/L-9111 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Gujarat Pestichem Inds., 111, Nandesari Industrial Estate, Nandesari-391340 Dist. Baroda (Gujarat)	Fenitrothion EC— IS : 5281—1969

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
76.	CM/L-9112 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Prem Products, Darshan Industrial Estate Behind Anil Starch Mill, Ahmedabad-380025 (Gujarat)	Biscuit of glucose variety only— IS : 1011—1968
77.	CM/L-9113 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Hariganga Alloys & Steel Ltd., 39, MIDC Industrial Estate, Hingna, Nagpur	Cast billet ingots for rolling into structural steel (standard quality)— IS . 6914—1978
78.	CM/L-9114 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	-do-	Cast billet ingots for rolling into structural steel (rodinary quality)— IS : 6915—1978
79.	CM/L-9115 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Bhoomi Sudhar Chemical Industries, 7 A, Focal Point Industrial Area, Sangrur-148001 (Punjab)	Zinc sulphate, agricultural grade— IS : 8249—1976
80.	CM/L-9116 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Lotus Pesticides, Sadri-306702, Dist. Pali (Rajasthan)	Malathion EC— IS : 2567– 1978
81.	CM/L-9117 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Hindustan Pulverising Mills, 12 & 13 Industrial Area, Street No. 9, Samepur, Delhi-110042 (Office : 278, Katra Peran, Tilka Bazar Delhi-110006)	BHC (HCH) dusting powders— IS : 561—1978
82.	CM/L-9118 1980-10-31	80-11-01	81-10-31	Span Industries, 1, Rajendra Nagar, P.O. Mohan Nagar, Ghaziabad (U.P.) (Office : 2880, Sirkiwalan, Hauz Quazi, Delhi-110006)	Steel tubes for structural purposes, ERW, plain end, black Clas-light; grade-Yst 210; Size-from above 50mm NB upto and including 100mm NB— IS : 1161—1979
83.	CM/L-9119 1980-10-31	80-11-01	81-10-31	Sahnisons Manufacturing Company, 3482, Netaji Subhas Marg, New Delhi-110002	Handloom cotton gauze absorbent IS : 758—1975
84.	CM/L-9120 1980-10-31	80-11-01	81-10-31	Johar Sales (India), 73-A, Rashid Market Extension Bhagat Singh Road, Khurezi Khas, Delhi-110051	Handloom cotton gauze absorbent— IS :758—1975]
85.	CM/L-9121 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Uttar Bharat Metal Products, 11-E, Industrial Area, Yamunanagar-135001 (Haryana)	Zinc sulphate, agricultural grade— IS : 8249—1976
86.	CM/L-9122 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Bir Engineering Works, G.T. Road, Maqsudan, Jullundur-144004	G.M. Gate and globe valves-Class I 15 to 50mm size— IS : 778—1971
87.	CM/L-9123 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Parekh Cables Pvt. Ltd., A-1/71, G.I.D.C. Estate, Ankleshwar (393002)	Single core PVC insulated (unsheathed) cables with aluminium and copper conductors for working voltages upto and including 1100 volts excluding cables for outdoor use/low temperature applications— IS : 694—1977
88.	CM/L-9124 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	-do-	PVC insulated and sheathed armoured and unarmoured (heavy duty) cables with aluminium and copper conductors for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Part I)—1976
89.	CM/L-9125 1980-10-31	80-11-16	81-11-15	Union Pesticides, Shri Ram Nagar, Vidisha-464001 (M.P.)	Malathion EC— IS : 2567—1978

[No. CMD/13 : 11]

का० आ० 4614.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उप-विनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 82 लाइसेंस जिनके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारियों को मानक सम्बन्धी मुहर लगाने का अधिकार माह सितम्बर 1980 से स्वीकृत किया गया है :

अनुसूची

क्रम सं०	लाइसेंस संख्या सी एम/एल	वैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और तत्सम्बन्धी IS : पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सी एम/एल-8955 1980-09-03	80-08-16	81-08-15	हुकमचन्द जूट मिल्ज लि०, डाकखाना हाजी नगर- 743135 नाइहाटी, जिला 24 परगना (बंगाल) कार्यालय : 15 इंडिया ऐक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700001	अनाज के पटसन के बोरे और अनाज के पटसन के बोरे का कपड़ा— IS : 2975–1964 और IS : 3750–1966
2.	सी एम/एल-8636 1980 08-03	80-08-16	81-08-15	,,	एलटि्वल बोरे और एलटि्वल बोरे का कपड़ा— IS : 3794–1966 और IS : 3668–1966
3.	सी एम/एल-8957 1980-09-03	80-08-16	91-08-15	हुकम चन्द्र जूट मिल्ज लि०, डाकखाना हाजी नगर 743135 नाइहाटी, जिला 24 परगना (बंगाल) (कार्यालय : 15 इण्डिया ऐक्सचेंज प्लेस कलकत्ता 700001)	एट्विल पटसन के बोरे— IS : 1943–1964
4.	सी एम/एल-8958 1980-09-03	80-08-16	81-08-15	,,	भारी सी पटसन के बोरे और भारी "सी" कपड़ा— IS : 2874–1966 और IS : 3751–1966
5.	सी एम/एल-8959 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	शा वैलेस एण्ड कं० लि०, (कीटनाशक पदार्थ विभाग, दुर्गाचक–721602) जिला हलदिया (प० बंगाल) (कार्यालय : 4 बैंकशाल स्ट्रीट, कलकत्ता-700001)	डाइमिथाएट पायसनीय सांद्र द्रव— IS : 3903–1975
6.	सी एम/एल-8960 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	सकब्री इंजीनियरिंग कार्पोरेशन झारग्राम, जिला मिदनापुर (प० बंगाल) (कार्यालय : जी सी/-1, क्लाइव बिल्डिंग, 8 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001)	सरंचना कार्य के लिए इस्पात नलियां किस्म: काली ई आर डब्ल्यू वाई एम टी 210, श्रेणी-हल्की माप: 40 मिमी तक एन बी— IS : 1161–1969
7.	सी एम/एल-8961 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	इलाइट सर्जिकल इंडस्ट्रीज 23 ए पंडित पार्क, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051	रक्तचापमापी, पारेदार, किस्म 1— IS 3390–1977
8.	सी एम/एल-8962 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	जी एम एग्रो इंडस्ट्रीज निमोम डाकखाना, त्रिवेन्द्रम-695020	हस्तचालित संपीड़न नेपसेक छिड़काव यन्त्र अदाबधारी किस्म का 9 लिटर क्षमता का— IS : 1970 (भाग 1)-1974
9.	सी एम/एल-8963 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	लक्ष्मी केमिकल्ज, बी-3 इंडस्ट्रियल एरिया पतवा (जिला पटना), बिहार	बी एच सी (एच सी एच), धूलन चूर्ण- IS : 561–1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	सी एम/एल-8964 1980-09-10	80-09-01	81-08-31	विजय स्टील रोलिंग मिल (प्रा०) लि० 37 दुमकुर रोड, दूसरा फेज पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बंगलौर-562139	कंक्रीट प्रबलन के लिए शीत बलदार विकृत इस्पात छड़ें— IS : 1786–1966
11.	सी एम/एल-8965 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	सारदा प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि०, 9 पारसी चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-700001	कंक्रीट शटरिंग कार्य के लिए प्लाईवुड, किस्म 2— IS : 4990–1969
12.	सी एम/एल-8966 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	आसाम उद्योग कं०, मनकोटा रोड, डिब्रूगढ़ (आसाम)	संरचना इस्पात (मानक गुणता वाली)— IS : 226–1975
13.	सी एम/एल-8967 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	नारंग आयरन एण्ड स्टील कं० प्रा० लि०, बरवा रोड डाकखाना नागनगर, जिला धनबाद (बिहार)	संरचना इस्पात (मानक गुणता वाली)— IS : 226–1975
14.	सी एम/एल-8968 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	होप इंडिया लि०, पेन्च स्टील विभाग, डाकखाना शाहगंज, जिला हुगली (प० बंगाल) (कार्यालय : हांगकांग हाउस, बी० बी० डी० बाग, कलकत्ता-700001)	कंक्रीट प्रबलन के लिए शीत बलदार विकृत इस्पात छड़ें— माप 12 मिमी से 28 मिमी सांकेतिक व्यास— IS : 1786–1966
15.	सी एम/एल-8969 1980-09-11	80-09-16	81-09-15	मोदी स्टील्स, (प्रो० मोदी इंडस्ट्रीज लि०) मोदीनगर-201204	शिरोपरिपावर प्रेषण के लिए जस्ती-कृत इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चालकों की कोर के लिए इस्पात तार— IS : 398 (भाग II) –1976
16.	सी एम/एल-8970 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	गवर्नमैंट सोप फैक्ट्री, बंगलौर इंडस्ट्रियल सबर्ब राजाजीनगर, बंगलौर-560055 (कर्नाटक)	कपड़े की धुलाई की संश्लिष्ट डिटर्जेंट बट्टी, केवल श्रेणी 1— IS : 8180–1976
17.	सी एम/एल-8971 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	चिकमगलूर केमिकल्स वर्क्स, इंडस्ट्रियल इस्टेट, शेड न० डी 1 और डी 2 कदूर-मंगलौर रोड, चिकमगलूर-577101 [कार्यालय : मुनीर काम्पलेक्स, मलन्दुर रोड, चिकमगलूर-577101 (कर्नाटक)	नाअ सल्फेट तकनीकी— IS : 261–1966
18	सी एम/एल-8972 1980-09-11	90-10-01	81-09-30	श्री अम्बिका मेटल वर्क्स, 8 नूतनपारा रोड, लिलुआ, हावड़ा-711204 (कार्यालय : 12-ए नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता-700001)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)— IS : 226–1975
19.	सी एम/एल-8973 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	"	कंक्रीट प्रबलन के लिए शीत बलदार विकृत इस्पात छड़ें, माप 20 मिमी० तक— IS : 1786–1966

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	सी एम/एल-8974 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	होप इंडिया लि०, पेंचे स्टील विभाग डाकखाना शाहगंज, जिला हुगली (प० बंगाल) (कार्यालय. हांगकांग हाऊस, बी० बी० डी० बाग, कलकत्ता-700001)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)- IS : 226–1975
21.	सी एम/एल-8975 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	जुपीटर थर्मोमीटर्ज, 33-21-24 एलुरु रोड, सीतारामपुरम, विजयवाडा–520004 (आं० प्र०) [कार्यालय: डा० रामचन्द्र राव रोड, विजयवाड़ा-520002 (आं० प्र०)]	ठोस नली वाले डाक्टरी थर्मोमीटर- - IS : 3055–(भाग 1)–1977
22.	सी एम /एल-8976 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	वेंकटेश्वर स्टेनलेस स्टील एंड वायर इंडस्ट्रीज, 3, 4 और 5 वुड कार्फ वाल टैक्स रोड, मद्रास–600001 (तमिलनाडु) [कार्यालय: 305 मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास–600003 (तमिलनाडु)]	पिटवां एलुमिनियम के बर्तन ग्रेड 19000– IS : 1660–(भाग 4)–1977
23.	सी एम/एल-8977 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	अम्बर एलेक्ट्रिकल कंडक्टर्ज प्रा० लि०, रंगपुरम, वेलोर–632009	लहुदार एलुमिनियम चालक और जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एलुमियनम चालक— IS: 398–(भाग 1 और II)-1976
24.	सी एम/एल–8979 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	जय किसान एग्रो इंडस्ट्रीज, 31/33 उद्योग नगर (नवलखा), इन्दौर-451001 (म०प्र०)	मुर्गा मुर्गी आहार के लिए खनिज मिश्रण— IS : 5672–1970
25.	सी एम/एल-8979 1980-09-12	80-09-16	81-09-15	स्वदेशी ट्यूब्ज प्रा० लि०, दिल्ली हिसार रोड, हिसार (हरियाणा) (कार्यालय · 56 बी रामा मार्ग नजफगढ़ रोड, दिल्ली)	मृदु इस्पात की नलियां, समतली सिरों की काली ; श्रेणी हल्की मध्यम, माप : 50 मिमी फत एनबी– IS : 1239(भाग 1)–1979
26.	सी एम/एल-8980 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	अजय कैमिकल्ज, एफ-400 रोड नं० 9 एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)	जस्ता सल्फेट, कृषि ग्रेड— IS 8249–1976
27.	सी एम/एल-8981 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	किलपेस्ट प्रा० लि०, 7 सी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्द पुरा, भोपाल-462023 (म०प्र०)	डी डी टी पायसनीय सांद्र द्रव– IS : 633–1975
28.	सी एम/एल-8982 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	"	बी एच सी (एचसीएच) धूलन चूर्ण— IS : 561–1978
29.	सी एम/एल-8983 1980-09-12	80-10-01	91-09-30	"	मेलाथियान धूलन चूर्ण— IS 2568–1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	सी एम/एल-8984 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्ज लि०, बलरामपुरम-695501 जिला त्रिवेन्द्रम (केरल)	अविरंजित सूती धागे, ग्रेड बी धुने हुए ताने का नं० 60 एस और 40 बी--, IS 171; 1973
31.	सी एम/एल-8985 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	इलेक्ट्रोमेक इंडस्ट्रीज, पुराना मनबजार रोड, पो० बा० नं० 53, पुरुलिया-723191 (प० बंगाल)	शॉट फायरिंग केबल, पी वी सी रोधित दो कोर वाले समानान्तर जुड़वा) एक शॉट फायर वाले केबल--; IS 5950-1971
32.	सी एम/एल-8986 1980-09-12	80-09-16	81-09-15	भारत स्टील रोलिंग मिल्ज मालिक (रोनक एण्ड कं० प्रा० लि०) गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल इस्टेट 12.6 मील पत्थर, मथुरा रोड, डाकखाना अमर नगर, फरीदाबाद (हरियाणा)	गढ़ाई के लिए कार्बन इस्पात बिलेट और छड़े : श्रेणी 4 तक सब श्रेणियां— IS : 1875-1978
33.	सी एम/एल-8987 1980-09-15	80-10-01	81-09-30	नेशनल मेटल इंडस्ट्रीज 314, भागीरथपुरा, इन्दौर-452003 (म०प्र०)	संरचना इस्पात (मानक किस्म)--- IS : 226-1975
34.	सी एम/एल-8988 1980-09-15	80-10-01	81-09-30	अजन्ता ट्यूब्स लि०, जैन इंडस्ट्रियल इस्टेट, 36 कि०मी० दिल्ली हापुड़ रोड, गाजियाबाद, (कार्यालय : डी. 20 कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001)	जल गैस और मल के लिए विद्युत वैल्डकृत इस्पात नलियां, श्रेणी I, II, III और विशेष श्रेणी, 70 कि०ग्रा०/सेमी2 दबाव माप—केवल 2000 मिमी एन बी--- IS : 3589-1966
35.	सी एम/एल-8989 1980-09-15	80-10-01	81-09-30	बत्तियां स्टील इंडस्ट्रीज प्रा० लि० 34, नई भोइगुडा, सिकन्दराबाद-500003 (आ०प्र०)	इस्पात की खानेदार अलमारी (समंजनीय किस्म की)-- IS : 3312-1974
36.	सी एम/एल-8990 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	एग्रो पेस्टीसाइड्स, 10, इंडस्ट्रियल इस्टेट, खेड़ा, इटारसी (म० प्र०)	बीएचसी (एचसीएच) धूलन चूर्ण-- IS : 561-1972
37.	सी एम/एल-8991 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	ऐग्रो पेस्टीसाइड्स, 10, इंडस्ट्रियल इस्टेट, खेड़ा इटारसी (म० प्र०)	डी डी टी धूलन चूर्ण— IS : 564-1975
38.	सी एम/एल-8992 1980-09-16	80-10-16	81-10-15	कारोमन्डल लूब्रिकेन्टस प्रा० लि० ए-7 आटोनगर इंडस्ट्रियल इस्टेट, विशाखापतनम-530012 (आ० प्र०)	पैराफिन मोम, किस्म 3— IS : 4654-1975
39.	सी एम/एल-8993 1980-09-16	80-12-16	81-12-15	यसमेन होजिरी मिल्स 81-मंगलम रोड, तिरुपुर-638604 (त०ना०)	सादी बुनी हुई सूती बनियान किस्म : गोल गले और गोल गले बाहों वाली, माप : 75 से 100 सी गेज : 24— IS: 4964 (भाग II)—1975
40	सी एम/एल-8994 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	दुर्गा पेस्टीसाइड्स 13 इंडस्ट्रियल एस्टेट,	कार्बारिल धूलन चूर्ण-- IS : 7122-1973

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				बरहामपुर-450031 (म०प्र०)	
41.	सीएम/एल–8995 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	,, ,,	एंडोसल्फान पायसनीय सांद्र द्रव— IS : 4323–1973
42.	सीएम/एल–8996 1980-09-18	80-10-01	81-09-30	हीरा (इंडिया) लि०, पंचशील स्टील विभाग डाकखाना शाहगंज जिला हुगली, (पश्चिमी बंगाल) (कार्यालय हॉगकांग हाउस, 31 बी बी डी बाग, कलकत्ता-700001)	गढ़ाई के लिए कार्बन इस्पात छड़ें— IS 1875–1978
43.	सीएम/एल–8997 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	पर्फेक्ट मैन्युफेक्चरर्स, 8 डी भक्ति नगर, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजकोट-360002 (कार्यालय : कनक रोड, राजकोट 360001) (गुजरात)	ऊर्ध्वा एक सिलिंडर के, जल शीतित डीजल इंजन, निम्नलिखित क्षमता का निर्धारण गति 5.88 किवा 850 आरपीएम (8 हा पा) लागू विशेष ईंधन खपत श्रेणी बी 309 ग्रा/किवा/घंटा IS : 1601–1960
44	सीएम/एल–8998 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	कैमो इलेक, प्लाट नं० ए-484, 24 वी रोड वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट ठाणे-400604 (महाराष्ट्र)	ज्वालासह खोल : (1) लिमिट स्विच-सीई/लिम्स का (2) रोटेरी स्विच-सी ई 2 लिम्स का (3) पुश बटन स्टेशन आर्मीटर सहित—सी ई 3 लिम्स का के लिए— IS : 2148–1968
45.	सीएम/एल–8999 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	विजय टैंक्स एंड वेसेल्स प्रा० लि० बी-8 और बी-11, ए०पी० इंडस्ट्रियल इस्टेट (बी एच पी वी के निकट) विशाखापटनम (आं०प्र०)	बिटूमन, ड्रम, बिम्स की— IS : 3575–1977
46.	सीएम/एल–9000 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	एस० पी० कुमार स्या एण्ड सन्स मसूर नगर, लखनऊ 226003 (उ०प्र०)	इस्पात बट कब्जे मध्यमभार के, 150 मिमी तक के, IS : 1341–1976
47.	सीएम/एल–9001 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	मार्डन कैमिकल्ज, डाकखाना रिप्पनपेट-577426 जिला शिमोगा (कर्नाटक)	बी एच सी (एच सी एच) जल विसर्जन य चूर्ण सांद्र IS 562–1978
48	सीएम/एल–9002 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	इंडिकोल पी-2, ए-टाइप, शेड नं० 5, और 6, जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट, वत्वा (प० रेलवे) अहमदाबाद-382445 (गुजरात)	मेलाथियान धूलन चूर्ण : IS : 2568–1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	सीएम/एल-9003 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	विद्युत उद्योग बी-142 रोड 6 विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302013 कार्यालय, सिरोरिया दरवाजा (जयपुर-302002)	1100 वो तक की चालू वोल्टता के लिए तांबा चालक वाले पी वी सी रोधित (भारी क्षमता के) विद्युत केबल, आच्छादित और कवच रहित IS 1554 (भाग 1)—1976
50.	सीएम/एल-9004 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	राजकोट क्लिनिकल थर्मामीटर्ज क० प्रा० लि० उद्योग नगर रोड, सुरेन्द्र नगर-363001 (गुजरात)	ठोस नली के, मुंह में लगाने वाले, डाक्टरी थर्मामीटर— IS 3055 (भाग 1)—1977
51.	सीएम/एल-9005 1980-09-24	80-01-01	81-09-30	सिन्दिकेम लिमिटेड सिदी रेलवे स्टेशन के निकट सिदी जिला वर्धा (महाराष्ट्र) (कार्यालय : धरस्कार बिल्डिंग, रणदास पेठ नागपुर-440101	कार्बारिल जल विसर्जनीय सान्द्र चूर्ण—(बाहरी छिड़काव के लिए)— IS : 7131—1973
52.	सीएम/एल-9006 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	राको मर्केन्टाइल ट्रेडर्स, बी-2 राज्य इंडस्ट्रियल इस्टेट, तालकटोरा रोड, लखनऊ 226005 (उ० प्र०)	सूखा डिस्टेम्पर, वांछित रंग के— IS 427—1965
53.	सीएम/एल-9008 1980-09-25	80-01-01	81-09-30	लार्सविन इंजीनियर्स प्रा० लि०. प्लाट नं० 9 और 10, आई०डी०ए० जीडी मटेला, हैदराबाद-500854 (आं०प्र०)	33.3 लिटर क्षमता वाले एल पी जी, सिलिण्डर, सी सी ई पत्र नं० जी-3 (42)/82 तारीख 80-09-11/18 द्वारा ड्राइंग नं० 4001 के अनुसार— IS : 3196—1974
54.	सीएम/एल-9003 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	बी के इलेक्ट्रिकल्स, 15, 16, 17, इंडस्ट्रियल एरिया, जबलपुर (म० प्र०) (कार्यालय : 994 राइट टाउन जबलपुर)	1100 वोल्ट तक की चालू वोल्टता के लिए एलुमीनियम चालक वाले पी वी सी रोधित और पी वी सी वलयदार केबल (माप 6.00 मिमी² तक)— IS : 694—1977
55.	सीएम/एल-9009 1980-09-25	80-01-01	81-09-30	इचालकरन्जी मशीन सेंटर प्रा०लि० 112, इंडस्ट्रियल इस्टेट, इचालकरन्जी (महाराष्ट्र)	अन्तर्दाह इंजन के लिए सिलिंडर लाइनर किस्म "X" वेटलाइनर— IS : 6750—1972
56.	सीएम/एल-9010 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	कैल्ट्रान प्रोजेक्टर्स लि० 1133 और 1134, सास्ती बिहार पीरुरकडा, त्रिवेन्द्रम-895005	16 मिमी के सुवाह्य ध्वनि और चित्र और चलचित्र प्रक्षेपी IS 4497—1977
57.	सीएम/एल-9011 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	हाइमैटिक इन्डस्ट्रीज, 42, न्यू वजीरपुर कम्पलैक्स, दिल्ली-110052	पदचालित स्प्रेयर— IS : 3652—1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	सी एम/एल–9012 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	इलैक्ट्रिकल मशीनज कारपोरेशन, ब्लाक न० 28/2, श्री इंडस्ट्रियल मिल्स इस्टट, कालीदास मिल अहाता, गोमतीपुर, अहमदाबाद (कार्यालय : निर्मल, तीसरी मंजिल, वीन बाई टॉवर के सामने, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380001	घुमनी विद्युत मशीन, 7.5 किवा० 140 वो० 2000 आर पी एम टी ई एफ सी, रोधण श्रेणी एफ, निरन्तर क्षमता की डी सी रांट मोटर— IS : 4722–1968
59.	सी एम/एल–9013 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	ब्राइट वायर्ज लि०, डाकखाना, बाडु-743202 बाडु रोड, धायामध्यमग्राम, जिला 24 परगना (प० बं०)	ऊर्ध्व प्रेषण के लिए अस्तीकृत इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चालक की कोर के लिए इस्पात तार– IS : 398(भाग II)—1976
60.	सी एम/एल–9014 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	ट्रापिकल ऐग्रोसिस्टम्ज प्रा० लि०, 530/28, वनग्राम रोड, अथिपेट, मद्रास-600058	मानोक्रोटोफ़ास जल घुलनशील सांद्र— IS : 8074–1976
61.	सी एम/एल-9015 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	पुंज सन्स प्रा० लि०, वर्मा माइन्ज एरिया, जमशेदपुर-831007 (बिहार) कार्यालय : 4ए रायड स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 (प० बंगाल)	ऊष्मीय रोधन के लिए अबद्ध रॉक और स्लेग वूल, किस्म-1— IS : 3677–1973
62.	सी एम/एल–9016 1980-09-29	80-10-01	81-09-30	स्टील एण्ड मेटल ट्यूब्ज (इंडिया) प्रा० लि०, 22वां मील, दिल्ली हापुड रोड, गॉवगलंद, जिला गाजियाबाद	मृदु इस्पात नलियां, काली, चूड़ीदार, और साकेट सहित, श्रेणी–हल्की, माप-50 मिमी एन बी से अधिक और 100 मिमी एन बी तक– IS : 1239 (भाग I)—1979
63.	सी एम/एल–9017 1980-09-29	80-10-16	81-10-15	सिन्दीकेम लि०, शहर सिन्दी, जिला वर्धा (महाराष्ट्र) (कार्यालय : नीलगिरी रामदास पैठ, नागपुर-440010 (महाराष्ट्र)	कापर आक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत जल विसर्जनीय सांद्र चूर्ण— IS : 1507–1977
64.	सी एम/एल-9018 1980-09-29	80-10-16	81-10-15	मदन इंजीनियरिंग टूल प्रोडक्टस, बी 26 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020	इस्पात बट कब्जे, माध्यम भार के कोल्ड रोल्ड मृदु इस्पात बट कब्जे, माप : 75 मिमी, 100 मिमी और 125 मिमी IS : 1341–1976
65.	सी एम/एल—9019 198 0-09-29	8 0-10-16	81-10-15	युनिवर्शल स्टील एण्ड एलोइज लि०, गुरूकुल इन्द्रप्रस्था इंडस्ट्रीयल एस्टेट 1216, माईल स्टोन, मथुरा रोड पो०ओ० अमरनगर, फरीदाबाद— 121003	स्टील इनगोट्स फार दी प्रोडक्शन आफ लेमीनेटिड स्प्रिंग (रेलवे रोलिंग स्टोक)— IS : 8 054—1976
66.	सी एम/एल–9020	8 0-10-16	8 1-10-15	गोरमिन्ट आफ इंडिया प्रोडक्ट सैन्टर फार इलैक्ट्रिक मोटर्स, तिरूवैली-5 (केरल)	थ्रीफेस स्कवारीय नेज इन्डक्सन पम्प्स फार एग्रीकचरल एपलीकेसन 2.2 के डिब्बे विद क्लास 'ए' इन्सूलेशन IS: 7538—1975
67.	सी एम/एल–9021	8 0-10-16	8 1-10-15	एरावली केमीकल्ज लेबोरेट्रीज, जी–464, विश्वाकर्मा इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302013 (राजस्थान)	डिसइफैकटेन्ट फलूइड ग्रेड 3 क्लास 'ए' टाइप नारमल— IS : 1061—1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68.	सीएम/एल–9022 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	कृष्णा पैन्ट्स एण्ड केमिकल्स कं०, भूली रोड, वासेपुर, धनबाद (बिहार)	इनेमिल, इन्टीरीयर, (क) अन्डर कोटिंग, एण्ड (ख) फिनिशिंग— IS: 133 : 1975
69.	सी एम/एल–9023 1980-06-30	80-09-16	81-09-15	स्टील क्रीट प्राईवेट लि० इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेन्ट एरीया, गाजूवाका, विशाखापतनम आफिस, स्टील क्रीट हाउस, 3 दिनशाह वाचा रोड, बम्बई—400020	माईल्ड स्टील ट्यूब्ज, ब्लैक विद पलेन एण्ड्ज साइज अप्टू एण्ड इन्कलुडिंग 50 एम०एम० ओनली— क्लास : लाइट— IS. 1239 (पार्ट I)—1979
70.	सी एम/एल-9024 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	ग्वालियर वायर प्रॉडक्ट्स, 40 इंडस्ट्रियल इस्टेट ग्वालियर-474004 (म०प्र०)	शिरोपरि पावर प्रेषण के लिये एलुमिनियम/लड़दार चालक और जस्तीकृत इस्पात प्रबलित एलुमिनियम चालक— IS : 398–1976
71.	सी एम/एल–9025 1980-09- 30	80-10-16	81-10-15	इंडियन पेस्ट कंट्रोल क०, प्लाट 1 ए, सैक्टर बी, गोविंदपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया, भोपाल 462003 (म० प्र०)	बी एच सी (एच सी एच) धूलन चूर्ण— IS : 561-1972
72.	सी एम/एल–9026 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	एस पी वरमानी एंड संस प्रा० लि०, ज्वाला फ्लार मिल्ज़ हरिपुरा अमृतसर-143003 (पंजाब)	मवेशी के लिए मिश्रित आहार— IS 2052-1979
73.	सी एम/एल–9027 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	गोल्डन पेन्ट्स एण्ड कैमिकल्ज, छातीविन्ड गेट के बाहर, कोटमहना सिंह, अमृतसर 143001 (पंजाब)	पेंट के लिए तैल पेस्ट, अंतरंग, सफेद, किस्म 1 और 2 IS : 96–1950
74.	सी एम/एल–9028 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	नेल्को (इंडिया) प्रा० लि०, बागपत रोड, मेरठ-250002	डिस्कस, माप 1 और 2— IS : 4142–1967
75.	सी एम/एल–9029 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	ऐक्वालेक पेंट्स, 70 नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015	इनेमल संश्लिष्ट बाह्य, केवल अंडरकोटिंग रंग श्रेणी केवल 17– IS : 2932–1974
76.	सी एम/एल–9030 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	ऐक्वालेक पेंटस 70, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015	तैयार मिश्रित पेंट फिनिश देने का अंतरंग सामान्य, उपयोग के लिए— IS : 2932–1974
77.	सी एम/एल–9031 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	दि साइंटीफिक इलेक्ट्रोमाइड्ज़ कं० 117/1, मंगलगिरी रोड, गुंटूर 522001 (आ० प्र०)	कार्बारिल जल विर्जनीय सान्द्र चूर्ण— धरती छिड़काव ग्रेड— IS : 7121–1973
78.	सी एम/एल–9032 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	फोनिक्स आयल कं० (इंडिया), प्रा० लि०, 448 मीरपुर, कानपुर छावनी-208004 कार्यालय : कमरा नं० 27 और 28, मोती भवन, कलेक्टरगंज, कानपुर उ०प्र०	(1) मशीनी तेल—मध्यम ग्रेड, (2) स्पिंडिल तेल—हल्का ग्रेड— IS : 493—1958
79.	सी एम/एल–9033 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	रामकृष्ण मेटल वर्क्स (बम्बई) प्लाट नं० सी 33 वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (महाराष्ट्र)	स्टेनलेस इस्पात की चादरें और कुंडल IS : 5522–1978

1	2	3	4	5	6
80.	सी एम/एल-9034 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	एम एम इंडस्ट्रीज, 138, फोरशोर रोड, रामकिस्तोपुर, हावड़ा (प० बं०) (कार्यालय : 130 काटन स्ट्रीट, कलकत्ता-700007)	उर्वरक भरने के परतदार पटसन के बोरे— IS : 7406-1974
81.	सी एम/एल-9035 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	टैकनिको (इण्डिया) 3 बी०बी० गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-700012 (प० बं०)	लैण्डिंग वाल्व (अतरंग हाइड्रेंट) किस्म ग— IS : 5290-1977
82.	सी एम/एल-9036 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	,, ,,	अग्निशमन के लिए स्वचालित शाखा पाइप, किस्म—स्वचालित IS : 2871-1964

[सं० सी०एम०डी०/13:11]

ए०पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

S.O. 4614.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that eightytwo licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been granted during the month of September 1980 authorizing the licensees to use the Standard Marks:

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L—)	Period of Validity From	To	Name and Address of the Licencee	Article, Process covered by the Licence and the Relevant IS : Designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L—8955 1980-09-03	80-08-16	81-08-15	Hukumchand Jute Mills Ltd., P.O. Hazinagar-743135, Naihati, Distt. 24 Parganas (West Bengal) (Office : 15 India Exchange Place, Calcutta-700001)	Jute corn sacks and jute corn sack cloth- IS : 2875—1964& IS : 3750—1966
2.	CM/L—8956 1980-09-03	80-08-16	81-08-15	-do-	L—twill bags and L—twill cloth— IS : 3794—1966 & IS : 3668—1966
3.	CM/L—8957 1980-09-03	80-08-16	81-08-15	Hukumchand Jute Mills Ltd., P.O. Hazinagar-743135 Naihati, Distt. 24 Parganas, (West Bengal) (Office : 15, India Exchange Place Calcutta-700001)	A—twill jute bags— IS : 1943—1964
4.	CM/L—8958 1980-09-03	80-08-16	81-08-15	-do-	Heavy cee jute bags and heavy cee cloth. IS : 2874—1966 IS : 3751—1966
5.	CM/L—8959 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	Shaw Wallace & Co. Ltd . (Pesticides Division), Durgachak-721602. Distt. Haldia, (W.B.) (Office : 4 Bankshall Street . Calcutta-700001)	Dimethoate EC— IS : 3903—1975
6.	CM/L—8960 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	Sakbry Engineering Corporation, Jhargram, Distt. Midnapur, (West Bengal). (Office : GC/-1, Clive Buildings, 8 Netaji Gupta Road, Calcutta-700001)	Steel tubes for structural purposes Type : Black ERW: Yst 210 Class : 'Light' Size : upto 40mm NB IS : 1161—1969
7.	CM/L—8961 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	Elite Surgical Industries, 23 A, Pandit Park, Krishna Nagar, Delhi-110051	Sphygmomanometer, mercurial type-I — IS : 3390—1977
8.	CM/L—8962 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	Geeyes Agro Industries, Nemom P. O., Trivandrum-695020 (Tamil Nadu)	Hand operated compression knapsack sprayer, non-pressure retaining type-Capacity 9 Litres— IS : 1970 (Part I)—1974

1	2	3	4	5	6
9.	CM/L-8963 1980-09-03	80-09-16	81-09-15	Lakshmi Chemicals, B-3, Industrial Area, Fatwah, Dist. Patna, (Bihar)	BHC (HCH) DP - IS : 561—1978
10.	CM/L-8964 1980-09-10	80-09-01	81-08-31	Vijaya Steel Rolling Mill (P) Ltd., 37 Tumkur Road, IInd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-562139	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement — IS : 1786—1966
11.	CM/L-8965 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Sarda Plywood Industries Ltd., 9, Parsee Church Street, Calcutta-700001	Plywood for concrete shuttering work Type-2 IS : 4990—1969
12.	CM/L-8966 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Assam Udyog Co., Mancotta Road, Dibrugarh Assam	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
13	CM/L-8967 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Narang Iron & Steel Co. (P) Ltd., Barwa Road, P.O. Nagnagar, Distt. Dhanbad (Bihar)	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975
14	CM/L-8968 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Hope (India) Ltd., Pench Steel Division, P.O. Shahgunge, Distt. Hooghly, (West Bengal) (Office : Hongkong House, B.B.D. Bag(s), Calcutta-700001)	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement Size : 12mm to 28mm nominal diameter— IS : 1786—1966
15	CM/L-8969 1980-09-11	80-09-16	81-09-15	Modi Steels, (Prop. Modi Industries Ltd.), Modinagar-201204	Steel wire for the core of galvanized steel reinforced aluminium conductors for overhead transmission purposes— IS : 398 (Pt-II)—1976
16.	CM/L-8970 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Govt Soap Factory, Bangalore Industrial Suburb, Rajajinagar, Bangalore-560055 (Karnataka)	Synthetic detergent tablets for laundry use Grade : 1 only — IS : 8180—1976
17.	CM/L-8971 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Chikmagalur Chemical Works Industrial Estate, Shed No. D1 & D2, Kadur—Mangalore Road, Chikmagalur—577101 [Office : Munir's Complex, Mallandur Road, Chikmagalur-577101 (Karnataka)] ,	Copper sulphate technical— IS : 261—1966
18.	CM/L-8972 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Shri Ambika Metal Works, 8, Nutanpara Road, Ililloah, Howrah-711204 (Office : 12-A, Netaji Subhash Road, Calcutta-700001)	Structural steel (standard quality) — IS : 226—1975
19.	CM/L-8973 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	-do-	Cold twisted deformed steel bars for concrete reinforcement Size : upto 20mm IS : 1786—1966
20	CM/L-8974 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Hope (India) Ltd., Pench Steel Division, P.O. Shahgunge, Distt. Hooghly, (West Bengal) (Office : Hongkong House, 31, B.B.D Bag(s), Calcutta-700001)	Structural steel (standard quality) — IS : 226—1975
21	CM/L-8975 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Jupiter Thermometers, 33-21-24 Eluru Road, Seetheramapuram, Vijayawada-520004 (Andhra Pradesh) [Office : Dr Ramachandra Rao Road, Vijayawada-520002, (Andhra Pradesh)]	Clinical thermometers solid stem type, oral— IS : 3055 (Part I)—1977

1	2	3	4	5	6
22.	CM/L—8976 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Venkateshwara Stainless Steel & Wire Inds., 3, 4 & 5 Wood Wharf, Wall Tax Road, Madras-600001 (Tamil Nadu) [Office : 305, Mint Street, Madras-600003 (Tamil Nadu)]	Wrought aluminium utensils, grade 19000— IS : 1660 (Part IV)—1977
23.	CM/L—8977 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Amber Electrical Conductors (Pvt) Ltd., Rangupuram, Vellore-632009	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel-reinforced— IS : 398 (Part I & II)—1976
24.	CM/L—8978 1980-09-11	80-10-01	81-09-30	Jai Kisan Agro Industries, 31/33, Udyog Nagar, (Navlakha), Indore-452001 (M.P.)	Mineral mixtures for poultry feeds IS : 5672—1977
25.	CM/L—8979 1980-09-12	80-09-16	81-09-15	Swadeshi Tubes Pvt. Ltd., Delhi Hissar Road, Hissar, (Haryana). (Office : 56-B Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi)	Mild steel tubes, plain end, black: Classes light and medium Sizes—upto and including 50mm NB— IS : 1239 (Part I)—1979
26.	CM/L—8980 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	Ajay Chemicals, F-400 Road No. 9F, Vishwakarama Industrial Area, Jaipur-302013, (Rajasthan)	Zinc sulphate, agricultural grade IS : 8249—1976
27.	CM/L—8981 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	Kipest Pvt. Ltd., 7C, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462 023 (M.P.)	DDT EC— IS : 633—1975
28.	CM/L—8982 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	-do-	BHC (HCH) DP— IS : 561—1978
29.	CM/L—8983 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	-do-	Malathion DP— IS : 2568—1978
30.	CM/L—8984 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	Trivandrum Spinning Mills Ltd., Balaramapuram-695501; Distt. Trivandrum (Kerala)	Grey cotton yarn, Grade B, Carded warp of counts 60s and 40b— IS : 171—1973
31.	CM/L—8985 1980-09-12	80-10-01	81-09-30	Electromach Industries, Old Manbazar Road, Post Box No. 53, P.O. Distt. Purulia-723101 (West Bengal)	Shot firing cables PVC insulated two core (parrel twin) single shot firing cables— IS : 5950—1971
32.	CM/L—8986 1980-09-12	80-09-16	81-09-15	Bharat Steel Rolling Mills, (Prop : Raunaq & Co. Pvt. Ltd.) Gurukul Indraprastha Industrial Estate, 12.6 Milestone, Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad, (Haryana)	Carbon steel billets and bars for forging; All classes upto and including class IV— IS : 1875—1978
33.	CM/L—8987 1980-09-15	80-10-01	81-09-30	National Metal Industries, 314, Bhagirathpura, Indore;452 003 (M.P.)	Structural steel (standard quality)— IS : 226—1975

1	2	3	4	5	6
34.	CM/L—8988 1980-09-15	80-10-01	81-09-30	Ajanta Tubes Ltd., Jain Industrial Estate, 36 K.M. Delhi-Hapur Road, Ghaziabad, (Office : D-20, Connaught Place, New Delhi-110001)	Electrically welded steel pipe for water, gas and sewages; Classes-I, II, III and special class upto 70Kg/cm pressure; Size-200mm NB only— IS : 3589—1966
35.	CM/L—8989 1980-09-15	80-10-01	81-09-30	Bantia Steel Industries Pvt. Ltd., 14, New Bhoiguda, Secunderabad-500003, (A.P.)	Steel shelving cabinets (adjustable type)— IS : 3312—1974
36.	CM/L—8990 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	Agro Pesticides, 10, Industrial Estate, Khera, Itarsi, (M.P.)	BHC (HCH) DP— IS : 561—1972
37.	CM/L—8991 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	-do-	DDT DP— IS : 564—1975
38.	CM/L—8992 1980-09-16	80-10-16	81-10-15	Coromandel Lubricants Pvt. Ltd., A-7 Autonagar, Industrial Estate, Visakhapatnam-530012 (Andhra Pradesh)	Paraffin wax— Type 3— IS : 4654—1975
39.	CM/L—8993 1980-09-16	80-12-16	81-12-15	Yesman Hosiery Mills, 81, Manglam Road, Tirupur-638604 (Tamil Nadu)	Plain knitted cotton vest : Type : RN & RNS Size : 75 to 100 cms Gauge : 24— IS : 4954 (Part II)—1975
40.	CM/L—8994 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	Durga Pesticides, 13, Industrial Estate, Burhanpur-450331, (M.P.)	Carbaryl DP— IS : 7122—1973
41.	CM/L—8995 1980-09-16	80-10-01	81-09-30	Durga Pesticides, 13, Industrial Estate, Burhanpur-450331 (M.P.)	Endosulfan EC— IS : 4323—1967
42.	CM/L—8996 1980-09-18	80-10-01	81-09-30	Hope (India) Ltd., Pench Steel Division, P.O. Shahgunge, Distt. Hooghly, West Bengal. (Office : Hongkong House, 31 B.B.D. Bag(s), Calcutta-700001)	Carbon steel bars for forgings— IS : 1875—1978
43.	CM/L—8997 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	Perfect Manufacturers, 8-D, Bhaktinagar Industrial Estate, Rajkot-360002 [Office : Kanak Road, Rajkot-360001] (Gujarat)	Vertical, single cylinder, water cooled diesel engines of the following rating Output: 5.88KW (8HP) — Speed: 850 RPM Governing: Class 'B' — SFC: 309 g/kW/h IS : 1601—1960
44.	CM/L—8998 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	Chemi Elec., Plot No. A-484, 24th Road, Wagle Industrial Estate, Thane-400 604 (Maharashtra)	Flameproof enclosures for (1) Limit switch, type CE-1; (2) Rotary switch, type CE-2; (3) Push buttons station with ammeter, type CE-3 IS : 2148—1968

1	2	3	4	5	6
45.	CM/L—8999 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	Vijay Tanks & Vessels Pvt. Ltd., B-8 & B 11, A.P. Industrial Estate, (Near BHPV), Visakhapatnam (A.P.)	Bitumen drums, type - 'B'— IS : 3575—1977
46.	CM/L—9000 1980 09-23	80-10-01	81-09-30	S.P Kumria & Sons, Mansoor Nagar, Lucknow-226003, (U.P.)	Steel butt hinges-Medium weight upto 150mm— IS : 1341—1976
47.	CM/L—9001 1980 09-23	80-10-01	81-09-30	Modern Chemicals, P.O. Ripponpet-577426 Dist. Shimoga (Karnataka)	BHC (HCH) WDP6— IS : 562—1978
48.	CM/L—9002 1980-09-23	80-10-01	81-09-30	Indichem. C2, A Type Shed No. 5 & 6, G.I.D.C. Industrial Estate, Vatva (W. Rly) Ahmedabad-382445 (Gujarat)	Malathion DP— IS : 2563—1978
49.	CM/L—9003 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	Vidyuat Udyog, B 142, Road No. 9, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302 013 (Office : Tripolia Gate, Jaipur-302002)	PVC insulated (heavy duty) electric cables sheathed and unarmoured with copper conductor for working voltages upto and including 1100 volts— IS : 1554 (Part I)—1976
50.	CM/L—9004 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	Jintan Clinical Thermometers Co. (India) Pvt. Ltd. Udyonagar Road, Surendranagar-363001 (Gujarat)	Clinical thermometers, solid stem type, oral pattern— IS : 3055 (Part I)—1977
51.	CM/L—9005 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	Sindichem Limited, Sindi, Near Sindi Railway Station, Town Sindi, Distt. Wardha (Maharashtra) (Office : Dharaskar Building, Randaspeth, Nagpur-440010)	Carbaryl WDPC—(Ground Spray) IS : 7121—1973
52.	CM/L—9006 1980-09-24	80-10-01	81-09-30	Rako Mercantile Traders, B-2 Govt. Industrial Estate, Talkatora Road, Lucknow-226005, (U.P.)	Distemper dry, colour as required IS : 427- -1965
53.	CM/L—9007 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	Larsvin Engineers (P) Ltd., Plot Nos. 9 & 10, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad-500854, (M.P.)	33.3 litres capacity LPG cylinders as per drawing No. 4001 sheet No. 1/ CCE letter No. G-3 (42)/82 dated 80-09-11/18- IS : 3196 -1974
54.	CM/L—9008 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	Vee Kay Electricals, 15, 16, 17 Industrial Area, Jabalpur (M.P.) Office : 994, Wright Town, Jabalpur, (M.P.)]	PVC insulated and PVC sheathed cables with aluminium conductor for working voltages upto and including 1100 V (size upto 6.00 sq. mm)— IS : 694—1977
55.	CM/L—9009 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	Ichalkaranji Machine Centre Pvt. Ltd., 112, Industrial Estate, Ichalkaranji, (Maharashtra)	Cylinder liners for internal combustion engines, Type 'X' wet liner— IS : 6750 -1972

1	2	3	4	5	6
56.	CM/L—9010 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	Keltron Projectors Ltd., 1133 & 1134, Sasi Vihar, Peroorkada, Trivandrum-695005	16mm portable sound and picture cinematograph projector IS : 4497—1977
57.	CM/L—9011 1980-09-25	80-10-01	81-09-30	Hymatic Industries, 42, New Wazirpur Complex, Delhi-110052	Foot sprayer— IS : 3652—1974
58.	CM/L—9012 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	Electrical Machines Corporation, Block No. 28/2, Shree Industrial Mills Estate, Kalidas Mill Compound, Gomtipur, Ahmedabad-380021 (Office : Nirmal, 3rd Floor, Opp. Dinbai Tower, Laldarwaja, Ahmedabad-380001)	Rotating electrical machines 7.5 KW, 440 V, 2000 r.p.m. TEFC, Class F insulation continuous rating D.C. shunt motor IS : 4722—1968
59.	CM/L—9013 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	Bright Wires Limited, P O . Badu Pin Code No. 743202, Badu Road, Via Madhayamgram, 24-Parganas (West Bengal)	Steel wire for the core of galvanized steel reinforced aluminium conductor for over head transmission purposes IS : 398 (Part II) —1976
60.	CM/L—9014 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	Tropical Agrosystems (P) Ltd., 530/2B, Vanagram Road, Athipet, Madras-600058	Monocrotophos WSC— IS : 8074—1976
61.	CM/L—9015 1980-09-26	80-10-16	81-10-15	Punj Sons Pvt Ltd., Burma Mines Area, Jamshedpur-831007 (Bihar), [Office : 4A Royd Street, Calcutta-700016 (West Bengal)]	Unbonded rock and slagwool for thermal insulation type : 1— IS : 3677—1973
62.	CM/L—9016 1980-09-29	80-10-01	81-09-30	Steel & Metal Tubes (India) Pvt. Ltd., 22nd Mile Delhi Hapur Road, Village Galand , Distt. Ghaziabad	Mild steel tubes, black, screwed and socketed; Class-light; size-above 50mm NB upto and including 100mm NB IS : 1239 (Part I) —1979
63.	CM/L—9017 1980-09-29	80-10-16	81-10-15	Sindichem Ltd., Town Sindi, Tehsil & Dist. Wardha, (Maharashtra) [Office : Neelgiri Ramadaspeth, Nagpur-440010 (Maharashtra)]	Copper oxychloride 50% water dispersible powder concentrates— IS : 1507—1977
64.	CM/L—9018 1980-09-29	80-10-16	81-10-15	Madan Engineering Tool Products, B-26, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020	Steel butt hinges, Medium weight, cold rolled mild steel butt hinges Sizes : 75mm, 100mm and 125mm — IS : 1341—1976
65.	CM/L—9019 1980-09-29	80-10-16	81-10-15	Universal Steel & Alloys Ltd., Gurukul Indraprastha Industrial Estate, 12/6, Milestone Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003	Steel ingots for the production of laminated spring (railway rolling stock)— IS : 8054 -1976
66.	CM/L-9020 1980-09-29	80-10-16	81-10-15	Govt. of India Product Centre for Electric Motors, Tiruvalla-5 (Kerala)	Three-phase squirrel cage induction motors for centrifugal pumps for agricultural application 2.2 KW with class 'A' insulation— IS : 7538-1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
67.	CM/L-9021 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Aravali Chemical Laboratories G-464, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013 (Rajasthan)	Disinfectant fluid : Grade 3 Class A Type Normal— IS : 1061-1975
68.	CM/L-9022 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Krishna Paints & Chemicals Co , Bhuli Road, Wasseypur, Dhanbad (Bihar)	Enamel, interior, (a) undercoating, and (b) finishing — IS :133-1975
69.	CM/L-9023 1980-09-30	80-09-16	81-09-15	Steelcrete Pvt Ltd., Industrial Development Area, Gajuwaka, Visakhapatnam (Office : Steelcrete House, 3 Dinshaw Wachha Road, Bombay-400020)	Mild steel tubes, black with plain ends Size : upto and including 50 mm only— Class : Light— IS : 1239 (Part I) —1979
70.	CM/L-9024 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Gwalior Wire Products, 40 Industrial Estate, Gwalior-474004 (M.P.)	Aluminium stranded conductors and aluminium conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes — IS : 398-1976
71.	CM/L-9025 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Indian Pest Control Co , Plot No 1-A, Sector B, Govindpura, Industrial Area, Bhopal-462003 (M.P.)	BHC (HCH) DP - 1 IS : 561-1972
72.	CM/L-9026 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	S P Virmani & Sons Pvt Ltd , Jwala Flour Mills, Haripura, Amritsar-143003 (Punjab)	Compounded fees for cattle IS : 2052-1979
73.	CM/L-9027 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Golden Paints & Chemicals, Outside Chatiwind Gate, Kot Mahna Singh, Amritsar-143001 (Punjab)	Oil paste for paints, interior, white, types 1 & 2— IS : 96-1950
74.	CM/L-9028 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Nelco (India) Pvt Ltd , Baghpat Road, Meerut-250002	Discus Sizes 1 & 2 — IS : 4142-1967
75.	CM/L-9029 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Aquolac Paints, 70 Najafgarah Road, New Delhi-110015	Enamel, synthetic, exterior, undercoating only, colour category No -17 only— IS : 2932-1974
76.	CM/L-9030 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	-do-	Ready mixed paint, finishing interior for general purposes — IS : 3537-1966
77.	CM/L-9031 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	The scientific Insecticides Company, 447/1, Mangalagiri Road, Guntur-522001 (AP)	Carbaryl WDPC Grade Ground spray— IS : 7121-1973
78.	CM/L-9032 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Phoenix oil Co. (India) Pvt. Ltd., 488, Mirpur, Kanpur Cantt-208004 (U.P.) Office : Room No. 27 & 28, Moti Bhawan, Collectorganj, Kanpur (U.P.)	(i) Machinery oil-medium grade; (ii) Spindle oil—light grade —— IS : 493-1958
79.	CM/L-9033 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Ramakrishan Metal Works (Bombay), Plot No. C-33, Wagle Industrial Estate, Thane (Maharashtra)	Stainless steel sheets and coils— IS : 5522-1978
80.	CM/L-9034 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	M.M. Industries 138, Foresore Road, Ramkistopur, Howrah (West Bengal) (Office : 130, Cotton Street, Calcutta-700007)	Laminated jute bags for packing fertilizers— IS : 7406-1974
81.	CM/L-9035 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	Technico (India), 3, B.B. Ganguli Sreet, Calcutta-700 012 (W.B.)	Landing valves (Internal hydrant) Type 'A'— IS : 5290-1977
82.	CM/L-9036 1980-09-30	80-10-16	81-10-15	-do-	Branch pipe, universal for fire fighting purposes Type universal— IS : 2871-1964

[No. CMD/13:11]

A. P. BANERJI, Addl. Director General

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1983

का० आ० 4615.—भूमि के अधिग्रहण के लिए, कलक्टरों को आदेश देने के लिए, उप निदेशकों/कार्यपालक इंजीनियरों को प्राधिकृत करने वाली इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1983 की अधिसूचना सं 41 (19)/82-एफ० सी० में आंशिक आशोधन करते हुए, उक्त अधिसूचना में उल्लिखित प्रभागों के नामों में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन कर लिया जाए : —

(1) क्रम सं 19 में वाराणसी से पहले 'सं० I' में शब्द को निकाल दिया जाए ।

(2) क्रम सं० 21 को पूर्णतया निकाल दिया जाए ।

[सं० 44 (19)/82- एफ० सी०]
सी० एस० हुकमानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 16th November, 1983

S.O. 4615.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 44(19)/82-FC dated the 17th September, 1983 authorising Deputy Directors/Executive Engineers to direct the Collectors for acquisition of land, the following corrections deletions may be made in the names of Divisions mentioned in the Notification :—

(i) In Sl. No. 12, the word "NO" before "Agra" may be deleted ;

(ii) In Sl. No. 19, the word "NO. I" before "Varansi" may be deleted ;

(iii) Sl. No. 21 may be deleted completely.

[No. 44(19)/82-FC]
C. S. HUKMANI, Jt. Secy.

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलौर, 21 अक्तूबर, 1983

का० आ० 4616.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है ज उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
(1)	(2)
इंजीनियर : — जो सम्पदा प्रबन्धक के रूप में पदाभिहित किया गया है, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर	कर्णाटक राज्य में बंगलौर जिला में अंतरिक्ष विभाग और उसके केन्द्रों/यूनिटों के स्वामित्व में के या उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए या अधिगृहीत परिसर, जिनके अन्तर्गत भूमि और भवन, आवासीय कालोनियां हैं ।

[सं० 9/2(2)/82-III

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, the 21st September, 1983

S.O.4616.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises
(1)	(2)
Administrative Officer-II SHAR Centre, Department of Space, Sriharikota Range-524 124, Nellore District, ANDHRA PRADESH.	Premises including lands and buildings, housing colonies, owned by or taken on lease or requisitioned by the Department of Space and its centres/units at Sriharikota and Sullurpeta in the State of Andhra Pradesh, Balasore in the State of Orissa and Madras City in the State of Tamil Nadu.

[No. 9/2(2)/82-III]

का० आ० 4617—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
(1)	(2)
प्रशासन अधिकारी-II शार केन्द्र, अन्तरिक्ष विभाग, श्रीहरिकोटा रेंज 524124, नेल्लोर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।	आन्ध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा और सुल्लुरपेटा, उड़ीसा राज्य में बालासोर और तमिलनाडु राज्य में मद्रास नगर में स्थित अन्तरिक्ष विभाग और उसके केन्द्रों यूनिटों के स्वामित्व में है या उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए या अधिगृहीत परिसर, जिनके अन्तर्गत भूमि और भवन, आवासीय कालोनियां है ।

[सं० 9/2(2)/82-III]
पी. आई. यू नम्बियार, उप सचिव

S.O. 4617.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below bring an officer equivalent to the rank of gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises
(1)	(2)
Engineer designated as Estate Manager, Civil Engineering Division, Department of Space, Bangalore.	Premises including lands and buildings, housing colonies owned by or taken on lease or requistioned by the Department of Space and its centres/units in Bangalore District in the State of Karnataka.

[No. 9/2(2)/33-III]
P.I.U. NAMBIAR, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवंबर, 1983

का० आ० 4618—केन्द्रीय सरकार, वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उपनियम (2 क) के अनुसरण में प्रादेशिक वायु सुरक्षा नियंत्रक और वायु सुरक्षा अधिकारी के कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नागर विमानन प्राधिकृत करती है और भारत सरकार के पर्यटन और मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3562 तारीख 29 सितम्बर, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में प्रथम अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी अर्थात:—

(1)	(2)
"प्रादेशिक वायु सुरक्षा नियंत्रक	44, 45
वायु सुरक्षा अधिकारी	44"

[फा० सं० एवी-11012/2/81-ए]

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 24th November, 1983

S.O. 4618.—In pursuance of sub-rule (2A) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby authorises the Regional Controller of Air Safety and Air Safety Officers to exercise certain powers and makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 3562 dated the 29th September, 1976, namely :—

In the said notification, after the existing entries to the First Schedule, the following entries shall be added namely :—

1.	2
"Regional Controller of Air Safety	44, 45.
Air Safety Officer.	44.

[F. No. Av. 11012/2/81-A]
B. N. JHA, Dirertor

का० आ० 4619.—केन्द्रीय सरकार, वायुयान नियम, 1937 के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसरण में प्रादेशिक वायु सुरक्षा नियंत्रक और वायु सुरक्षा अधिकारी को कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है और भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ 3563, तारीख 29 सितम्बर, 1976 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"प्रादेशिक वायु सुरक्षा नियंत्रक	2, 10
वायु सुरक्षा अधिकारी	2, 10"

[फा० सं० एवी० 11012/2/81-ए]
बी०एन० झा, निदेशक

S. O. 4619.—In pussuance of sub-rule (2) of rule 3 of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby authorises the Regional Controller of Air Safety and the Air Safety officer to exercise certain powers and makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministryr of Tourism and Civil Aviation No.S..O. 3553 dated the 29th September, 1976 namely :—

In the said notification, in the First Schedule, after the existing entries, the following entries shall be added namely :—

1	2
"Regional Controller of Air Safety	2,10
Air Safety Officer	2,10"

[F.No. Av.11012/2/81-A]
B. N. JHA, Director

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1983

का० आ० 4620:—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 18-5-1977 के पृष्ठ 1916 से 1921 पर प्रकाशित भारत सरकार, के संचार मंत्रालय (डाक-तार बोर्ड) की अधिसूचना सं० का० आ० 1576, तारीख 12-5-1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में क्रम संख्या 66 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थान
67.	प्रभागीय इंजीनियर फोन्स (प्लानिंग) जिला प्रबन्धक का कार्यालय टेलीफोन आगरा ।	आगरा की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक आगरा टेलीफोन के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन स्थान ।
68.	प्रभागीय इंजीनियर फोन्स जिला प्रबन्धक का कार्यालय टेलीफोन जालन्धर ।	जालन्धर की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक जालन्धर टेलीफोन के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन स्थान ।
69.	प्रभागीय इंजीनियर फोन्स (II) जिला प्रबन्धक का कार्यालय टेलीफोन वाराणसी ।	वाराणसी की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित जिला प्रबन्धक वाराणसी टेलीफोन के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन स्थान ।
70.	उप महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक का कार्यालय, उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद ।	गाजियाबाद की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित महाप्रबन्धक, डाकतार उच्चस्तरीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद के प्रशासनिक नियन्त्राधीन स्थान ।

[संख्या 2-209/73-एन०बी०]

एम. कृष्णन, निदेशक स्टाफ (दूरसंचार)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 14th November, 1983

S.O. 4620.—In exercise of the power conferred by section 3 of the public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs Board) No. S.O. 1576, dated the 12 th May, 1977 published at pages 1916 to 1921 of the Gazette of India, Part II-Section 3 Sub-section (ii), dated the 28th May, 1977 namely:—

In the Table below the said notification after serial No. 66 and the entires relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Designation of Officer	Public premises
1	2	3
67.	Divisional Engineer Phones (Planning) Office of the District Manager, Telephones, Agra.	Premises under the administrative control of the District Manager, Agra Telephones situated within the local limits of Agra.
68.	Divisional Engineer Phones. Office of the District Manager, Telephones, Jullundur.	Premises under the administrative control of the District Manager, Jullundur Telephones, situated within the local limits of Jullundur.
69.	Divisional Engineer phones (II) Office of the District Manager, Telephones, Varanasi.	Premises under the administrative control of the District Manager, Varanas Telephones situated within the local limits of Varanasi.
70.	Deputy General Manager, Office of the General Manager, Advanced Level Telecom. Training Centre, Ghaziabad.	Premises under the administrative control of the General Manager, Posts & Telegraphs Advance Level Telecom. Training Centre, Ghaziabad situated within the local limits of Ghaziabad.

[No 2-209/73-NB]

S. KRISHNAN, Director (ST)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4621.—अस्थायी आदेश संख्या 627 दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खण्ड III के पैरा (क) अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने अरामबोली टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-1-84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/83-पी० एण्ड०बी०]

New Delhi, the 3rd December, 1983

S.O. 4621.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-1-1984 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Aramboly Telephone Exchange Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4|83-PHB]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4622.—स्थायी आदेश संख्या 627 दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने साथियामंगलम/भवानिसागर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-12-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-4/83 पी० एण्ड० जी०]

त्रिलोकी नाथ, सहायक महानिदेशक
(पी० एण्ड० बी०)

New Delhi, the 6th December, 1983

S.O. 4622.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 16-12-1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sathiamangalam|Bhavani Telephone Exchange Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4|83-PHB]

TRILOKI NATH, Asstt. Director General (PHM)

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 3rd December, 1983

S.O. 4623.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of New Bank of India and their workmen, which received by the Central Government on the 25th November, 1983.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI.

I.D. No. 39 of 1983

In the matter of disputes

BETWEEN

Shri Vindya Saran Singh C|o Shri Dwarka Prasad Shukla, 2 Navin Market, Kanpur.

AND

New Bank of India H.O.1, Tolstoy Marg, New Delhi.

PRESENT :

Mr. N. C. Sikri—for the Management.
None—for the Workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12025|33|81-D.II.A. dated 22nd April, 1982 made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the Management of New Bank of India in terminating the services of Shri Vindya Saran Singh, Clerk-cum-Godown Keeper, Khatoli Branch, with effect from 24-10-79 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. In his Statement of Claim, the workman claimed that he was appointed as Clerk-cum-Godown Keeper by the New Bank of India at Khatauli Branch on probation for a period of six months and he joined duty on 24-1-79, but his services were terminated on 24-10-79 and that the ground to terminate him was that he has not come up to the desired standard which was not explained to him at any stage and claimed that the Bank violated the provisions of Section 25-G and H of the Industrial Disputes Act, because new hands have been recruited after terminating his services and that the termination was not on the ground of misconduct.

3. The Management raised preliminary objections and on facts pleaded that Mr. Singh's services were terminated in accordance with the term of service and after paying retrenchment compensation under Section 25-F of the Industrial Disputes Act, 1947 and that he was not entitled to any relief.

4. Shri V. V. Mangalvadekar appeared for the employee at one stage and the workman appeared himself on 19-4-83, but the workman has failed to appear thereafter and Shri Mangalvadekar pleaded lack of instructions. It appears from the written statement filed by the Management that his case is one where Section 25-F of the Industrial Disputes Act has been complied with and the termination of services is justified and the workman is not entitled to any relief.

5. Accordingly, the award is made in the terms aforesaid.

November 10, 1983.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12025|33|81-D.II(A)]

S.O. 4624.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, in the Industrial Dispute betwen the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th November, 1983.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case No. I. D. 65|83—125|81.

PARTIES :

Employers in relation to the management of the State Bank of Patiala, Punjab.

AND

Their Workman—Prakash Chand.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. K. Gupta.
For the Workman.—Shri T. C. Sharma.

State Bank of Patiala State—Punjab

AWARD

Dated, 23rd of November, 1983

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, vide their Order No.. L-12012|302|80-D.II.A. dated the 25th of August, 1981 read with S.O. No. S-11025(2)|83 dated the 8th of June 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of State Bank of Patiala in relation to its Br. at Industrial Area, Mansa in promoting Shri K. K. Mittal, Clerk-cum-Cashier, as Head Cashier Category 'B' under letter No. GEM/276 dated 28-9-1979 in preference to Shri Prakash Chand, Clerk-cum-Cashier is justified ? If not, to what relief is Shri Parkash Chand entitled ?"

2. On having taken up an alternative job of comparatively lucrative nature the petitioner|Workman is no longer interested in persuing his cause as would be evident from the statement of his authorised representative taken down by me on the records of the case.

3. Accordingly, on the request of the parties, I hereby return a No-dispute Award.

I. P. VASISHT, Presiding Officer

Chandigarh,
the 23rd November, 1983.

[No. 12012|302|80-D.II(A)]

S.O. 4625.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Patiala and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th November, 1983.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case. No. I.D. 62/83—121/83

PARTIES :

Employers in relation to the Management of the State Bank of Patiala—Punjab.

AND

The Workman—Soorvir Singh.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. K. Gupta.

For the Workman—Shri T. C. Sharma.

State Bank of Patiala State—Punjab.

AWARD

Dated 23rd of November, 1983

The Central Government Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No. L-12012(278)|81.D.II(A) dated the 10th of June 1982 read with S.O. No. S-11025 (2)|83 dated the 8th of June 1983, referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of Patiala in not allowing the opportunity of re-employment to Shri Soorvir Singh retrenched workman is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. On having taken up an alternative job of comparatively lucrative nature the petitioner-workman is no longer interested in persuing his cause as would be evident from the statement of his authorised representative taken down by me on the records of the case.

3. Accordingly, on the request of the parties I hereby return a No-dispute Award.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

Chandigarh.

23rd November 1983.

[No. L-12012|218|81-D.II(A)]

New Delhi, the 5th December, 1983

S.O. 4626.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in relation to the Punjab National Bank, and their workmen which was received by the Central Government on the 30th November, 1983.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI.

I.D. No. 42 of 1981

In the matter of disputes

BETWEEN

Shri Gobind Singh through PNB Workers' Organisation, 898, Nai Sarak, Chandni Chowk, Delhi.

AND

Punjab National Bank, Head Office, Parliament Street, New Delhi.

PRESENT :

Shri C. L. Bhardwaj—for the workman.

Shri Arun Verma—for the Management with Shri Mohar Singh.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012|100|80-D.II.A. dated 24th March, 1981, made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Parliament Street, New Delhi (1) in not absorbing Shri Gobind Singh As Cook|Waiter in Officers Canteen; (2) in not giving him benefits as such and (3) in terminating his services with effect from 11-4-78 was justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Gobind Singh, the workman, claimed that he was appointed as a Cook|Waiter without any appointment letter and|or written orders by the Punjab National Bank, New Delhi in the Officers Canteen (Mess) from 30-1-78 to 10-4-78 and his services were terminated w.e.f. 11-4-78. He claimed that he attended office from 8.00 A.M. till 5.30 P.M. during this period and he was required to bring necessary cooking and eating materials from the market for use in the Officers Canteen (Mess). He was not paid wages payable to a member of subordinate cadre, but was paid Rs. 10 per day for only 5 or 7 days as and when some outsiders' parties were at the Mess. On 10-4-78, he requested the Mess Incharge to pay him full wages for the whole period, but instead of doing so, he advised him not to come to the Mess thereafter. His case is that he is a 'retrenched' employee entitled to employment in place of those persons who were taken by the Bank later in service, namely, Bhagat Singh, Rajinder Parsad and Malu Ram, who came later.

3. The Management contested the workman's claim and asserted that Gobind Singh was not appointed as a Cook/Waiter, but was only used on casual basis as a Coolie to bring vegetables etc. from the market and he paid Rs. 10 per day for the days he actually worked, when there were outsiders parties and did sot work other days and he was not even a temporary employee and was not entitled to re-employment because the posts filled in were those of Cooks or Waiters and he never worked as a Cook or Waiter, but only as a Casual employee to work as a Coolie.

4. The following issue was framed:—

(1) As in terms of Reference.

5. The workman gave his own affidavit and he has been cross-examined and Shri V. N. Gupta, Accountant, Finance & Taxation Division, Head Office, New Delhi gave his affidavit on behalf of the Management and he has been cross-examined. I have heard the representatives of the parties. Written arguments filed by the Bank have also been perused.

6. It is an admitted case that Gobind Singh has been paid at the rate of Rs. 10 per day and he has been paid only for 5 or 7 days during the period 30-1-78 to 10-4-78 and has not been paid for any longer period. Gobind Singh has not filed any L.C.A. under Section 33-C (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 claiming wages for the remaining period during 30-1-78 to 10-4-78. These facts clearly go to show that he was engaged as casual labourer only for 5 or 7 days when there were outsiders parties, as a Coolie to bring vegetables from the market and was not engaged as a Cook or Waiter and he does not have any diploma in Cooking with him.

7. The Management engaged Malu Ram and Bhagat Singh as Cooks|Waiters and not as coolies and therefore, there is no question of employment of Gobind Singh by the Management of the Bank in those posts.

8. On the facts of this case, it is, therefore, unnecessary to examine the full meaning of retrenchment in respect of operation of Section 25-F of the I.D. Act when the facts do not disclose a case of appointment to the post of a Coolie in the Bank, when the Workman, Gobind Singh was employed only as a coolie in the Officers Canteen (Mess) to bring vegetables as a casual labourer and never worked continuously even for a week. He has been paid wages at the rate of Rs. 10 for each of the days he worked as coolie.

9. The factual situation militates against the case set up by the workman for working as a Cook|Waiter and disentitles him to any relief. The Action of the Management of the Bank appears justified.

November 25, 1983.

O. P. SINGLA, Presiding Officer,

[No. L-12012(100)|80-D.II.A]

New Delhi, the 8th December, 1983

S.O. 4627.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Hindustan Commercial Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Givernment on the 3rd December, 1983.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI.

I.D. No. 177 of 1983.

In the matter of disputes between :

Shri Shatrughan Singh, Sub-staff through Hindustan Commercial Bank Employees Congress, 8|75 Arya Nagar, Kanpur.

Versus

Hindustan Commercial Bank Limited, H.O. Birhan Road, Kanpur.

PRESENT :

Shri Umesh K. Saxena with Shri Parbhat Shukla—for the Management.

None—for the Workman.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012|141|82-D.II(A) dated 11th April, 1983 made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Limited, Head Office Kanpur, in not promoting Shri Shatrughan Singh, sub-staff as Cashier-cum-Godown Keeper with effect from 23-7-1980 is justified ? If Not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. The workman concerned has already been promoted w.e.f. 22-3-82 as Cashier-cum-Godown Keeper and a statement to this effect has been made by the Bank's representative today and the dispute has been mutually resolved between the parties. The workman for that reason has not appeared. Therefore, a 'No Dispute Award' is made.

November, 28 1983.

[No. L-12012|141|82-D.II(A)]

O. P. SINGLA, Presiding Officer

S.O. 4628.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 2nd December, 1983.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

Reference No. 30 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Calcutta.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. N. V. Sundaram, Principal Legal Adviser.

On behalf of Workmen.—Mr. N. Mitra, Vice-President of the Reserve Bank Staff Association, 105-Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-16.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12012/162/82-D.II(A) dated 4 May 1983 the Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour in the Government of India referred the following dispute to this Tribunal for adjudication —

"Whether the action of the management of the Reserve Bank of India, Calcutta in (i) making deductions from the wages of Shri Hem Chandra Roy, Pharmacist for the period from 6-6-81 to 17-2-82, (ii) deferring his confirmation as Pharmacist, and (iii) treating certain days as leave granted to him on 16-6-80 and on certain days during the period 19-6-80 to 24-6-80 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. At the first hearing on 3 October 1983 Sri N. V. Sundaram appearing for the management raised a preliminary objection that the dispute in the present case is not an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 because it has not been espoused by an Association having a representative capacity amongst class III employees of the Reserve Bank at Calcutta. He submitted that the Reserve Bank of India Staff Association has not worthwhile following amongst class III employees of the Bank. He pointed out that there are two recognised unions o fthe bank, one of class III employees and another of class IV employees, that the Reserve Bank of India Staff Association, Calcutta is an unrecognised union, consisting of two factions which are operating under the same registration number, that the present dispute has been espoused by only one faction of the said staff Association functiong at Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta, its General Secretary being Susil Kumar Das. This preliminary objection was also taken in the written statement of the management dated 13 July 1983. The Staff Association led by Sri S. K. Das took time twice to file their written statement but it has not been filed. They are local men but still they did not choose to appear on 3 October 1983 before this Tribunal. Sri N. V. Sundaram who came from Bombay for the purposes of this very case was heard on preliminary objection. He submitted that a copy of the written statement of the workmen was served upon the management and that the statement of claim was signed by Susil Kumar Das himself. He urged that nothing had been said in that statement or claim about the locus standi of the Staff Association to represent the concerned workman, namely, Hem Chandra Roy, Pharmacist. He also drew my attention to an award passed by Sri S. K. Mukherjee, the then Presiding Officer of this Tribunal in Reference No. 14 of 1977 dated 3 December, 1979 in which it was held that the other faction of the identical Staff Association led by Sri A. K. Roy lacked representative character and was not competent to represent the concerned workman and therefore there was no industrial dispute and the reference was incompetent. Order on preliminary objection was to be passed next day.

3. But on the next day (4 October 1983) Sri A. K. Roy, the general Secretary of the other faction of the Staff Association appeared and desired to be added as party and to be heard. This faction had not raised the dispute was not a party at the conciliation stage nor a party to this reference. Hence by order dated 22 October 1983 this Tribunal rejected his prayer. In the meantime a letter was received from Sri S. K. Das, the General Secretary of the other faction who is party to this reference for being heard. So this case was adjourned to 23 November 1983 for hearing him. On that day both Sri S. K. Biswas, Personnel Officer of the Bank and Sri N. Mitra, Vice-President of the Staff Association were heard on the point of locus standi. Sri S. K. Biswas adopted the argument of Sri N. V. Sundaram which had been advanced earlier on 3 October 1983. Sri Mitra for the Union strongly argued that the Staff Association is a registered trade union and therefore it has locus standi to represent the concerned workman. He further submitted that the Government of India in the Ministry of Labour has referred this dispute for adjudication and therefore there is presumption of industrial dispute and hence the reference is competent. In my opinion his submission is not

helpful. As held in Reckitt & Colman V Fifth Industrial Tribunal, Calcutta, 1980 Lab. IC 92 (Cal) the presumption is rebuttable. When the locus standi of the Union is challenged, I think the union is bound to produce relevant evidence and to establish the fact that it is entitled to represent the concerned workman. Onus is on the Union to prove it. It is not sufficient to show that the Union is registered under the Trade Union Act, vide Deepak Industries Ltd. v. State of West Bengal, 1975 Lab. IC 1153 (Cal). So the point raised by Sri N. Mitra has no force. In this case the Union has not adduced any evidence oral or documentary to establish their locus standi.

4. Sri S. K. Biswas the Personnel Officer of the management drew my attention to the fact that out of the three matters mentioned in the reference issue only one (relating to deduction of his wages) now remains for adjudication because Mr. Hem Chandra Roy the Pharmacist has already been confirmed and the six days in question which had been treated as leave have also been treated as on duty. He submits that wages were rightly deducted due to his regular absence from duty hours and on Saturdays as proved by the record. It was also submitted that Mr. Hem Chandra Roy had filed a writ petition regarding the staggering of the duty hours which was subsequently withdrawn. In the view which I have taken about this case regarding the locus standi of the splinter Staff Association, it is not necessary to go into all these matters.

5. In the present case, as already observed, the splinter Association has not chosen to adduce any evidence and to prove their competency to represent the concerned workman. In this state of things, I would hold that the Staff Association has not been able to establish its representative character. It must, therefore, be held that there is no Industrial dispute and the reference is incompetent.

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 25th November 1983.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-12012/162/82-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer.

New Delhi, the 5th December, 1983

S.O. 4629.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bejdih-Methani-Patmohana Collieries of Messrs Eastern Coalfields Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st December, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD.

Reference No 20/82.

PRESENT :

Shri J. N. Singh—Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bejdih-Methani-Patmohana Collieries of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O. Sitarampur, Dist. Burdwan.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman.—None.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dhanbad, the 25th November, 1983

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has forwarded the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(74)/81-D. IV(B) dated the 27th February, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the Agent, Bejdih-Methani-Patmohana Collieries of M/s. E. C. Ltd., P. O. Sitarampur, Dist. Burdwan in not regularising Shri Mahendra Singh Munshi from 25-5-76 is justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. On 21-11-1983 a petition has been filed by the Organising Secretary of the sponsoring union stating that the concerned workman and the union are no longer interested in the dispute and it is prayed that a no dispute award may be passed in this case.

3. Accordingly a 'no dispute' award is passed in the present case in terms of the above petition dated 21-11-1983.

J. N. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-19012(74)/81-D. IV (B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer.

आदेश

नई दिल्ली, 6, दिसम्बर, 1983

का० आ० 4630—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3453 तारीख 22 सितम्बर, 1967 द्वारा गठित श्रम न्यायालय (मुख्यालय नागपुर) के पीठासीन अधिकारी का एक पद रिक्त हुआ है।

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री जी. एच. कदम को उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[एफ. सं० एस-11020/1/81-डी-1) (ए)]

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1983

S.O. 4630.—Whereas a vacancy has occured in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Nagpur constituted by the Notification of the Government of India in the then Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation No. S. O. 3453 dated the 22nd September, 1967;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri G. H. Kadam, as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

[No. S-11020/1/81-D. I. (A)]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4631—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा अयस्क खनन उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम सूची के मध्य 16 में शामिल है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रयोग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/8/81-डी-1(ए)]

एस० एच० एस० अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 9th December, 1983

S.O. 4631.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Iron Ore Mining Industry, which is covered by item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017(8)/81-D. I(A)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4632—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री ए० सी० श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, खान सुरक्षा (पूर्वी जोन) को, श्री एच० एस० आहूजा, जो छुट्टी पर गए हैं, के स्थान पर उन सभी क्षेत्रों के लिए, जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार है, 12 दिसम्बर, 1983 से अगले आदेश जारी होने तक मुख्य खान निरीक्षक होने के लिए नियुक्त करती है।

[एफ० सं०-ए-24011/1/83-एम आई]

जे० के० जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 12th December, 1983

S.O. 4632.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri A. C. Srivastava, Deputy Director General of Mines Safety (Eastern Zone), to be the Chief Inspector of Mines for all the territories to which the said Act extends from 12th December, 1983 until further orders, vice Shri H. S. Ahuja proceeded on leave.

[F. No. A-24011/1/83-MI]

J. K. JAIN, Under Secy.

New Delhi, the 12th December 1983

S.O. 4633.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Sone Valley Portland Cement Company Limited, Baulia and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th December, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha,

Presiding Officer.

Reference No. 140 of 1982

In the matter of an industrial disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act. 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs Sone Valley Portland Cement Company Limited, Baulia.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers.—Shri H. Tiwary, Chief Personnel Manager, Limestone Quarry Baulia of M/s. Sone Valley Portland Cement Co. Ltd.

On behalf of the workmen.—Shri Jadubansh Singh, General Secretary, Baulia Quarries Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Limestone.

Dhanbad, the 30th November, 1983

AWARD

This is an industrial dispute under Section 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its Order No. L-29011/23/82-D. III(B) dated 1st December, 1982 has referred the following dispute for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Baulia Limestone Quarry of Messrs Sone Valley Portland Cement Company Limited, Post Office Baulia (Rohtas) in not granting Casual Leave for 7 days with pay in a year to the workers on labour roll is justified ? If not to what relief are the workmen entitled ?"

Soon after the receipt of the reference notices were sent to the parties for filing their written statement. Thereafter a few adjournments were granted to the parties for filing their respective written statement and rejoinder along with documents. Ultimately on 28-11-83 both the parties appeared and filed a memorandum of settlement, in terms of which the management agreed to allow 7 days casual leave to all permanent workers in a Calendar year starting from 1-1-1983. I find that the terms of settlement are fair and proper and beneficial to both the parties and I accept the same. I therefore, pass an Award in terms of the settlement. The settlement will form part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Officer.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) NO. 2, DHANBAD.

Ref. No. 140/82

The Management of Limestone Quarry Baulia of M/s. Sone Valley Portland Cement Co. Ltd.,

V/s.

Workmen represented through Baulia Quarries Mazdoor Sangh.

The humble joint petition on behalf of the above named parties.

Most respectfully sheweth :—

1. That the Government of India Ministry of Labour have referred the dispute vide order No. L-29011/23/82-D.III(B) dated 1st Dec. 1982 on the demand made by the General Secretary, Baulia Quarries Mazdoor Sangh.
2. That the above referred dispute stands settled vide clause 6 of the settlement arrived between the parties dated 12-7-82.
3. That in view of the facts mentioned above, we request your goodself to pass an award in terms of the settlement.

And for this the petitioners shall ever pray.

(H. Tiwary)

Chief Personnel Manager.

Limestone Quarry Baulia of
M/s. Sone Valley Portland Cement Co. Ltd.
Dated.—28-11-83.
(Jadubansh Singh)
General Secretary
Baulia Quarries Mazdoor Sangh
28-11-83.

Memorandum of Settlement signed between the Management of Sone Valley Portland Cement Co. Ltd. Baulia Limestone Quarries and Baulia Quarries Mazdoor Sangh during the course of conciliation proceedings held by the Assistant Labour Commissioner (Central), Patna, Government of India, at Calcutta on 12th July, 1982, under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Parties Present

Management :

1. Shri K. P. Singh,
   President of the Company.
2. Shri Harihar Tiwari,
   Personnel Manager.
3. Shri A. P. Singh,
   Supdt. of Mines.

Union :

1. Shri Surai Singh,
   Vice President.
2. Shri J. B. Singh,
   General Secretary.

Short Recital of the Case :—

The Union, i.e., Baulia Quaries Mazdoor Sangh, Vide its letter No. US. 8/82 dated 28-1-82, approached the Assistant Labour Commissioner(C) with a Charter of Demands containing 9 items. The Management and the Union sat together number of times in presence of the ALC(C) and separately also to bring about an amicable settlement. In all the sittings the Management has stressed that it is beyond their capacity to pay the awarded rate of wages because of the bad financial position. If wages of terminated Arbitrator's Award is implemented, it will be an extra burden of Rs. 5 crores a year to the Management, which possibly the Management is unable to bear and the Company will have to close down the establishment because of financial bankruptcy which will lead to the unemployment of all the workman working in Japla Cement Factory and its Limestone Quarries at Baulia. The ALC(C) on this argument of the Management quoted the advice of the Labour Secretary Govt. of Bihar communicated vide his letter No. 3/DOI-102/82-1042 dated 8-6-1982, which will untimately give an impact of atleast Rs. 1 1/2 crores in the first year and progressively more during subsequent years on this issue the Management said that their financial positions are not permitting to carry such a heavy burden and they are not legally bound to accept the advice of the Government of Bihar, but for maintenance of industrial peace and healthy industrial relations agreed to abide by the advice of the Labour Secretary Govt. of Bihar. The Union states that the company has the capacity to implement the Award of the Board of Arbitrators for Cement Industry. The ALC(C) then advised the Management to be generous over the workers of Baulia Quarries also. In this connection it is pertinent to mention here that on 1-7-1982 both the parties requested the ALC(C) to be present at Calcutta to bring about an amicable settlement which the ALC(C) Patna had to agree seeing the gravity of the situation prevailing at Baulia.

However, on persuation of the ALC(C) Patna, both parties agree to settle the dispute amicably on following terms :—

Terms of Settlement :—

1. (a) The Management agreed that the wages of the terminated Award of the Arbitrator shall be implemented with effect from 1-6-82 without prejudice to the Case No. CWWC 21/79(R) pending before the Hon'ble High Court, Patna-Ranchi Bench, against the Arbitrator's Award of 1978 as also to the claim of the Union for Interim Relief awarded by the new Board of Arbitrators and impending final award.

1. (b) It is agreed between the parties that the terminated Award of the Arbitrators shall be implemented phase-wise in respect of each worker of the Baulia Quarries excepting the erstwhile workers of the Co-operative Society for whom separate mutual settlement has already been signed on 16-12-81 and which is in operation. The workmen will be paid following increased emoluments per month.

(i) Rs 125.52 p will be paid per worker in respect of difference of V.D.A. from 1-6-1982.

(ii) Rs. 45.00 p. will be paid per worker in respect of difference of wages from 1-8-1983.

(iii) Rs. 63.00 p will be paid per worker in respect of difference of wages from 1-8-1984.

(iv) Rs. 71.02 p will be paid per worker in respect of difference of wages from 1-8-1985.

(c) It is further agreed that any rise or fall in the V.D.A shall be adjusted accordingly, i.e., Rs. 1.30 p per point rise/fall in the cost of living index (Base : 1960).

2. The case No. 27/81 on the subject is pending before the Labour Court Patna. However, the Management agreed to pay arrear wages to the Security Personnel and workers engaged in Sanitation for the period, as a matter of fair deal before 30th September 1982. Regarding other workers, the matter shall be mutually discussed between the Management and the Union.

3. It is agreed between the parties that deserving cases shall be decided on humanitarian ground in consultation with the Union.

4. It is agreed that the arrear Quarters' rent deducted shall be paid back to the workers within 1982.

5. (a) The Management agreed to withdraw their pending writ applications of the arrear Bonus cases from Hon'ble Patna High Court, i.e., for the year 1974, 1976, 1977 and 1978.

5. (b) The management further agreed that the Bonus for the accounting year 1974, 1976, 1977 and 1978 shall be paid as follows—

(i) 1974 Bonus will be paid by November, 1982.

(ii) 1976 & 1977 Bonus will be paid by November, 1983.

(iii) 1978 Bonus will be paid by November, 1984.

6. It is agreed that the Management shall allow 7 days Casual leave to all permanent workers in a Calendar year starting from 1-1-1983.

7. It is agreed that to honour the mutual settlement dated 16th December, 1981 the Management will absorb 90 workman (65 from mines faces, i.e. 54 workers from Jugar and one each from Mate, Munshi, Tramline Mistry, Tramline Khalasi, Drillers Blasters, Oilman Water-carriers, Peons, Trolleyman and Haulage drivers subject to adjustment by mutual discussion between the parties and 25 from surface) of the erstwhile Baulia Co-operative Society against permanent vacancies in the first phase on the basis of seniority/suitability in the different categories. As regards absorption of others against permanent vacancies within to stipulated period of settlement dated 16-12-81 the matter shall be mutually discussed and settled. It is also agreed that it will not affect adversely the case pending before Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in ref. 32/77.

8. The Management agrees that principles followed at Japla shall also be followed at Baulia in case of date of retirement of workmen.

9. It is agreed that the question of permanency of workmen shall be governed as per certified standing orders applicable at Baulia Quarries.

Both parties agreed to submit implementation report phase-wise till this settlement is implemented in letter and spirit. The final implementation report shall be submitted latest by 1-9-1985 to the ALC(C) Patna, failing which it will be presumed that terms of the settlement have been implemented.

Representing the Management	Representing the Workmen
1. Sd/- K. P. Singh	1. Sd/- Suraj Singh
President of the Company.	Vice President
2. Sd/- Harihar Tewari	2. Sd/- J. B. Singh
Personal Manager	General Secretary
3. Sd/- A. P. Singh	
Supdt. of Mines.	

Sd/- M.J. Mirza

Assistant Labour Commissioner(c)

Chief Personal Manager	GenerlSecretary
Sone Valley Portland Cement	Baulia Quarries Mazdoor
Co. Ltd.	Sangh
Witness	Wintess

[No.L-29011/23/82-D.III B]

New Delhi, the 15th December, 1983

S.O. 4634.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Associated Cement Companies Limited, Madukkarai, Coimbatore District, Tamil Nadu and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th December, 1983.

BEFORE THIRU T. ARULRAJ, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMILNADU, MADRAS

(Constituted by the Government of India)

Friday, the 25th day of November, 1983

Industrial Dispute No. 28 of 1982

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Messrs Associated Cements Companies Limited, Madukkarai.)

BETWEEN

Shri Jayes, No. 4, Kuppuswamy Gounder Street, Ward No. 11, K. K. Pudur, Sai Baba Colony, Coimbatore 641038.

AND

The Manager, Messrs Associated Cement Companies Limited, Madukkarai-641105, Coimbatore District.

REFERENCE:

Order No. L-29025(1)/82-D.III(B), dated 4th June, 1982, Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 16th day of November, 1983 upon persuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru R. Arumugham, for Thiruvalargal Aiyar and Dolia and R. Arumugham, Advocate for the workman and of Thiruvalargal T. S. Gopalan, P. Ibrahim Kalifulla and S. Ravindran, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This dispute arises out of a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in Order No. L-29025(1)/82-D.III(B), dated 4th June, 1982 of the Ministry of Labour against the termination of the services of the Petitioner Shri Jayes (John Samuel), Mines Surveyor, with effect from 10th April, 1981.

(2) According to the allegations in the claim statement and reply statement, the Petitioner Shri Jayes (John Samuel) was employed in the Respondent's Firm on 1-11-1960 as permanent Way Inspector at the Kymore Cement Works on a monthly salary of Rs. 158/-. Later he was transferred to Shahabad and later, on 22-7-1963 he was transferred to Madukkarai ement Works. He was then promoted as Mine Surveyor on 1-11-1966 for Madukkarai, Walayar and Ettimadai Limestone Mines. The major work was to make a spot inspection to study the latest position of the Mines and prepare the plan which requires lot of clerical and technical duties. He has to prepare the plan and update the plan. Whenever the Petitioner arrives in a particular mine for the preparation of the plan or update the plan, the people in that particular mine will render assistance to him. He has no control over them and further he is not handling anything which is very so confidential in nature. Thus the nature of work performed by the Petitioner and the nature of responsibilities of the Petitioner will show that he is a workman. It is not correct to say that the nature of his work is of a supervisory capacity. In 1970, he was ordered to go to other mines situated at Shahabad, Wadi Mancherial, Sitarampuram, etc., belonging to the Respondent-Company for surveying those mines, in addition to the mines at Madukkarai, Walayar and Ettimadai after obtaining necessary permission from the Directorate of Mines, as laid down in the Mines Act, 1952 and Mettaliferous Mines Regulations, 1961. After 1976, the Petitioner was asked to shoulder more responsibilities by being entrusted with the surveying work for more than 30 mines scattered all over India owner by the Respondent. It is against Mines Act and Mettaliferrous Mines Regulations, 1961. Because of the heavy schedule of work and the frequent travel from one place to another, he developed rheumatoid Arthritis. Hence, he has to address the Management that if the Management is not willing to keep him in Madukkarai without giving the touring assignments, he would like to opt for premature retirement under Company's Voluntary Retirement Scheme But to the surprise and shock of the Petitioner, he received the order of termination dated 10-4-1981 stating that he was retired from the Respondent's services on medical grounds with immediate effect. It is incorrect to state that the Petitioner was suffering from Arthritis even while he was at Madukkarai and not necessarily during traveling only and he was not physically fit for the job of a Mines Surveyor which involves extensive travelling. The Chief Medical Officer failed to notice the relevant rules that "one Surveyor for one Mine" and has given his opinion on false assumption that the Surveyor's work involves extensive travelling which is absolutely wrong. Therefore the entire opinion given by the Medical Officer is wrong and the order based upon that wrong opinion is also illegal and invalid one. The continued ill health is different from physically unfit to carry out the work. The Respondent has no right to terminate the services of the Petitioner who is a workman under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act 1947 without any prior enquiry nor it is governed under the terms of contract of employment for abrupt termination on medical grounds. The Petitioner never accepted his termination and the amounts were accepted by him under protest. It is incorrect and false to state that the termination of the Petitioner's services on medical grounds was bona fide, justified and valid in law and the same is not liable to be interferred with. In any event, this termination amounts to retrenchment as contemplated under Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. In as much as the condition precedent contemplated by Section 25-F of the Industrial Disputes Act was not complied with, by payment of retrenchment compensation, the impugned termination is illegal, invalid and abinitio void Since the voluntary retirement submitted by the Petitioner under the voluntary retirement scheme of the Respondent's Company was rejected by the Respondent, the offer of the voluntary retirement by the Petitioner has no effect and stands repudiated by the Respondent The Petitioner is without any

employment. For all or any of these reasons therefore the Petitioner will be entitled to reinstatement with back wages.

(3) The Respondent in its counter statement contends under Rule 46 of the Mines Rules, a Surveyor shall be deemed to hold a position of supervision or management or employed in a confidenial capacity. The nature of work and the responsibilities of a surveyor are such that a surveyor is deemed to have been employed in a supervisory capacity. He is occupying a position of initiative and command and it cannot be said that his work was of a technical nature. As the Petitioner was not a workman, he was not entitled to raise a dispute under Section 2-A of the Industrial Disputes Act. Hence the present reference is bad. The Management-Company is engaged in the manufacture of cement. It has 18 cement factories located in 10 States in the country. The Management-Company is also having quarries at various places from where lime stone is mined. Lime stone is a main raw material in the manufacture of cement and therefore large number of workmen are employed in the various quarries for escavating lime stone. On his representation, the Petitioner was promoted to the Company's Grade on per with other Mines Foreman and was transferred to Bombay. In the year 1976, the Petitioner requested for transfer back to Madukkarai Works. His request was complied with on the condition he will attend to the statutory survey work of the quarries attached to various cement factories including Madukkarai works. Since then, he is to be deputed for survey work of the various quarries as and when required The Petitioner did not have full time work at Madukkarai and it was for that reason his services were used even outside Madukkarai Works. By deputing him to work in the various quarries, the Mangement-Company has not violated any of the statutory regulations. In January, 1981, the Pettiioner was asked to proceed to Sitaramapuram Mines in Andhra Pradesh in connection with the annual survey under the Metalliferous Mines Regulations. He was also asked to proceed to Kymore Works where his services were required. The Petitioner expressed his unwillingness to go to Sitaramapuram Mines and Kymore Works and his representation against going to these places was rejected. Thereupon on 14-2-1981 the Petitioner made an application to the Management Company for retiring him under the Voluntary Retirement Scheme. As Voluntary Retirement Scheme was applicable only to certain categories of employees in which there was surplusage and since Mines Surveyor was not a surplus category, his request for retirement under the Voluntary Retirement Scheme was not accepted However, as he wanted to retire on the ground of ill health, the Company sought the opinion of its Medical Officer. The Chief Medical Officer of the Madukkarai Works gave a report on 13-3-1981 confirming that the Petitioner was suffering from Arthritis for two years. He also opined that travelling long distance by itself cannot lead to Arthritis but it can aggrevate the disease as joints would get stiff due to sitting for long hours during the journey In other words he advised that the Petitioner be retired on medical grounds. Since he was not willing to work outside Madukkarai as originally agreed upon and further he was medically unfit, the Company have no option than to terminate his services. Accordingly, by letter dated 10-4-1981, the Petitioner's services were terminated on medical grounds by paying one month's salary in lieu of notice. His other dues were also settled according to the Company's rules. The Petitioner accepted his termination and also received all his dues without any demur. The termination of the Petitioner's services on medical grounds was therefore bona fide, justified and valid in law and hence it is not liable to be interfered with. Even assuming without admitting that the Petitioner was a workman and as such governed by the certified standing orders of the limestone mines, the termination of his employment was perfectly in accordance with the standing order 18(1) and therefore it cannot be interfered with. The retirement of the Petitioner on medical grounds even assuming to be a termination was not for any misconduct. There was no obligation to give any opportunity to the Petitioner before resorting to the termination on medical grounds The cessation of employment of the Petitioner being on the ground of continued ill health would not amount to retrenchment, and hence there is no question of paying any retirement compensation The application for voluntary retirement made by the Petitioner was on his own volition and that was an expression of his intention not to continue in employment Hence the Petitioner cannot plead for continued employment in the service of the Company It is reliably learnt that the Petitioner is employed in an undertaking of the Tamil Nadu Government. Hence the Respondent prays that for all or any of these reasons, this reference should be rejected in favour of the Respondent.

(4) The points for determination in this case will be :

(1) Whether this reference is bad for all or any of the reasons mentioned in the counter statement;

(2) whether the order of termination is not valid for all or any of the reasons stated in the claim statement? and

(3) what relief the parties are entitled to.

(5) Point No. 1 : W.W.1, the Petitioner states and it is not challenged that he was working as a Surveyor under the Quarry Manager and his work is that of surveying mines and preparing plans and sections as required under the Rules. According to him, he has no assistant or subordinate under him though, whenever he goes for survey work, he was helped by there or four helpers to carry the instruments etc. He has no power to grant any permission or leave to them nor he can take any disciplinary action against them. According to him therefore the work is only of a technical and clerical nature and not supervisory. Under Ex. M-11, which he admits to have received, scope, functions and responsibilities of the surveyor are set out. Besides surveying and levelling of Madukkarai and Walayar quarries, he has to prepare plans and sections as required under statute and also maintenance of records pertaining to asset units such as B. G. Track, airline, waterline, buildings, roads, fancings etc. He is also said to be holding overall charge of quarry carpenters and masons thereunder. It is also admitted by him that he has recommended leave for some workers under Exs. M-29 and M-30 and he has given appraisal report of one mining mate under Ex. M-31. It is also admitted by hi munder the Mines Rules, Mines Surveyor will be deemed to be of supervisory capacity and is recognised as an official under the Metalliferous Mines Regulations 1961 and except mazdoors, blasters, drillers others in the mining department including mining mates are officials and of supervisory staff. He also admits that he is a member of the Officers Superannuation fund and is entitled to the pension as against the workman who will not be entitled to pension It is on this evidence, it is contended therefore that W W 1 is not a workman under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947 to invoke the jurisdiction of this Court.

(6) Under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act "workman" means any person employed in any industry to do any skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the term of employment be express or implied, but does not include any such person who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or who being employed in a supervisory capacity; draws wages excessding five hunder rupees per mensem or exercise, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature. Accordingly therefore, all employees are workmen unless such workmen are engaged in the managerial or administrative capacity or if engaged in a supervisory capacity or functions mainly of a managerial nature and draws Rs 500. Undoubtedly, W.W.1 gets Rs. 1,400 per mensem and if he is engaged in managerial or administrative capacity he will be outside the purview of this section. It is contended by Sri Gopalan. learned counsel for the Management that he is employed in a supervisory capacity, as enjoined under Ex. M-11 to be in overall charge of carpenters and masons working in the quarry and in such capacity he has recommended leave for them under Exs M-29 and M-30 and sent confidential report of mining mate under Ex. M-31 Even statutorily according to him, under Rule 46 of the Mines Rules, 1955, mines surveyor is declared to be person, holding position of supervision or management and employed in confidential capacity. I do not think his contention is supported by facts in this case. On the other hand, from the evidence of W W.1 which stands unchallenged and also from the records of the Management, it is evident that the main work of W.W 1 is only survey of mines and preparation of plans and records which are his own manual work and therefore he is only a workman, entitled to raise the dispute under the provisions of the Industrial Disputes Act.

(7) Under Ex. M-11, where the duties and functions of the Sureveyor particularly W.W.1 are mentioned, besides surveying work and maintenance of records which is admittedly of technical and clerical nature, he is also put in overall charge of quarry carpenters and the masons. In fact, he has also recommended under Ext. M-29 and M-30, sanction of leave, one in the case of carpenter and another in the case of manson. He has also sent confidential report Ex. M-31 in respect of one Sri Kumaraswamy who was a mining mate. Of course, W.W.1 says that it is not his duty to recommend leave for any person as he has no subordinate and in the absence of the Foreman, he has recommended leave for mason and carpenter and with the previous experiences as Permanent Way Inspector, he has given a confidential report about Sri Kumaraswamy, Mining Mate under Ex. M-31 and not because he worked under him as surveyor. Of course his belated explanation cannot carry conviction, but neverthless as he was put in charge of masons and carpenters and not mining mate under Ex. M-11, it is likely that he would have recommended the leave applications Exs. M-29 and M-30. As has been laid down in Rajendra Singh vs. State of U.P and others, reported in 1981 (L.I.C.) at page 1439, merely because an employee recommends the leave applications of other workmen, he cannot be said to be working in supervisory capacity. Because under Rule 46 of the Mines Rules, 1955, surveyor and assistant surveyor besides manager, under-manager, underground manager, assistant manger, ventilation officer and safety officer; mining electrical and mechnical engineer overman, foreman, sider and mate; mechanical and electrical foreman and electrical supervisor; medical officer, etc., are declared as persons holding position of supervision or management or employed in a confidential capacity the work of W.W.1 as Mines Surveyor cannot be said to be of supervisory nature under the Industrial Disputes Act, which alone governs the present dispute. On the other hand, as has been held in Lloyds Bank Ltd., New Delhi vs. Panna Lal Gupta and others reported in A.I.R. 1967 (Supreme Court) page 428 and Burmah Shell Oil Storage & Distribution Company of India Limited vs. The Burmah Shell Mangement Staff Association and others reported in 1970—II—L.L.J. at page 590 (Supreme Court), the test of substantial work performed by the concerned employee should be applied to find out as to whether the employee is employed to do skilled, unskilled, manual, clerical, technical work or supervisory work and the Supreme Court has held in the former one, even though the work of an auditor, is that of checking type, it is purely mechanical and it cannot be said to include a supervisory function and in the letter case, because the work of Fualling Superintendent, is mainly and substantially his own manual work and is not that of supervising the work of the few workmen who assist him and therefore both of them are workmen, though they may be drawing more than Rs. 500. Equally, the work of W.W.1 which is mainly of surveying the mines and preparing plans and sections is certainly of a technical nature and his own manual one and though he may incidetially discharge the supervisory work and send confidential report like Ex. M-31 about those, who assist him, he will be only a workman under the statute, viz., Industrial Disputes Act which will overide any of the rules under the Mines Act to the contrary. Even in Andhra Pradesh State Road Transport Corporation vs. Joseph Bernad and two others reported in 59 F.J.R. at page 307, Andhra Pradesh High Court has held that the only test is what is the predominant nature of the duties performed by the concerned person and his duties like testing of vehicles to certify their fitness, brake-test and steering-test and other checks were predominantly of a manual nature as was held by the Court below, though he performed some supervisory duties also like scrutinising the drivers' log sheets, etc., he is a workman for the purpose of Hyderabad Civil Service Rules. In fact, in Dr. P. N. Gulati vs. The Presiding Officer, Labour Court, Gorakhpur and another reported in 1977 (L.I.C.) at page 1088, the Allahabad High Court has held, even though a doctor is not employed for doing manual or clerical work, he is certainly employed for doing work of technical nature and therefore if he is employed in an industrial for rendering medical aid to its employees, he will be a workman. In Engineering Construction Corporation Limited, Madras vs. Additional Labour Court, Madras and others reported in 1980—II—L.L.J. at page 16, the Division Bench of our High Court has also held that a foreman, who is entrusted with shuttering work with the help of 10 or 12 carpenters, in accordance with the design and specification given, is only doing the technical work mainly and his work is not of a supervisory nature.

(8) In fact, the Respondent-Management itself has admitted under Ex. W-12 before the Conciliation Officer that he is only a workman. Merely because W.W.1 makes a tall claim that he is admitted to the Officers Superannuation Fund and he is eligible for pension as an officer, though it is not true, he cannot be held not only because as I have held earlier his work is pre-dominatly technical nature, but also because the Respondent himself has admitted earlier that he is a workman. When the services of W.W.1 were terminated under Ex. M-20 dated 10-4-1981, W.W.1 sent a complaint Ex. W-11 reporting unlawful termination and also contending that he was working as a Mines Surveyor in his technical capacity in the Respondent's industry and not either in the administrative or managerial capacity though his total monthly salary was Rs. 1,430. As against this averment, the Respondent Management under Ex. M-12 has stated what is stated in paragraph 10 of the complain (i.e.) what is referred above, is substantially correct. In fact, it is understood by both parties, even at the time when the dispute was raised that W.W.1 is only a workman doing work of a technical nature and it is too late in the day for Sri Gopalan to contend that it is a slip and inadvertant statement. When a party comes to Conciliation Officer, as entitled to relief under the Industrial Disputes Act, if in fact he is not entitled to any such relief thereunder, the first thing that would be contended by the opposite party or the party who contends that he will not be entitled to any relief under the said Act, is to say that this dispute will be outside the scope of the Act because W.W.1 is not a workman. By no stratch of imagination, I can conceive the contention of Sri Gopalan under these circumstances that it is not an admission or it is an inadvertant admissoin made out of ignorance particularly when the Management is helped by legally qualified officers if not by fullly qualified team of officers. Even on this admission, therefore, I have to hold that W.W.1 is a workman and therefore this reference is valid. This point I find accordingly in favour of the Petitioner.

(9) Point No. 2 : It is true under Ex. M-20 dated 10-4-81, W.W.1 is said to have retired from Company's service on medical grounds with immediate effect. Of course, a month's salary was paid in lieu of notice and subsequently as admitted by W.W.1, the Petitioner, gratuity amount and provident fund amount, amounting to Rs. 53,000 were paid to him on 27-5-1981 and 30-5-1981 respectively. It is not known whether it is pure and simple, retirement or termination. In fact, in the counter statement, it is alleged by the Respondent Management that his services have been terminated under clause 18(1) of the certified Standing Orders of the Respondent Company and he was paid a month's wages in lieu of notice. It is therefore pure and simple, termination not on account of any misconduct on his part, but on medical grounds at his own request according to the Respondent. W.W.1, the Chief Medical Officer of the Respondent Company has stated that W.W.1 first complained of Arthritis on 23-5-1979 as entered in Ex. M-32, the medical history card, and thereafter he had fallen sick for 9 times, out of which he complained of Arthritis for 7 times. In fact, he states that in December, 1980, W.W.1 requested him to recommend non-touring job on account of his ailment. He did not of course recommend as desired by him, but he only sent Ex. M-33 on 2-1-1981 to the effect that cold climate especially affects him adversely and aggravates his joint pains. In the end of February or 1st week of March, 1981 the General Manager asked his report about his physical fitness to work as Mines Surveyor. He gave his report Ex. M-26 on 13-3-1981 stating that W.W.1 is physically unfit to discharge his duties as Mines Surveyor and also recommended that he may be retired on medical grounds. It is on the strength of his report, his servlces have been terminated under Ex. M-20. It is true W.W.1 himself has admitted that he is suffering from chronic Rheumatoid Arthritis under Exs. M-13, M-14 and M-17, dated 25-12-1980, 27-1-1981 and 14-2-1981 respectively, though he has stated therein that he may be given stationary work and not touring work and in case it is not possible, he may be permitted to retire with benefits as a special case under voluntary retirement benefits scheme. However, the Mangement did not favour him with any of his request. On the other hand he has been retired, or the services have been terminated under

Ex. M-20 on medical grounds. It is therefore contended by Sri Arumugam, learned counsel for W.W.1 that this termination without any enquiry is illegal. On the other hand, Sri Gopalan will contend that since W.W.1 himself wanted to get out of service, he has been only complied with the order of termination though of course the voluntary retirement scheme he asked for could not be extended in his case, as to his knowledge, it is available only in the case of surplus personnel and not to retirement on medical grounds.

(10) Whatever concession the Management might have been given to W.W.1 earlier in taking him back to Madukkarai Cements at his request while he was working at Bombay and whatever may be the conditions contemplated under clause 38(3) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 that one surveyor should be appointed for each mine, as per the conditions of transfer, when he was transferred from Bombay to Madukkarai, he has to look after various mines in various parts of India, It is only in 1979, he was pleading his inability under Exs. M-13, M-14 and M-17 on health grounds to go out of Madukkarai and opted for voluntary retirement in case, his request is not conceded. In fact, his request under Ex. M-13 has been rejected under Ex M-16 and inspite of his request not to disturb him out of Madukkarai, he has been directed under Ex. M-18 dated 21-2-1981 to go to Chanda Sindola Mines. When the same was not complied with. Ex. M-20 order of termination was passed. It is obvious from these circumstances, whatever may be the terms of contract between parties or obligations to go out of Madukkarai on the part of W.W.1, that it is only when W.W.1 refused to move out of Madukkarai, in spite of his request, not to disturb him out of Madukkarai, being rejected that this order of termination has been served on him. Though obviously, on the face of it, it may appear that it is an order of retirement at his request on medical grounds, it is in fact termination for misconduct of disobedience to carry out the orders of the superior authorities. In such cases, it necessarily, follows explanation must be called for, enquiry must be held and thereafter on being found guilty only, he must be either dismissed from service or his services must be terminated In as much as nothing has been followed either under clause 18(2) or clauses 19 and 20 of the certified Standing Orders Ex. M-28, this order of termination cannot be sustained.

(11) There is no provision under the Standing Orders that a person can be retired either at his own request on medical grounds in the said certified Standing Orders Ex. M-28. On the other hand under clause 18(7) of the said certified Standing Orders, there is only this provision that every worker shall retire on attaining the age of 60 years which shall be fixed as the age of superannuation, provided that the Company may in their discretion extend the period of service of any worker on reaching the said age of superannuation. Even if his services are to be terminated on medical grounds, two things must be established. One is that he is medically unfit to do the work entrusted to him and the other is that an opportunity was given to him to prove that he is fit. He might have admitted that he is suffering from Arthritis, but he was pleading this disease only not to to move out of Madukkarai and not to be removed from service. In fact, his plea that his present disease disables him to go out of Madukkarai, is supported by Ex. M-33, the Medical Certificate admittedly issued by M.W.1 that cold climate especially affects him adversely and aggravates his joint pains. It is not as if this disease even if true is incurable. On the account, of course, he was on leave till 14-2-1981 and he reported to duty on 15-2-1981, on being found fit for duty by M.W.1 himself under Ex. M-32. M.W.1 did not examine him after 15-2-1981 and before his report Ex. M-26 as admitted by him. If he still gives a report Ex. M-26 on 13-3-1981, it is not because that he was actually sick or disabled after 15-2-1981 but because he was previously sick as I said before. Even granting that W.W.1 has admitted that he is suffering from Arthritis, in as much as he was found fit on 15-12-1981, in the absence of any examination by Medical Officer thereafter, he cannot be declared unfit for job. In fact, he was not even found unfit under Ex. M-26 for the job as it is. but only a job of a mines surveyor which involves extensive travel. As it is therefore even on his own certificate, it cannot to be said that he is physically unfit for doing the survey work to be discharged or retired from service under Ex. M-20. If therefore he is hale and healthy and he is also physically fit, he cannot be retired on this ground Even if it is true, as I said before, as no explanation was called for and no opportunity was given to him, to offer his defence as was held in Cpt. Virendra Kumar vs. Union of India reported in 1981 (L.I.C.) at page 433 (Supreme Court) and Binny Limited vs. K. P. Joy and another reported in 58 F.I.R. at page 369, this order of termination cannot be sustained.

(12) Of course Sri Gopalan is not contending that W.W.1 will be estopped from challenging the order of termination in as much as he has fully received all the amounts due to him, and it is only thereafter he has challenged the order. On the other hand, his contention will be that the grievance of W.W.1 is not against the order of termination, but only against not granting the benefit under the voluntary retirement benefit scheme which will be available only with hands are in surplus and therefore he will be deemed to be conceded this order of termination as valid. Of course, merely because he received all the dues. I do not think W.W 1 is estopped from challenging the order of termination as was held in Andhra Pradesh State Road Transport Corporation vs. Joseph Bernard and two others reported in 59 F.J.R. at page 307, as referred earlier for a different point. If therefore he is not estopped from challenging this order, then certainly if the order is found invalid if has to be set aside. This poit I find accordingly in favour of the Petitioner.

(13) Point No. 3 : It is seen from various correspondence till 1980 that the work of W W 1 is mostly or atleast for a period of six months, outside Madukkarai It is only from January, 1981, he started his plea of disability to move out of Madukkarai on the ground of his ill health. Under these circumstances, if he is again reinstated, naturally the Management will insist upon sending him out, and on his refusal, he will be again taken to task But at the same time, I cannot uphold the order of termination which has been declared invalid and I am bound to order reinstatement with back wages In between therefore, a via media should be struck, under which both parties can be free from their respective difficulties. The best way will be to order compensation in lieu of reinstatement, once the order of termination is found illegal. W.W.1 was removed from service with effect from 10-4-1981. It is nearly two years and seven months since he is out of job. If he is ordered to be reinstated with back wages, it comes to nearly Rs. 43,400. On the other hand, as offered by him to retire from the Respondent's industry under voluntary retirement benefit scheme which carries a month's wages for every year of service, (i.e.) from 1960 onwards for nearly 23 years till this date, when, because of the order of termination being held invalid, he will be deemed to be in service, works out to about Rs. 32,200. To be fair for both parties, I think a sum of Rs. 40,000 a round figure, will be decent amount as compensation in lieu of reinstatement with back wages and fixe the same accordingly. This point I find accordingly in favour of the Petitioner.

(14) In the result, an award is passed that W.W.1 the Petitioner Sri Jayes (John Samuel) is entitled to reinstatement with back wages, but however there will be no order of reinstatement and he will be paid a sum of Rs. 40,000 as compensation in lieu of reinstatement with back wages. There will be no order as to costs.

Dated, the 25th day of November, 1983.

WITNESSES EXAMINED

W.W.1—Thiru S. Jayes.
For Management
M.W.1—Dr. M. Bhaskara Rao.

EXHIBITS MARKED

For Workman

W-1 8-12-66—Surveyor's Service Certificate of competency to survey the workings. (copy) issued to workman.

W-2-10/15-2-83—Copy of letter from Madukkarai Cement Works addressed to Wadi Cement Works.

W-3/29-7-71—Copy of letter from the Mangement to the Joint Director of Mines Safety, Mysore.

W-4-12/16-1-80—Copy of letter Annual Survey of quarries 1980 from Respondent/ Management.

W-5/29-1-80—Copy of letter from the Management to the Mining Department regarding Annual Survey of Quarry.

W-6/10-12-80—Copy of letter from Chanda Cement Works to the Madukkarai Cement Works.

W-7/31-12-80—Copy of letter from the Management, Madukkarai Works, Savingram.

W-8/2-1-81—Copy of letter of the Management to Mining Department, Bombay.

W-9/27-1-81—Copy of letter from the Management to W.W.1.

W-10/19-3-81—Copy of letter of Mining Department of the Management.

W-11/15-10-81—Copy of 2-A petition filed by the W.W.1 (Jayes), before the Regional Labour Commissioner (General), Madras-6.

W-12/21-11-81—Copy of reply statement given by the Management to Ex. W-11 before the Assistant Labour Commissioner (Central) Madras-6.

W-13/21-12-81—Copy of letter from Thiru Jayes (W.W.1) to the Assistant Labour Commissioner (Central) Madras-6.

W-14/—Particulars of sick leave taken from 1971 to 1981 of the workman.

W-15—Particulars of tour made by W W.1 after retransfer to Madukkarai from Bombay.

W-16/5-12-68—Copy of management's letter addressed to the Director General of Mines Safety, Bihar.

W-17/3-6-70—Copy of letter from Director General of Mines Safety to the Management.

W-18/14-10-70—Copy of circular issued by the Management to all works.

W-19/14-10-70—Copy of letter from the Management, Mining Department to all branches.

W-20/9-11-70—Copy of circular regarding appointment of surveyors.

W-21/15-5-72—Copy of circular issued by the Director General of Mines Safety Dhanbad.

W-22/17-7-74—Copy of letter from the Joint Director of Mines Safety, Hyderabad Region to the Management.

W-23/31-7-74—Copy of letter from the Management to Madukkarai Works.

W-24/8-8-74—Copy of reply to Ex. W-23 from Madukkarai Works.

W-25/9-8-74—Copy of letter from Mining Department.

W-26-9/10-9-74—Copy of letter from Wadi Cement Works to Mining Department.

W-27/12-6-76—Minutes of the meeting between DGMS and the Managements of Oorgam Region KGP.

W-28/10-8-76—Copy of letter from the Management to the workman (W.W.1) regarding transfer.

For Management.

M-1/19-2-64—Letter from the Petitioner to the Management.

M-2/12-3-64—Letter from the Petitioner to the Management for reinstatement.

M-3/30-3-64—Reply from the Management to Ex. M-2.

M-4/18-4-64—Letter from the Petitioner to the Management.

M-5/27-4-64—Letter from the Management to the Petitioner. changing his designation as Oversear.

M-6/7-4-67—Letter from the Management to the Petitioner promoting him as "Surveyor Mines".

M-7/17-10-74—Letter from the Petitioner to the Management.

M-8/3-12-75—Letter from the Management to the Petitioner.

M-9/24-2-77—Letter from the Petitioner to he Management.

M-10/20-5-77—Letter from the Petitioner to the Management.

M-11/30-7-77—Copy of page 1 from the Annual Appraisal report for the year ended on 31-7-1977 of the Petitioner.

M-12/16-3-79—Letter from the Petitioner to the Management.

M-13/25-12-80—Letter from the Petitioner to the Management.

M-14/27-1-81—Letter from the Petitioner to the Management. for posting him at Madukkarai permanently.

M-15/27-1-81—Letter from the Petitioner to the Management.

M-16/27-1-81—Letter from the Management to the Petitioner rejecting his request.

M-17/14-2-81—Letter from the Petitioner to the Managing Director of the Company.

M-18/21-2-81—Letter from the Management to the Petitioner posting him at Chanda Sindola Mines.

M-19/27-2-81—Letter from the Petitioner to the Management.

M-20/10-4-81—Retirement order issued by the Management to the Petitioner.

M-21/17-6-81—Letter from the Petitioner to the Management for reinstatement.

M-22/13-7-81—Letter from the Managment to the Petitioner.

M-23/20-7-81—Letter from the Petitioner to the Management.

M-24/26-2-82—Conciliation failure report of the Regional Labour Commissioner (Central) Madras-6.

M-25/—Extract of the rule 46 of the Mines Rules 1955.

M-26/13-3-81—Report of the Chief Medical Officer of the Management addressed to General Manager.

M-27—The personal data card of the Petitioner.

M-28—Certified standing orders of the Management, Lime Stone Mines.

M-29—Leave application of R. Gopal with the initials of the Petitioner in the year 1978.

M-30—Leave application of Vasu with the initials of the Petitioner in the year 1980.

M-31—Annual Appraisal report for the year ended 31-7-79 for Lower Supervisory and Office Staff for the employee No. OS. 4092.

M-32—Medical record of the Petitioner/W W.1.

M-33/2-1-81—Medical report given by the Chief Medical Officer against W.W.1.

T. ARULRAJ, Presiding Officer.
Industrial Tribunal

[No. L-29025/1/82-D-III(B)]

New Delhi, the 17th December, 1983

S.O. 4635.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Burhar and Amkai Collieries, District Shahdol (M.P.) and their workmen, which has been received by the Central Government.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

Case No. CGIT|LC(R)(3) of 1976.

PARTIES

Employers in relation to the management of Burhar and Amlai Collieries, Post Office Dhanpuri, District Shahdol (M.P.), and their workmen represented through the Colliery Labour Union, P.O. Dhanpuri, District, Shahdol (M.P.).

APPEARANCES

For Union : Shri Motilal Pal

For Management : 1. Shri Gulab Gupta, Advocate for M|s. Rewa Coalfields Ltd.

2. Shri P.S. Nair, Advocate, for Western Coalfields Ltd.

INDUSTRY : Coal Mines DISTRICT : Shahdol (M.P.)

AWARD

Jabalpur, the 31st December, 1982

By Notification No. L-22012/14/75-D. III B dated 31-1-1976 by the Government of India in the Ministry of Labour the following dispute has been referred to this Tribunal for adjudication :—

"Whether Messrs Rewa Coalfields Limited, 4, Bank shall Street, Calcutta and the Coal Mines Authority Limited, Sohagpur Area, Post Office Dhanpuri, District Shahdol, the erstwhile and present owners of Burhar No. 1 and 2 and Amlai Colliery Dhanpuri, Shahdol, Madhya Pradesh are justified in not making payment of bonus to their workmen for the period 1-1-1973 to 30-4-1973 at 20 per cent as demanded by the workmen ? If not, to what quantum of bonus are the workmen of the above said collieries entitled ? "

For the reasons given in the orders/awards passed today in Reference No. 14|1974 the award in this case as under :—

(2) Messrs Rewa Coalfields Ltd., 4, Bankshall Street, Calcutta and the Coal Mines Authority Ltd. Sohagpur, P.O. Dhanpuri District Shahdol the erstwhile and present owners of Burhar No. 1 and 2 and Amlai Colliery, Dhanpuri, Shahdol, Madhya Pradesh are justified in not making payment of bonus to their workmen for the period 1-1-1973 to 30-4-1973 at 20 per cent as demanded by the workmen as under the law i.e. Payment of Bonus Act, 1965 no bonus is payable by the emplover for a part only of the accounting year. The workmen have been paid bonus for the whole of the accounting year 1973 by their employer according to law. Hence no more bonus, except the amount and at the rate at which they have been paid for the whole year 1973, is payable either by the erstwhile or the present owners of these mines.

(2) In the circumstances of the case both the parties shall bear their own costs.

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-22/12/14/75-D. III(B)-Pt.]

NAND LAL, Under Secy.

New Delhi, the 12th December, 1983

S.O. 4636.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ningha Colliery and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th December, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No 7/81

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ningha Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P. O. Kalipahari, Dist. Burdwan.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. N. Lala, Advocate.

For the Workman.—Shri B. B. Pandey, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

AWARD

Dhanbad, the 1st December, 1983

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012-(4)/80-D.IV(B) dated the 19th March, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ningha Colliery of Eastern Coalfields Ltd., P O. Kalipahari, Dist. Burdwan by not regularising Shri Jamuna Kumar Singh as Sub-Area Incharge with effect from 28-1-1976 was justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. The case of the workman is that he had been working as a Havildar from the year 1960 as permanent employee under the erstwhile management at Sripur Colliery and continued to work as such even after nationalisation. After nationalisation the said colliery came under the control of Eastern Coalfields Ltd.

3. It is then stated that a permanent vacancy of Sub-Area Security Incharge, Ningha Sub-Area fell vacant for which all the eligible Havildars were interviewed by the Departmental Promotion Committee (D.P.C.) in December, 1975 in which the concerned workman Sri Jamuna Kumar Sigh was selected on promotion as Security Incharge, Ningha Sub-Area. By letter dated 28-1-76 the Dy. Chief Security Officer allowed the concerned workman to take up his duty as Security Incharge Ningha Sub-Area with effect from 1-2-76 and accordingly Shri Singh reported for his duty on 1-2-76 and continued to work till July/August, 1977 when his services as Security Incharge was abruptly stopped without any notice and another person viz. Sri B. B. Pandey a junior to workman concerned was placed to work in his place. It is, however, submitted that the letter posting him as Security Incharge, Ningha Sub-Area was in a very peculiar manner and though he had been posted at Ningha Sub-Area on promotion the recitals made in the said letter was not proper.

4. It is further stated that the action of the management in posting Sri B. B. Pandey as Security Incharge and reverting the concerned workman as Havildar is illegal and unjustified and that Sri Pandey was junior to him. The concerned workman, however, admits that he was paid the difference of wages for the period he worked as Security Incharge. The concerned workman raised an industrial dispute and after

failure report the issue has been referred to this Tribunal. The prayer of the workman is that he is entitled to be regularised as Sub-Area Security Incharge (Inspector) from the date he was deprived from the said status with all consequential benefits.

5. The management's case, however, is that on 19-3-1981 when the Reference was made there was no Sub-Area and there was no post of Sub-Area Incharge and hence the Reference is vague. It is also submitted that the matter was taken up by the union after six years and so it is a stale claim.

6. On facts it is stated on behalf of the management that the concerned workman Sri Jamuna Kumar Singh was working at Rana Colliery as a Havildar upto January 1976. After nationalisation the organisational set up was changed and a group of collieries were placed under the supervision of Sub-Area Manager. Thereafter there was further reorganisation and the Sub-Area was also abolished. It is stated that previously Rana Colliery was placed within the Ningha Sub-Area and the concerned workman was transferred from that colliery to Ningha SubArea where he joined his duties on 8-2-76. At that time the post of Sub-Area Security Incharge was lying vacant for the time being and he was allowed to work in that post till 27-4-76 as Sub-Area Security Incharge. When the said post was filled up by Sri B. B. Pandey and the concerned workman was ceased to work as Sub-Area Security Incharge with effect from 28-4-76 but he was paid difference of wages between his substantive post and the post of Sub-Area Security Incharge for the said period. According to the management the substantive post of the concerned workman was that of a Havildar only and that he had been directed to act in a higher category for some period only but he was not promoted to that post. It is further stated by the management that the concerned workman never worked as a Havildar from 1960 as alleged by him and that he became Havildar only in the year 1973. It is further stated that the post of Sub-Area Security Incharge fell vacant for which eligible Havildar including the concerned workman were interviewed but the concerned workman was not selected for that post and he was not promoted. Sri B. B. Pandey was promoted and he was posted as Sub-Area Security Incharge at Ningha Sub-Area. The allegation that Sri Pandey is junior to concerned workman has also been denied on behalf of the management. The prayer of the management is that as Shri Singh the concerned workman was never promoted as Sub-Area Security Incharge the question of regularising him does not arise at all and therefore it is submitted that the Reference be decided in favour of the management.

7. The point for consideration is as to whether the action of the mangement is not regularising the concerned workman as SubArea Security Incharge with effect from 28-1-1976 is justified. If not, to what relief the concerned workman is entitled.

8. It may, however, be stated that the terms of Reference is somewhat defective as in the year 1976 there was not post like Sub-Area Incharge. There was however a post of Sub-Area Security Incharge during that period which appears from the pleadings of the parties and therefore the words 'Sub-Area Incharge' in the terms of Reference should be read as "Sub-Area Security Incharge".

9. It may also be stated that the designation of Sub-Area Security Incharge was subsequently changed to Inspector and the persons holding the said post are now called as Inspector.

10. It is admitted that in the year 1975 a post of Sub Area Security Incharge fell vacant at Ningha for which eligible Havildars were called for interview by the Departmental Promotion Committee (D.P.C.). The concerned workman appeared before that Committee. The case of the concerned workman in paragraph 4 of his written statement is that after interview he was selected on promotion as Security Incharge. The question, therefore is as to whether the concerned workman was ever selected on promotion as Security Incharge or not. It is not denied that the said post is to be filed up only from the persons working as Havildars and that also after interview and selection by the D.P.C. Ext. M-2 is the result of the said D.P.C. dated 8-3-1976. From this list it will appear that the name of the concerned workman is not there but one Shri Big Bihari Pandey was then working at Girimint Colliery was recommended for promotion to the post of Sub-Area Security Inspector and was to be posted at Ningha Sub-Area. As stated already the post of Sub-Area Security Incharge was designated as Security Inspector by that time. The contention of the workman therefore, that he was selected and promoted to the post of Security Inspector or Sub-Area Security Incharge thus falls to the ground and there is no document filed by him to show that he was even selected for the said post.

11. On behalf of the management a varified petition has been filed stating that the relevant papers of the D.P.C. could not be filed in this case as they have been misplaced from the office or stolen away by somebody. For the said reason the other papers of the D.P.C. have not been filed. But the management has succeded in filing the result of the said Committee (Ext. M-2) which clearly indicate that the concerned workman was not promoted to the post of Security Inspector but one Sri B. B. Pandey was promoted and was subsequently posted at Ningha Sub-Area. The concerned workman has examined himself as W.W.1 and though he has stated that he was promoted to the said post but there is no document to support this fact.

12. Much reliance has been placed by he concerned workman on the Office Order of the management dated 28-1-1976 which has been marked as Ext. W-1. The reference of this Office Order is made in the written statement of the workman also. It is, therefore, to be seen as to whether this office order amounted to promotion of the concerned workman as Sub-Area Security Incharge. The order reads as follows —

> "Sri Jamuna Kumar Singh, Hav. Ningha Colliery is hereby appointed temporarily to act as a Sub-Area Security Incharge Ningha Sub-Area II without any change in the existing grade and scale of his pay.
>
> He will take up his duties from 1-2-76 and report to the Sub-Area Manager and Area Security Incharge accordingly."

Thus from the above order it is clear that Sri Singh the concerned workman was appointed temporarily to act as Sub-Area Security Incharge without any change in his existing grade and scale of pay. This letter thus definitely does not prove that the concerned workman was promoted as Sub-Area Security Incharge. According to the management the post was vacant and so Sri Singh was deputed to act temporarily there but his grade or scale of pay was not changed and for the period during which he worked he got difference of wages as provided under N.C.W.A-I & II. This fact has also been stated by MW-1 Deputy Chief Security Officer who has stated that the concerned workman was not promoted to the said post but he was deputed to act in that post temporarily. There is provision in the Coal Wage Board and N.C.W.A.-I & II that if a person is asked to officiate in a higher grade he is to get difference of wages but that will not entitle him to be regularised in the higher post. It is in evidence of the MWs that as the concerned workman was posted as Havildar at the same station he was temporarily directed to act in the higher grade till the vacancy was filled up after the result of the D.P.C. Sri B. B. Pandey who was selected and promoted was posted there and naturally the concerned workman was reverted back to his original post.

13. The next contention of the workman is that Sri B. B. Pandey was junior to him but still he was promoted. The question, therefore, is as to whether a junior person was promoted ignoring the claim of the concerned workman. It may, however, be stated that seniority is not the sole criteria for promotion and both seniority and suitability are to be taken into consideration. The management has filed a return of the erstwhile management sent to the C.M.P.F. Sl. No. 106 of thte said register has been marked as Ext. M-8. It is for the period January to March, 1961 and in this register the designation of the concerned workman has been shown as Chaprasi. The claim of the concerned workman, therefore, that he was working as Havildar since the year 1960 thus falls to the ground. It is only the Form 'B' register Ext. M-7 prepared in 1975 which shows that the concerned workman was a Havildar in that year vide entry No. 210. No document has been filed on either side to show on which particular date the concerned workman was promoted as a Havildar. Ext. M-6 is the service record of Shri

Pandey of the time of erstwhile management. It shows that Shri Pandey was appointed as Civil Guard on 2nd February, 1949 and that he was made officiating Havildar from 24th March, 1972. This document thus clearly indicate that Sri Pandey was working as Havildar from March, 1972 and therefore it cannot be said that Sri Pandey was junior to the concerned workman. Shri Pandey was promoted as Security Inspector by the D.P.C. by Ext. M-2 and by Office Order Ext. M-4 he was transferred to Ningha Sub-Area. Thus it is also not proved that a junior man was promoted ignoring the claim of the concerned workman. It will also appear that after 1975 there was another D.P.C. in the year 1978 and Sri Jamuna Kumar Singh the concerned workman was called for interview in the said Committee vide Ext. M-3 and annexure attached to it. This clearly indicates that Sri Singh was working as a Havildar till 1978. If he would have been selected and promoted as Havildar earlier there was no question of calling him again for interview by the D.P.C. The workman in his evidence has admitted that he had been called for interview for the post of Security Inspector in the year 1978.

14. Considering the entire evidence and facts and circumstances of the case it is held that the concerned workman was never selected or promoted as Sub-Area Security Incharge and so the question of regularising him in that post as prayed for does not arise at all and the management was justified in not regularising him in that post from 28th January, 1976. In the circumstances the concerned workman is not entitled to any relief.

15. The award is passed accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012(4)/80-D, IV(B)]

S.O. 4637.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd December, 1983.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT/LC(R)(37)/1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Coalfields Limited, Pench Area, Parasia, District Chhindwara,

AND

Their workmen represented through the Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (BMS) Chandametta, District Chhindwara (M.P.).

APPEARANCES :

For Union—Shri S. B. Singh.

For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mine. DISTRICT : Chhindwara (MP)

AWARD

Jabalpur, the 25th November, 1983

Central Government in exercise of its power under Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 referred a dispute between Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh (BMS) Chandametta, District Chhindwara and the management of the Western Coalfields Limited, as to whether the Badli workers would be entitled to wages for three festival holidays ? Bhartiya Koyala Khadan Mazdoor Sangh gave a strike notice to the management and amongst the various demands made, one of the demands was as under :—

"Wages be paid for all festival holidays to Badli workers engaged during the year."

The matter was taken up in conciliation proceeding by the Assistant Labour Commissioner (Central) Chhindwara and on his failure report the Central Government has made the reference for adjudication vide Notification No. L-22011(B)/82-D.IV(B) dated 28th May, 1982. The dispute under reference is as under :—

"Whether the action of the management of Western Coalfields Limited, Pench Area in making payment for three paid festival holidays only in a year to Badli workers, is justified ? If not, to what relief such workmen are entitled ?"

2. Though certain preliminary objections were raised in the statements filed by the management, none has been pressed before me and therefore, I will proceed to decide the question as referred to me.

3. Prior to the Nationalisation of coal mines, badli workers in the Chandametta mines were paid wages for seven days in a year for the festival holidays and the national holidays. There were one day for Diwali, one day for Holi, one day for Bhujaria i.e. the day succeeding Raksha Bandan and one for Idul-fitr as festival holidays and the Republic Day, Independence Day and the Mahatma Gandhi Anniversary day, as national holidays. It seems that a settlement had been arrived at before nationalization in regard to payment for festival holidays to badli workers working in the colliery and the workers were allowed seven paid holidays. It was agreed that such badli workers as had the benefit of seven paid holidays before the nationalisation will continue to get the benefit and shall be allowed seven days paid holidays as before. It is also not disputed that in some of the collieries run by M/s. Western Coalfields Limited badli workers are given seven paid holidays as stated above. Management, however, contends that there is no law, rule or regulation requiring seven holidays to be granted to any workman & much less a badli worker in the colliery. The badli workers had no right to claim payment for seven national holidays. In practice they were being given payment for three national holidays but not the festival holidays.

4. In the evidence led by the management the Additional Chief Personnel Manager, Shri Gur Bachan Singh Kapoor admitted that seven days holidays are provided to the regular workmen but these seven days holidays could be given to a regular workman only. The witness was also put the provision made in the recommendations of the Central Wage Board Report for the Coal Mining Industry at page 127 of Vol. I where it deals with paid festival holidays which are reproduced as under :—

"PAID FESTIVAL HOLIDAYS :—

16. The demand for paid festival holidays was dealt with by the Majumdar Tribunal which directed the grant of seven paid festival holidays in the year. It further directed that of these seven paid holidays (1) Republic Day, (2) Independence Day, (3) Mahatma Gandhi's Birth Day, should be observed without option, the remaining four days being fixed by agreement according to local custom, which varies from place to place.

17. The workmen have stated that the existing provision of seven paid festival holidays is not sufficient. They have endeavoured to justify an increase in the number of holidays on the grounds of social requirements, religious customs, climatic variations and similar reasons. The claims for paid festival holidays vary from ten to sixteen days in the year. The employers have pointed out that the existing provision for seven paid festival holidays in the year is adequate compared with similar facilities in other industries.

18. We are of the opinion that the existing provision for seven paid festival holidays in the year compares favourably with the number of festival holidays granted in other industries and must be held to be adequate. If, however, in any unit or units of the industry, more than seven paid festival holidays are granted, they shall be continued."

The above witness also admitted that these Wage Board Recommendations are accepted by the management and are binding on it. The management is thus regulated by the

Wage Board recommendations and the recommendations provided that the seven paid festival holidays granted to the workers shall be continued in general. The question,therefore, that arises is whether the badli workers in general can also avail of this benefit as had been indicated in paragraph 18 cited above."

5. While dealing with the scope of enquiry the Central Wage Board for Coal Mining Industry in para 2 in Chapter IV of the report clearly indicated as under :—

> "At the very first meeting of the Board held in Calcutta on 10th September, 1962, it was unanimously decided that the scope of the terms of reference to the Board would cover all employees in the coal mining industry who fall within the definition of the term "workman" in Section 2(a) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act XIV of 1947), including miners' and other sirdars."

The Wage Board report seeks to cover all types of workmen as would fall in the definition of the "workman" under the Industrial Disputes Act 1947. Similarly the National Coal Wage Agreement I dated 11th December, 1974 in paragraph 7.2 laid down that (i) leave shall continue to be governed by the Mines Act; (ii) the existing paid festival holidays shall continue as at present. Further in paragraph 7.3 it was stated that the existing benefits and facilities not covered or altered by this agreement shall continue as hitherto observed.' The provision as regards festival holidays was, therefore, the arrangement which was already in force existing at that time and accordingly fell to be governed as such under the Central Wage Board recommendations. Similarly N.C.W.A. II which is by the Joint Bipartite Committee for Coal Industry in para. 7.5.1 laid down that the existing national/festival holidays will continue and thereby again referring to the existing arrangement which was regulated by the Central Coal Wage Board recommendations.

6. It would be observed from para 2 of the Wage Board recommendations that they were made to cover all employees in the Coal Mining Industry who fall within the definition of "workmen". If the badli workers fell in the definition of "workmen" as provided under the Industrial Disputes Act 1947 the Wage Board recommendations would apply to them.

7. The definition of workmen under the Industrial Disputes Act lays down that the workman means—

> "any person (including an apprentice) employed in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be expressed or implied."

A Badli worker is undoubtedly a "workman" in this definition because he is either skilled or an unskilled worker and is not hit by the exceptions in the definition clause. Badli worker accordingly is a workman for which Wage Board made recommendations and those recommendations are that they should be given seven paid holidays.

8. Learned Counsel for the management strenuously argued that they are casual daily rated workers and they can sustain no claim for payment of wages for festival holidays. In my opinion, there would be a distinction between a casual labour as envisaged by the Industrial Disputes Act and the badli worker. The term badli worker, temporary workman and a casual worker as defined by the Standing Orders and is binding on the management. They are defined as under :—

> "(d) A "badli" or substituted is one who is appointed in the post of a permanent workman or a probationer who is temporarily absent; but he would cease to be a "badli" on completion of a continuous period of service of one year (190 attendances in the case of below ground workman and 240 attendances in the case of any other (workman) in the same post or other post or posts in the same category or earlier if the post is vacated by the working in the place of a probationer would be deemed to be permanent after completion of the probationary period.
>
> (e) A "temporary" workman is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature likely to be finished within a limited period. The period within which it is likely to be finished and should also be specified but it may be extended from time to time, if necessary.
>
> (f) An "apprentice" is a learner who is either paid an allowance or not paid any allowance during the period of his training, which shall inter-alia be specified in his term of contract.
>
> (g) A "casual" workman is a workman who has been engaged for work which is of substantially casual nature."

9. The nature of the casual and temporary workman is determined not by the nature of the tenure but essentially by the nature of their work. If the workman is employed to do the work which is essentially of casual nature he is a 'casual' workman. If he is employed to do the work which is essentially of a temporary nature he is a 'temporary' workman. A 'badli' worker on the other hand is a substitute who is appointed to the post of a permanent workman or a probationer who is temporarily absent and his tenure ceases, the moment the incumbent resumes duties. The work which he is required to do is not of a casual nature nor is of a temporary character, but he is employed only for a short time to step into the shoes of a permanent workman or a probationer who for some reason or the other is absent. While in the case of a casual or daily rated workman it may be argued that he is appointed for the day on which he had worked and after the day's work the contract of employment ceased till he is again appointed on the next day. A badli worker continues to remain on the post as long as the permanent incumbent is absent and therefore the contract of employment does not terminate at the end of the day as in the case of a casual worker. If a festival holidays falls between the days of work he was working he ought to be given the benefit and should be paid the wages for the holiday as the holiday has fallen during the sumsistence of the contract of employment. In this view of the matter I see no difficulty why the Wage Board recommendations as regards the festival holidays should not be availed of by the badli workers.

I would therefore make an award accordingly and direct that the Badli workers are entitled to wages for the festival holidays namely, one day for Diwali, one day for Holi, one day for Bujariya & one day for Idul-fitr.

There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-22011(8)/82-D. IV(B)]

New Delhi, the 13th December, 1983

S.O. 4638.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of J. K. Ropeways of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th December, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 19/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of J. K. Ropeways of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan.

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri N. Das, Advocate.

For the Workman—Shri J. D. Lal, Advocate.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

AWARD

Dhanbad, the 30th November, 1983

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10 (i) (d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-19012(75)/81-D IV(B) dated 27th February, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the General Manager, J. K. Ropeways of M/s. E.C.L., P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan in not regularising Sri Sriprasad Singh as water cooli from 13-8-80 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. The case of the workman Sri Sriprasad Singh is that he was regular employee as Water Cooli at Station No. 3/10 under the opp party J. K. Ropeways of M/s. Eastern Coalfields Ltd, and that he along with others have been working on contract basis. It is alleged that all the other water coolies were regularised by the management except the concerned workman who was on leave on medical ground. He applied for job after recovery but his application was not considered by the management. The present dispute was then raised through the union for taking the concerned workman on the role of the management as other water collies had already been regularised but when the conciliation ended in failure the present Reference was made.

3. It is submitted that the management adopted a discriminatory attitude and a policy of pick and choose according to their whims It is, therefore, prayed that the concerned workman should be absorbed as water coolie with effect from 13-8-1980 the date on which other water coolies were absorbed with full back wages.

4. The case of the management, however, is that the concerned workman never served as an employee under the management and that there was never any relationship of employer and employee. It is however stated that the concerned workman used to supply water required by the staff and employees of Station No. 3/10 and he used to collect water from nearby sources of drinking water and used to store the same in pitchers and drums kept in the Station The concerned workman used to carry water in tin containers and for each Bhar he was charging Rs 1.50 It is submitted that there was no other contractual relation with the concerned workman and the management and he was just a water supplier which is like all other local suppliers in the locality.

5. It is further stated that after taking over of the management of J. K. Ropeways which was previously under the Coal Board by Eastern Coalfields, the management provided a regular water mazdoor and as such there was no further requirement to take any drinking water from the concerned workman who ceased to have any connection with the management.

6 It is, however, admitted by the management that as per bipartite settlement water coolies were regularised by the management but this action of the management cannot lay any support to the case of the concerned workman and that no discrimination has been made as alleged.

7. On the above grounds it is prayed that the Reference be decided in favour of the management.

8 The point for consideration is as to whether the action of the General Manager, J. K. Ropeways in not regularising the concerned workman as water cooli from 13-8-1980 is justified. If not to what relief is he entitled.

9. It is not in dispute that J. K. Ropeways was originally under Coal Board The Coal Board, however, was abolished with effect from 31-3-75 by an Act in which it was provided that all employees of the Coal Board will become employees under the Eastern Coalfields Ltd, in which the Coal Board was merged and since 1-4-1975 the employees of Coal Board became employees of the Eastern Coalfields and were governed by the Industrial Disputes Act. The workman WW-1 in his evidence has stated that he was working previously under the Coal Board and from 1975 he is working under the present management. Thus it is admitted that since before 1975 the concerned workman was supplying water at Station No. 3/10 of the Ropeway as a water mazdoor. The case of the management, however, in short is that the concerned workman was never an employee either of the Coal Board or under the Eastern Coalfields and as there was no relationship of employer and employee the question of regularising him did not arise at all.

10. It, however, appears from the documents on record that the concerned workman was getting his wages on piece-rate basis vide Ext. M-1 series the 4 bills showing supply of water by the concerned workman and others and getting wages which were different in different month. In support of the fact, however, that the concerned workman was not an employee the management has filed Form B register Ext. M-4 to show that his name did not appear in it. MW-1 has also came to say the same fact. As against this Ext. M-5 is the attendance register which shows the attendance of the concerned workman was being marked by the management everyday. The fact that the concerned workman supplied water at Station No. 3/10 of the Ropeway is also admitted. WW-2 who is working as Asstt. Foreman has also stated that the concerned workman supplied water at the said station since the year 1972. This supply of water however is said to have been made on contract basis according to the management and it is contended on behalf of the management that the concerned workman was just a water supplier like milk supplier, vegetable supplier etc. The management has also relied on para 2 of the written statement of the concerned workman in which it is stated that the concerned workman and others were working on contract basis. But this does not mean that the concerned workman was in fact a contractor If he would have been a mere contractor then the question of recording his attendance everyday would not have arisen at all. It is no doubt true that when no supply of water was made the concerned workman did not get any wages But this is also the case of regular employees who do not get any wages if he does not attend to his duty and no leave is due to him.

11. The fact, however, is admitted that the concerned workman was supplying water regularly at Station No. 3/10 since atleast 1972 or even prior to that and his attendance used to be marked regularly. The case of the workman is that all other persons who were supplying water like him were regularised by the management on the basis of a settlement but he was not taken in due to union rivalary. The fact that all the persons who were supplying water and were working as Water coolies like the concerned workman were regularised by the management on the basis of a settlement dated 17-7-1980. Ext. M-2 is the minutes of the meeting held on 16-7-80 between the management and representatives of certain unions in which the matter of regularisation of water mazdoors of J. K. Ropeways was taken up and discussed. On the basis of this discussion a settlement was arrived at on 17-7-80 which has been marked Ext. M-3. It has not been denied on behalf of the management that all the water mazdoors except the concerned workman were regularised by this settlement and were made permanent employees. The minutes of the meeting Ext. M-2 would show that Sri Ganesh Bhattacharjee and the concerned workman whose names also appeared in the list submitted by the Committee for regularisation were omitted from the list as they had been absenting for a long time. The terms of the settlement Ext. M-3 however would show that the name of the concerned workman appear in Sl. No. 13 of the persons who were regularised but subsequently his name has been penned through and the name of one Dilip Paswan has been entered. These two documents thus clearly indicate that the management had initially agreed to regularise the concerned workman also and his name was mentioned in the terms of settlement, but subsequently for some reason or other his name was deleted. The case of the workman in evidence is that due to union rivalary his name was deleted by the management and he was not taken in. There is no reason as to why when the Committee had recommended the name of the concerned workman for regularisation and his name was also entered in the original terms of settlement his name was deleted at the last stage. The reason assigned by the management is that as he was absenting he was not considered The definite case of the concerned workman, however, is that as he fell ill he went home and could not attend

his duty in time. Ext. W-1 is the representation filed by the workman dated 13-8-80 before the management stating that as he was sick from 1-2-80 at his house he could not attend his duty till 12-8-80 and so his absence should be excused and he may be allowed to join his duty. In support of it he also filed a medical certificate. There is nothing to disbelieve the case of the concerned workman. The note on his application would show that he was not taken in as certain water coolies had already been regularised at the instance of some union.

12. From all the facts mentioned above it is clear that whether employee or not all the water coolies who were supplying water at the Ropeway Station either on contract basis or otherwise were duly regularised by the management on the basis of the settlement of July 1980 except the concerned workman who was left out. The concerned workman no doubt was absent for some time as he was ill and his illness was also supported by a medical certificate. But that alone was not sufficient to delete the name of the concerned workman altogether. He was working as a water coolie since before 1972 even according to the management and in that case on humanitarian ground the management before finally striking out his name should have sent a notice to him. This was not done at all and the case of the concerned workman definitely is that due to union rivalary his name was deleted. In fact his name had been recommended by the Committee and in the terms of settlement his name was there but at the last stage it was penned through and another man was substituted in his place. The concerned workman was serving the management for more than 8 to 10 years and in such circumstances the management was not justified in not regularising him when all other working as water coolies were regularised. On humanitarian ground also the concerned workman should have been regularised by the management even though he was absenting for some time and no discrimination should have caused against him.

13. Considering all the facts and circumstances of the case, I hold that the action of the management in not regularising the concerned workman with effect from 13-8-80, when he reported for duty, is unjustified.

14. The next question is regarding the relief. As the non-regularisation was unjustified the concerned workman is certainly entitled to be regularised by the management with effect from 13-8-80. But considering the circumstances that he was absent for some time, he will be entitled to only half the wages for the idle period. He will be entitled to his full wages from the date he joins his service and the management must regularise him within 14 days from the date of publication of the award.

15. The award is given accordingly.

J. N. SINGH, Presiding Officer

[No. L-19012/75/81-D-IV(B)]

A. K. SAHA MANDAL, Desk Officer

New Delhi, the 13th December, 1983

S.O. 4639.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Sutlej Link Project Sundernagar Himachal Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st December, 1983.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 95/83; 49/81

PARTIES :

Employers in relation to the management of Beas Sutlej Link Project Sunder Nagar Himachal Pradesh.

AND

Their Workman-Harcharan Dass

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri M. K. Bohra with Shri R. L. Dogra.

For the Workman—Workmen in person.

B.S.L. Project STATE : Himachal Pradesh

AWARD

Chandigarh, the 24th of November, 1983

The Central Government Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, herein after referred to as the Act, vide their Order No. L-42012(84)/80-D.II(B) dated the 31st of March 1981 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June 1983 referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Beas Sutlej Link Project in not correcting the designation of Shri Harcharan Dass from Deisel Mechanic to Auto Mechanic and not replacing him in the seniority list of Auto Mechanic is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. According to the claim statement, the petitioner/Workman joined service under the respondent/BSL Project Sundernager as a Beldar on 2-5-1966; in due course of time he was promoted as an Asstt. Mechanic and then rose to the rank of Mechanic w.e.f. 1-11-1971. It was averred that he had been working in the Auto Trade and was an Auto Mechanic so much so that his name also been figured in the seniority list of the said Trade from time to time, however, when such Annual list was circulated for the year 1978, he was shown in the category of Diesel Mechanics. The workman protested against the change of Trade and also represented to the Authorities concerned, but his representations fell on the deaf ears; and the formal demand notice also proved futile. He, therefore, raised on Industrial dispute, cultiminating in the instant Reference.

3. Resisting the Workman's claims the respondent/management admitted the factum of his entry in service under them and consequent promotion to the rank of Mechanic, but according to their version the petitioner had throughout been working as a Deisel Mechanic and his name also appeared in the joint seniority list of the Mechanics up to year 1974, because till then there was no classification of Mechanics in 'Auto' and 'Diesel'. It was averred that due to inadventence his name could not be included in the seniority list of the Mechanics of either of the Trades in the year 1973 and 1977; but when this ommission was detected, due rectification was made to incorporate his name in the relevant trade of Diesel-Mechanics for the year 1978 against which he grumbled fearing retrenchment.

4. Since the respective averments of the parties were fully covered under the terms of Reference, therefore, my learned predecessor called upon them to adduce their evidence. In their discretion both the parties relied on documents alone without bothering to lead any oral evidence.

5. On a careful scrutiny of the entire material on records and on hearing the parties, I am inclined to sustain the Workman's claim because, both in the history sheet of the Transfers at page No. 4 and Classifiction of Trade at page No. 14 of his Service Book Ex. R-1 he has been depicted as Mechanic-Auto Shop w.e.f. 11-12-71. It goes without saying that the Document throughout remained in the custody of the Respondent/management and the petitioner/Workman had no control over its maintenance. Moreover, it had never been the case of the respondent/Management that he had excess to any of their documents or that there was any occasion for him to manipulate the entries.

6. On behalf of the management it was contended that the classification of Diesel and Auto Mechanics from the parent branch of Mechanics came into existence for the first time after the year 1974 and, therefore, his depiction as a Mechanic Auto Shop in the year 1971 was meaningless.

7. I am not impressed with the submission firstly because it is not supported by any available evidence, secondly be cause at page No 4 of the aforesaid Service Book, pertaining to the History-sheet of Transfers, there is an entry dated 1-5-1975 revealing his posting as a Mechanic in the Auto-shop of Sub-Divn. Sundernagar. Had he been classified in the Diesel Trade there must have been some of the other referen e to that category as such, but it was not to be. And to crown it all, according to the respondent/management's own story, petitioner's name was omitted from the seniority list of both the Trades for the years 1975 and 1977, and he was shown for the first time in the category of Diesel Mechanics in the seniority list of year 1978, against which he immediately protested. What surpises me most is that for the reasons better known to them the respondent/Management did not give any explanation for withholding the seniority list for the year 1976; and it hardly requires any amphasis that it was a document of their own possession.

8. It may also be worthwhile to note that in the Annexures A and B i e Exts W-1 and W-2 the petitioner/Workman had been admitted to be an Auto Mechanic by the concerned S.D.O in his correspondence to the X.E.N, (Personnal) office B.S.L. Project. A copy of this correspondence was also sent to the T.P.T. Mechanic Division for information. These documents were not properly explained except for the usual aversion that they were not properly proved. But surprisingly, no objection was taken to their admissibility when they were tendered in evidence before my learned predecessor, on behalf of the Workman as early as on 24-10-1981, in the very presence of the Respondent's authorised representative.

9. In so far as the respondent/Management's other evidence is concerned, it hardly advances their cause. Ex R-1 was the service Book of the petitioner which as examined earlier completely demolishes their defence. Ex. R-2 shows the extracts from the disputed seniority list whereas Ex. R-3 indicates the rejection of Workman's representation by the Supdt. Engg.

10 Thus to sum up my aforesaid discussion on the limited available data and the points raised before me I return my Award in favour of the Workman with the findings that the action of the management of the B.S.L. Project in not correcting his designation from Diesel Mechanic to Auto Mechanic was not justified and that w.e.f. 11-12-1971, he should be incorporated in the seniority list of Auto Mechanics.

Chandigarh,

Dated : 24-11-1983.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012(84)/80-D.II(B)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1983

का. आ. 4640.—मैसर्स उगोमी प्राइवेट लिमिटेड, नरोदा रोड, अहमदाबाद-380025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

1147 GI/83—9

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/230/83-पी. एफ.-2]

New Delhi, the 22nd November, 1983

S.O. 4640.—Whereas Messrs Ugomi Private Limited, Naroda Road, Ahmedabad-380025, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(230)/83-PF-II]

का.आ. 4641.—मैसर्स अपर इण्डिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग एण्ड इंजीनियरिंग कं. प्रा. लि. रत्न बिल्डिंग, बेरी रोड, अपोजिट जिला कोर्ट्स, लुधियाना-141001, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा(3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण साफ करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/233/83- पी. एफ.-2]

S.O. 4641.—Whereas Messrs Upper India Steel Manufacturing and Engineering Company Pvt. Limited, Rattan Building, Beri Road, Opp. Distt. Courts, Ludhiana-141001, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed

in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the diffedence to legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(233)|83-PF-II]

का. आ. 4642 :—मैसर्स तिरुचेनदुर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. नाज़रेथ-628617 तिरुनेलवेली, तमिलनाडु राज्य (तमिलनाडु/8926), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा(3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रहने जाते हैं, या इस

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/234/83-पी. एफ.-2]

S.O. 4642.—Whereas Messrs The Tiruchendur Co-operative Spinning Mills Limited, Nazareth-628617, Tirunelveli (Tamil Nadu) (IN|3926), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commisioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(234)|83-PF-II]

का. आ. 4643.—मैसर्स एगोमिएटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड, चान्दा, सीमेन्ट वर्क्स, डाकघर सीमेन्ट नगर, जिला चन्द्रापुर-44502 (महाराष्ट्र राज्य/11552), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा(3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम के संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/229/83-पी. एफ.-2]

S.O. 4643.—Whereas Messrs The Associated Cement Companies Limited, Chanda Cement Works, P.O. Cement Nagar, District Chandrapur-442502 (Maharashtra State) (MH|11552), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(229)/83-PF-II]

का. आ. 4644 :—मैसर्स राठी गैसीस लिमिटेड मत्स्या इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर राजस्थान (राजस्थान/2514), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मे देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के

बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदस्य का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/228/83-पी. एफ.-2]

S.O. 4644.—Whereas Messrs Rathi Gases Limited, Matsya Industrial Area, Alwar, Rajasthan (RJ/2514) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that any employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE.

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintence of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(228)/83-PF-II]

का. आ. 4645 :—मैसर्स इन्टरनैशनल कम्प्टर्स इण्डियन मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड, मैगनैट हाउस, एन. मोरारजी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई-400038 (महाराष्ट्र/3980), और इसकी शाखाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन

फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण और निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दे दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/226/83-पी.एफ-2]

S.O. 4645.—Whereas Messrs International Computers Indian Manufacture Limited, Magnet House, N. Morarjee Marg, Balafd Estate, Bombay-400038 (MH/3980) and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 10 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Goverament and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(226)/83-PF-II]

का. आ. 4646.—मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हाई प्रैशर ब्वाईलर प्लाण्ट, तिरुचिरापल्ली-620014 (तमिलनाडु) (टी. एन./5249) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2-ख) के अधीन नैगमित्तिक आधार पर या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित भिन्न अपने विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के विभागीय कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण और निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का सारांश, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. नियोजक ऐसे कर्मचारी की बाबत, स्थापन छोड़ देता है और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य स्थापन में नौकरी आरम्भ करता है, उस अन्य स्थापन की बाबत बीमा निधि में जाने वाले कर्मचारी के नाम में आनुपातिक प्रीमियम का अन्तरण कराएगा ।

6. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

7. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी; यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

9. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट उस तारीख से रद्द समझी जाएगी और उस स्थापन को उक्त स्कीम के अधीन समझा जाएगा ।

11. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकेगी और नियोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

12. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत आते हैं, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

13. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/208/83-पी.एफ-2]

S.O. 4646.—Whereas Messrs Bharat Heavy Electricals Limited, High Pressure Boiler Plant, Tiruchirapalli-620014, Tamil Nadu (TN/5249) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2B) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) in respect of their departmental employees other than those employed on casual basis or through contractors.

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the departmental employees of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. The employer shall arrange in respect of an employee who leaves the establishment and joins another establishment covered under the said Act to transfer to the Insurance Fund in respect of the other establishment, the proportionate premium to the credit of the outgoing employees.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

7. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

8. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

9. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

10. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be deemed to have been cancelled with effect from that date and the establishment shall be treated as covered under the said Scheme.

11. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled and the employer proceeded against.

12. In the case of default, if any made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who are covered under the Scheme will be that of the employer.

13. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(208)/83-PF. II]

का. आ. 4647.—मैसर्स गंगा नगर शुगर मिल्स लिमिटेड, मन्दौर, जोधपुर (राजस्थान/482), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसका स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे घटाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फंड के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/210/83-पी.एफ-2]

S.O. 4647.—Whereas Messrs Ganga Nagar Sugar Mills Limited Mandore (Jodhpur) (RJ/482) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked

Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(210)/83-PF-II]

का आ. 4648.—मैसर्स आगरा लैदर बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, 5 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नूनहै, आगरा-6, उत्तर प्रदेश (उ.प्र./2744) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत

आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/240/83-पी.एफ-2]

S.O. 4648.—Whereas Messrs Agra Leather Board Private Limited, 5, Industrial Estate Nunhai—Agra-6 Uttar Pradesh (UP/2744) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from the time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenence of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S 35014(240)/83-PF-II]

का. आ. 4649 —मैसर्स साइन्टिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट कम्पनी लि, 6-तेजबहादुर सप्रू रोड, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश (उ प्र /647) और इसकी शाखाएं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकेगी ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/235/83-पी.एफ-2]

S.O. 4649.—Whereas Messrs The Scientific Instrument Company Limited, 6 Tej Bahadur Sapru Road, Allahabad-211001, Uttar Pradesh (UP/647) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme

of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of section 17of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S. 35014(235)/83-PF. II]

का आ. 4650 —मैसर्स दीपक निट्राईट लिमिटेड, 9/12, जी. आई .डी सी. कैमिकल्स कम्पलैक्स, नन्दमारी-391340, जिला बड़ोदा (गुजरात/5278) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा(3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के

सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/212/83-पी.एफ -2]

S.O. 4650.—Whereas Messrs Deepak Nitrite Limited, 9/12, G.I.D.C. Chemicals Complex, Nandesari-391340, District Baroda (GJ/5278) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

1147 GI/83—11

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of section 17of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(212)/83-PF-II]

का. आ. 4651.—मैसर्स गंगा नगर शुगर मिल्स लिमिटेड, 17, सिविल लाईन्स, जयपुर (राजस्थान/35) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या-एस 35014/211/83-पी. एफ. 2]

S.O 4651.—Whereas Messrs Ganga Nagar Sugar Mills Limited, 17 Civil Lines Jaipur (RJ/35) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme

of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(211)/83-PF-II]

का. आ. 4652.—मैसर्स गंगा नगर शुगर मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़ (राजस्थान/2325), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/216/83-पी. एफ.-2]

S.O. 4652.—Whereas Messrs Ganga Nagar Sugar Mills Limited, Hanumangarh (RJ/2325) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(216)/83-PF-II]

का. आ. 4653.—मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 62-63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (ई.डी.एल./4070), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/217/83-पी.एफ-2]

S.O. 4653.—Whereas Messrs National Thermal Power Corporation Limited, 62-63, Nehru Place, New Delhi-110019 (EDL/4070) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(217)/83-PF-II]

का. आ. 4654.—मैसर्स गंगा नगर शूगर मिल्ज़ लिमिटेड, अजमेर (राजस्थान/481), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014/218/83 पी. एफ -2]

S.O. 4654.—Whereas Messrs Ganga Nagar Sugar Mills Limited, Ajmer (RJ/481) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the **Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and** where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(218)/83-PF. II]

का. आ. 4655.—मैसर्स नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अपोजिट विक्टोरिया जुबिली हास्पीटल, डाक्टर मोतीबाई मार्ग, पंचकुइया—अहमदाबाद-2 (गुजरात-4964) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/244/83-पी.एफ-2]

S.O. 4655.—Whereas Messrs Nutan Nagarik Sahakari Bank Limited, Opp. Victoria Jubilee Hospital, Dr. Motibai Marg, Panchkuwaa, Ahmedabad-2, (GJ/4694) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts submission of returns payment of insurance premia transfer of accounts payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason, the employees of the, said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled

10 Where for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S 35014(244)/83 PF II]

का. आ. 4656 —मैसर्स पोलीकेम लिमिटेड, ए बी एस प्लाण्ट, 18 जी सी सी एरिया पोस्ट पट्रोफिल्स, बडौदा-391347 (गुजरात/10032), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस. 35014/246/83-पी.एफ. 2]

S.O. 4656.—Whereasas Messrs Polychem Limited, ABS Plant, 18 PCC Area, Post Petrofils, Baroda-391347 (GJ/10032), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employes than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(246)/83-PF. III]

का. आ. 4657.—मैसर्स पोलीफेम लिमिटेड, 7-जमशेदजी, टाटा रोड, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र/9115), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन

किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/243/83-पी.एफ. 2]

S.O. 4657.—Whereas Messrs Polychem Limited, 7 Jamshedji Tata Road, Bombay 400020 (MH/9115), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced, so that the benefit available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(243)/83-PF.II]

का० आ० 4658.—मैसर्स दि अम्बर को-आपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, वादापुडुपेट, डाकघर-एन०ए० जिला पिन : 635 818 (तमिलनाडु/3205) (जिसे इसमें इसमें पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षक प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के वाधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होता बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/261/83पी०एफ० 2]

S.O. 4658.—Whereas Messrs The Ambur Co-operative Sugar Mills Limited, Vadapudupet, P. O. N. A. District Pin-635818 (TN/3205) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrole him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(261)/83-PF-II]

का० आ० 4659.—मैसर्स बंगलौर कॉ-आपरेटिव मिल्क प्राडयूसर्स सोसाएटीज यूनियन लिमिटेड, बंगलौर-27 (कर्नाटक/6737) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम (1976) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है,; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यो के नामनिर्देशितियों

या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014 / 260/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4659.—Whereas Messrs Bangalore Co-Operative Milk Producers' Societies Union Ltd., No. 22 Poornima Building, J. C. Road, 1. Cross, Bangalore-27, (KN/6737) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premiums the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/260/83-PF-II]

का० आ० 4660.—मैसर्स नेशनल शीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, बीज, भवन पूसा कम्पलैक्स नई दिल्ली 110012 (इंडिया) (दिल्ली / 1795) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय, जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारी के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन पल्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि, आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत-सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस- 35014/259/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4660.—Whereas Messrs National Seeds Corporation Limited, Beej Bhavan, Pusa Complex, New Delhi-110012 (India) (DL/1795) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a tranlation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrole him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(259)/83-PF-II]

का० आ० 4661.—मैसर्स कारबन कारपोरेशन लिमिटेड, प्लाट नं० 88, एम, आई० डी० सी० इण्डस्ट्रियल एरिया, सतपुर, नासिक-422007 (महाराष्ट्र/19682) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पटट् पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस- 35014/258/83-पी० एफ-2]

S.O. 4661.—Whereas Messrs Carbon Corporation Limited Plot No 88 M.I.D.C. Industrial Area, Satpur, Nasik-422007 (MH/19682) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrole him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insu-

rance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premiums the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(258) 83-PF-II]

का० आ० 4662.—मैसर्स कारबन कारपोरेशन लिमिटेड, प्लाट नं० 88, एम० आई० डी० सी० इण्डस्ट्रीयल एरिया, सतपुरा, नासिक-422007 (महाराष्ट्र/19795) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनका मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, ऐसे हर बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसके स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती

तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देतियो/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस०-35014/257/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4662.—Whereas Messrs Carbon Corporation Limited, Plot No. 88 M.I.D.C. Industrial Area, Satpur, Nasik-422007 (MH/19795) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the saliant features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrole him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premiums the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(257)/83-PF-II]

का० आ०4667.—मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेटरीज़ इण्डिया लिमिटेड, 39-वेलचेरी रोड, मद्रास-32 (तमिल नाडु/1075) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले, ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक उसके विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते ; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/256/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4663.—Whereas Messrs Glaxo Laboratories India Limited, 39, Velacheri Road, Madras-32. (TN/1075) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer

of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employess of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(256)/83-PF-II]

का० आ० 4664.—मैसर्स जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, गुना मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश)/2018), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/255/83-पी० एफ० 2]

S O 4664—Whereas Messrs District Co operative Land Development Bank Limited, Guna (Madhya Pradesh) (MP, 2018), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provdent Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available [illegible] under the Group Insurance Scheme [illegible] benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(255)/83-PF II]

का० आ० 4665.—मैसर्स बेरी इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, जी० टी० रोड, बाई पास जलन्धर-4 (पंजाब-3893) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य, है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/254/83-पी० एफ० 2]

S.O 4665.—Whereas Messrs Berry Electricals Private Limited G.T. Road, Bye Pass Jullunder-4 (PN/3893), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(254)/83-PF-II]

का० आ० 4666—मैसर्स नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, (मार्केटिंग डिवीजन, सेल्ज एम्पलाइज) 10वी मंजिल, वदना बिल्डिंग, 11-टालस्टाय मार्ग, (नई दिल्ली-4330) (जिसें इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसें इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसें इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं ,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारो का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे जिसके अन्तर्गत लेखाओ का रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओ का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का सदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमे

संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/253/83-पी०एफ० 2]

S.O. 4666.—Whereas Messrs National Textile Corporation Limited, (Marketing Division Sales Employees) 10th Floor, Vandhna Building, 11 Tolstoy Marg, New Delhi (DL/4330), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adevrsely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(253)/83-PF-II]

का० आ० 4667.—मैसर्स ग्लेसको लेबोरेटरीज इण्डिया लिमिटेड, 50-हैडेक्स रोड, डाकघर-बक्स नं० 202, कलकत्ता-700027 (पश्चिम बंगाल) 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे

किसी रीति से कम हो जाते है ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृतसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सख्या एस-35014/252/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4567.—Whereas Messrs Glaxo Laboratories, India Limited, 50, Hyde Road, P.O. Box No. 202, Calcutta-700027 (WB/1860), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(252)/83-PF-II]

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

का०आ०—4668-मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इंडिया) लि०, कैलाश, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 (दिल्ली-2921) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त बीमा स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए, ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में ,उन मृतसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर करेगा।

[सं० एस 35014/269/83-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 28th November, 1983

S.O. 4668.—Whereas Messrs Engineering Projects (India) Limited, Kailash, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 (DL/2921), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and

provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(269)/83-PF-II]

का० आ० 4669.—मैसर्स दि प्रीमियर आटोमोबाईल्स लिमिटेड, 92-93, मेकर टावर्स "एफ" कफी परेड, जी० डी० सोमानी मार्ग, कोलाबा, बम्बई-5. (महा० 74) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार को यह समधोन हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारीयों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रीति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बदाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा मे संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को अन्तर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारीयों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/270/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4669.—Whereas Messrs The Premier Automobiles Limited, 92/93, Maker Towers F', Cuffe Parade, G.D. Somani Marg, Colaba, Bombay-5, (MH/74), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer features thereof, in the language of the majority of the employees.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(270)/83-PF-II]

का०आ० 4670 :—मैसर्स दि प्रीमियर आटोमोबाईलम लिमिटेड, 92/93, मेकर टावर "एफ" कफी परेड, कालावा, बम्बई-5 (महाराष्ट्र/73) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी

गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो-के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/271/83-पी०एफ० 2]

S.O. 4670.—Whereas Messrs The Premier Automobiles Limited, 92/93, Maker Towers 'F' Cuffe Parade, Colaba, Bombay-5 (MH/73), hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/271/83-PF.II]

का० आ० 4671.—मैसर्स अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गांधी पुल के पास, इन्कम-टैक्स आफिस के सामने अहमदाबाद (गुजरात/4663). (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे

लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; [तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/272/83-पी. एफ. 2]

S.O. 4671.—Whereas Messrs Ahmedabad District Co-operative Bank Limited, Near Gandhi Bridge, Opp. Income Tax Office, Ahmedabad (GJ/4663), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(272)/83-PF-II]

का०आ० 4672.—मैसर्स सेशासायी पेपर एण्ड बोर्डस् लिमिटड, पाल्लिपालायाम, गौरी, आर०एस०पी०ओ०, इरोड, तमिलनाडु (तमिलनाडु 4028) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमीयम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये फायदे उन फायदों के अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिय उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द किया जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/273/83-पी०एफ० 2]

S.O. 4672.—Whereas Messrs Seshasayee Paper and Boards Limited, Pallipalyam, Gauvery, R.S.P.O. Erode, Tamil Nadu (TN/4028), (hereinafter refrered to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(273)/83-PF.II]

का० आ० 4673 —मैसर्स स्ट्रा प्राडक्ट्स लिमिटेड, जय-केय-पुर डाकघर-रेयागोडा जिला कोरापुट (उड़ीसा/353), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों सदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रति-कर के रूप में, दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय, जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृतसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का

संदाय तत्परता से और प्रत्यक मामला में भारतीय जीवन बीमा निगम इसे बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/274/83-पी. एफ. 2]

S.O. 4673.—Whreas Messrs Straw Products Limited, Jay-Kaypur P.O. Rayagoda District, Koraput (OR/353), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(274)/83-PF. II]

का० आ० 4674.—मैसर्स कान्टिनेन्टल कान्सट्रेक्शन लिमिटेड, कान्टिनेण्टल हाउस 28 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (दिल्ली/1169) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/275/83-पी० एफ० 2]

S.O. 4674.—Whereas Messrs Continental Construction Ltd., Continental House 28 Nehru Place, New Delhi-110019 (DL/1169) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(275)/83-PF.II]

का० आ० 4675—मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, 5वीं मंजिल पोस्ट बाक्स नं० 633, 18-संसद मार्ग दिल्ली-1 (दिल्ली/4519), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है—

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/276/83-पी० एफ० 2]

S.O.4675.—Whereas Messrs N.G.E.F. Limited, Bank of Baroda Building, 5th Floor P.B. No. 633, 18 Sansad Marg, New Delhi-1 (DL/4519), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and

when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(276)/83-PF. II]

का० आ० 4676—मैसर्स वार्मस्ट (इण्डिया) (प्राइवेट) लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा (पंजाब/4102) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/278/83-पी० एफ० (2)]

S.O. 4676.—Whereas Messrs Barmalt (India) (P) Limited, Gurgaon, Haryana (PN/4102) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(278)/83-PF.II]

फा०आ० 4677.—मैसर्स गुजरात मशीनरी मेन्यूफैक्चरस लिमिटेड, पो० बाक्स नं० 1, कर्मसाद 388325 (गुजरात) (गुजरात/4499), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकेगी है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/280/83-पी०एफ०2]

S.O. 4677.—Whereas Messrs Gujarat Machinery Manufacturers Limited, P.B. No. 1, Karamsad-388325 (Gujarat) (GJ/4499) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(280)/83-PF.II]

का०आ० 4678.—मैसर्स आन्ध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड वी०एच०आर० शोपिंग कम-आफिस कम्प्लैक्स 2 मंजिल गवरनरपेट विजयवाड़ा (एपी/5064) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृतसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/201/83-पी०एफ० 2]

S.O. 4678.—Whereas Messrs Andhra Pradesh Heavy Machinery and Engineering Limited, V.H.R. Shopping cum-Office Complex, 2nd Floor, Governorpet, Vijayawada (AP/5864) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject

to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(281)/83-PF.II]

का० आ० 4679.—मैसर्स बोलानी ओर्स लिमिटेड, चार्टर्ड हाउस बिल्डिंग, पो० बाक्स नं० 46, कलकत्ता-700001 (पश्चिम बंगाल 5077), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहयुक्त बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17, की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहा ऐसी किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/282/83-पी. एफ. 2]

S.O. 4679.—Whereas Messrs Bolani Ores Limited, Chartered Bank Building, Post Box No. 46, Calcutta-700001 (WB/5077) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in employment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(282)/83-PF-II]

का० आ० 4680—मैसर्स बोरपेज लिमिटेड, 34, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020 (दिल्ली/358) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, तब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस–35014/283/83–पी० एफ०-2]

S.O. 4680.—Whereas Messrs Sharpedge Limited, 34, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 (DL/358) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(283)/83-PF-II]

का० आ० 4681.—मैसर्स इलैक्ट्रा (इण्डिया) लिमिटेड, आगीर इलैक्ट्रा (इण्डिया) लिमिटेड, (यूनिट-2) औद्योगिक क्षेत्र, परतापुर-3, (मेरठ) उ० प्र०/3547 और उ० प्र०/5213)। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों की प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, वि[illegible]णियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का [illegible]ण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृतसदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/284/83-पी. एफ. 2]

S.O. 4681.—Whereas Messrs Electra (India) Limited and Electra (India) Limited, (Unit-2) Industrial Area, Partapur-3, (Meerut) (UP/3547 and UP/5213) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto; the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(284)/83-PF-II]

का० आ० 4682.—मैसर्स मोहता स्पात लिमिटेड, आत्माराम हाउस, 1-टालसटाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 और इसके यूनिट (मोहता स्पात लि०, 70-72, औद्योगिक क्षेत्र) रतलाम-(म० प्र०/3103) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का, वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का

पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/289/83-पी.एफ.2]

S.O. 4682.—Whereas Messrs Mohta Ispat Limited, Atmaram House, 1 Tolstoy Marg, New Delhi-110001 and its unit (Mohta Ispat Limited, 70-72, Industrial Area, Ratlam (MP/3103), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Nontice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(289)/83-PF.II]

का. आ. 4683.—मैसर्स दि कोयम्बतूर कमल्स मिल्स लिमिटेड, उप्पल्लीपलायम, डाकघर-कोयम्बतूर-641015 (तमिलनाडु/68), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के संदेय के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/291/83-पी.एफ. 2]

S.O. 4683.—Whereas Messrs The Coimbatore Kamals Mills Limited, Upplipalayam P.O. Coimbatore-641015 (TN/68), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(291)/83-PF. II]

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1983

का० आ० 4684.—पंजाब राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री हरदियाल सिंह, के स्थान पर श्री सी० डी० चीमा सचिव, पंजाब सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 (अ) दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "[राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद् 22 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री सी० डी० चीमा,
सचिव,
पंजाब राज्य सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
चण्डीगढ़।"

[सं० यू-16012/10/83-एच०आई०

New Delhi, the 28th November, 1983

S.O. 4684.—Whereas the State Government of Punjab has in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri C. D. Cheema, Secretary to the Government of Punjab, Health and Family Welfare Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri Hardial Singh;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4]", for the entry against Serial Number 22, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri C. D. Cheema,
Secretary to the Govt. of Punjab,
Health & Family Welfare Department,
Chandigarh."

[No. U-16012/10/83-H.I.]

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1983

का० आ० 4685.—मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड राय बरेली-229010/(उप्र/4699) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसा विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/277/83-पी० एफ० 2]

New Delhi, the 29th November, 1983

S.O. 4685.—Whereas Messrs Indian Telephone Industries Limited, Rae Bareli-229010 (UP/4699) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said stablishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(277)/83-PF.II]

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4686.—आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में डा० टी० एन० संघी के स्थान पर डा० सी० माधव राव, इन्चार्ज निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में उस राज्य से प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3329 दिनांक 19 नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "(संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)", शीर्षक के नीचे मद 4 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात्:—

"डा० सी० माधव राव, एम० डी०
इन्चार्ज निदेशक,
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा,
आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद"

[सं० यू०-16012/15/83-एच० आई०]

New Delhi, the 1st December, 1983

S.O. 4686.—Whereas the State Government of Andhra Pradesh has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. C. Madhava Rao, Director of Insurance Medical Services, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Dr. T. N. Sanghi;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely —

In the said notification, under the heading '[Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10]' for the entry against item 4 the following entry shall be substituted, namely:—

'Dr. C. Madhava Rao,
Director of Insurance Medical Services,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.'

[No. U-16012/15/83-H.I.]

का० आ० 4687.—हरियाणा राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में डा० ओ० पी० कपूर के स्थान पर डा० ए० सी० फोगट, सहायक निदेशक, (सामाजिक बीमा) स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में उस राज्य से प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3329 दिनांक 19/11/81 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "(संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)", शीर्षक के नीचे मद 8 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात्:—

"डा० ए० सी० फोगट,
सहायक निदेशक (सामाजिक बीमा) स्वास्थ्य सेवा,
हरियाणा सरकार
चण्डीगढ़"

[संख्या यू-16012/16/83-एच० आई०]

S.O. 4687.—Whereas the State Government of Haryana has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. A. C. Phogat, Assistant Director (Social Insurance) Health Service, Government of Haryana, Chandigarh to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Dr. O. P. Kapoor;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification, under the heading '[Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10]' for the entry against item 8, the following entry shall be substituted, namely :—

'Dr. A. C. Phogat,
Assistant Director (Social Insurance)
Health Services,
Government of Haryana,
Chandigarh

[No. U-16012/16/83-H.I.]

का० आ० 4688.—कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण मे डा० वी० नारायण स्वामी के स्थान पर डा० बी० कृष्णाचार्य, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (चिकित्सा) सेवा, कर्नाटक सरकार, बगलौर को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में उस राज्य से प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3329, दिनांक 19-11-81 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना मे "(संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)", शीर्षक के नीचे मद 11 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"डा० बी० कृष्णाचार्य,
निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना (चिकित्सा) सेवा,
कर्नाटक सरकार, राजाजी नगर,
बंगलौर-560010"

[संख्या यू-16012/17/83-एच० आई०]

S.O. 4688.—Whereas the State Government of Karnataka has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. B. Krishnacharya, Director FSI Scheme (Medical) services, Government of Karnataka, Bangalore to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Dr. V. Narayanaswamy;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification, under the heading '[Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10]' for the entry against item 11, the following entry shall be substituted, namely :—

'Dr. B. Krishnacharya,
Director,
Employees State Insurance Scheme
(Medical) services
Government of Karnataka,
Rajajinagar,
Bangalore-560010.

[U-16012/17/83-H.I.]

का० आ० 4689.—पंजाब राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में डा० आशा सिंह के स्थान पर डा० जगजीत सिंह, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में उस राज्य से प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3329 दिनांक 19-11-1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "[संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]", शीर्षक के नीचे मद 18 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"डा० जगजीत सिंह,
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा (एस० आई०)
पंजाब सरकार,
चण्डीगढ़।"

[संख्या यू-16012/18/83-एच० आई०]

S.O. 4689.—Whereas the State Government of Punjab, has in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. Jagjit Singh, Joint Director, Health Services (SI) Punjab to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Dr. Asa Singh;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification under the heading '[Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section (1) of section 10]' for the entry against item 18, the following entry shall be substituted, namely :—

'Dr. Jagjit Singh,
Joint Director, Health Services (SI),
Government of Punjab,
Chandigarh.'

[No. U-16012/18/83-H.I.]

का० आ० 4690.—तमिल नाडु राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण मे डा० अर्नेस्ट जे० डेविड के स्थान पर डा० (श्रीमती) आर सरस्वती, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन तमिल नाडु सरकार, मद्रास को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद में उस राज्य से प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्दिष्ट किया है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3329 दिनांक 19-11-81 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "[संबंधित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]", शीर्षक के नीचे मद 20 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"डा० (श्रीमती) आर० सरस्वती, निदेशक,
स्वास्थ्य सेवा और परिवार नियोजन,
तमिलनाडु सरकार,
मद्रास।"

[संख्या यू० 16012/19/83-एच० आई०]

S.O. 4690.—Whereas the State Government of Tamil Nadu has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Dr. (Smt.) R. Saraswathi, Director of Medical Services & Family Welfare, Govt. of Tamil Nadu, Madras to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Dr. Ernest J. David.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of

1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3329, dated 19th November, 1981, namely :—

In the said notification, under the heading 'Nominated by the State Governments concerned under clause (d) of sub-section 1 of section 10' for the entry against item 20 the following entry shall be substituted, namely :—

'Dr. (Smt.) R. Saraswathi,
Director of Medical Services &
Family Welfare
Govt. of Tamil Nadu,
Madras.'

[No. U-16012/19/83-H I.]

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4691.—यतः मैसर्स इंडियन अल्यूमिनियम केबल्स लिमिटेड 18-बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-1 (दिल्ली/1378) (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है ।

यतः केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिये तैयार किये गये भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है,

अब इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिये छूट प्रदान करती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिये सुविधायें प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा ।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान की दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगी ।

3. पेंशनियों के मामले में छूट-प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी ।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जायेगा । उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा ।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (क) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाये जायेंगे ।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है, तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनायेगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा ।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिये गये निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिये नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा ।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए, भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा ।

9 न्यासी बोर्ड कम से कम 3 मास में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्ग निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे । केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा-परीक्षा कराये और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा ।

10. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी । इस प्रयोजन के लिये भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

11. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने और कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा । अंशदानों को विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, जिस प्रकार एक न छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है ।

12. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा । प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

13. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा ।

14. न्यासी बोर्ड एक वस्तु ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा ।

15. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा ।

16. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा ।

17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है । ये पास बुकें कर्मचारियों को अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा ।

18. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

19 यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने मे असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

20. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण, लूटखसूट, ख्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

21 नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करे।

22. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

23 स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में किसी बात के होने पर भी यदि स्थापना के कर्मचारी के सदस्य न रहने पर या उसके अन्य स्थापनों में स्थानान्तरण होने पर उसको उपदान और पेंशन नियमों के अन्तर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि, नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित उस राशि से कम है जो उसे उस समय प्राप्त होती जब वह उक्त स्कीम का सदस्य होता, तो नियोक्ता मुआवजे के रूप में या विशेष अंशदान के रूप में राशि का अन्तर अदा करेगा।

24. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्चे, जिसमें लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

25. स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के अंदर ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत निश्चित करे।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27 "समुचित सरकार" स्थापना को चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28 यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं० एस० 35014/264/83/पी० एफ० 2·]

1147 GI/83—18

New Delhi, the 2nd December, 1983

S.O. 4691.—Whereas Messrs Indian Aluminium Cables Limited, 18-Barakhamba Road, New Delhi-1 (DL/1378) (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (*hereinafter referred to* as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government as the case may be from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balances in their custody.

9 The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re audited by any other qualified auditor and the expenses on such re audit shall be borne by the employer

10 A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March

11 The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for whic the contributions are payable The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances

12 The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India

13 Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative

14 The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds

15 The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee

16 The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial/accounting year

17 The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue passbooks to every employee These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees

18 The account of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme

19 If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer

20 The employer shall also make good any other loss that may be caused to the provident fund due to theft burglary, defalcation mis appropriation or any other reason

21 The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time

22 If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

23 Notwithstanding anything contained in the rules of the Provident Fund of the establishment, if the amount payable to any member upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment by way of employer and employees' contribution payable under the Gratuity or pension rules be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon if he were a member of the Provident Fund under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the member as compensation or special contribution

24 The employer shall bear all the expences of the administration of the provident fund including the maintenance of accounts, submission of returns transfer of accumulations

25 The employer in relation to the establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government may from time to time decide under clause (a) of sub section (3) of section 17 of the said Act

26 The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees

27 The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment

28 The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act

29 The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions

[No S-35014/264/83 PF II]

का० आ० 4692—यत मैसर्स सुन्दरम फाइनेन्स लिमिटेड, 180, माउण्ट रोड, मद्रास 600002, इसकी शाखो सहित (त० ना०/10595) (इसके आगे जहां कही भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यत केन्द्रीय सरकार की राय मे उक्त स्थापना के कर्मचारियो के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमो मे अभिदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 म उल्लिखित कर्मचारी अभिदान की दर से कम नही है तथा इसके कर्मचारियो को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहा कही भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) मे उल्लिखित लाभो से किसी भी प्रकार से कम नही है जो इस वर्ग की स्थापनाओ म कार्यरत कर्मचारियो को उपलब्ध है,

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची मे वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो से लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोजक केन्द्र सरकार के द्वारा समय समय दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान का दर किसी समय भी कम न होगा।

3. पेंशनियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उनपर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है, तो नियोक्ता उस निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अन्तरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तर दायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखापरीक्षा कराए और ऐसे पुन: लेखापरीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

11. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने और कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

12. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

13. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

14. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

15. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

16. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छ: माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा।

18. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसको न्यासी बोर्ड निर्णय करे परंतु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

19. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

20. नियोक्ता भविष्य निधि को चोरी के कारण, लूटखसूट, ख्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

21. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करे।

22. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शैली पर किसी कर्मचारी का निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों का जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

23. स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में किसी बात के होने पर भी यदि स्थापना में कर्मचारी के सदस्य न रहने पर या उसके अन्य स्थापना में स्थानान्तरण होने पर उसका उपदान और पेंशन नियमों के अन्तर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि, नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित उस राशि से कम है जो उसे उस समय प्राप्त होती जब वह उक्त स्कीम का सदस्य होता, तो नियोक्ता मुआवजे के रूप में या विशेष अंशदान के रूप में राशि का अन्तर अदा करेगा।

24. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्चे, जिसमें लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

25. स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के अंदर ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अन्तर्गत निश्चित करे।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों का कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप से बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं० एस०-35014/266/83/पी० एफ०-II]

S.O. 4692.—Whereas Messrs Sundaram Finance Limited, 180, Mount Road, Madras-600002 with its branches (TN/10595), (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government as the case may be from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balances in their custody

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses on such re-audit shall be borne by the employer.

10. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

11. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

12. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

13. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

14. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

15. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

16. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

17. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

18. The account of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

19. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer.

20. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the provident fund due to theft, burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

21. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time.

22. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

23. Notwithstanding anything contained in the rules of the Provident Fund of the establishment, if the amount payable to any member upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment by way of employer and employees' contribution payable under the Gratuity or pension rules be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon if he were a member of the Provident Fund under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the member as compensation or special contribution.

24. The employer shall bear all the expenses of the administration of the provident fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

25. The employer in relation to the establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government may from time to time decide under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employer shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S. 35014/266/83-PF. II]

का० आ० 4693.—यतः मैसर्स उषा मेल्स को-आपरेशन्स लिमिटेड, 19-कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली (दिल्ली/2481) (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इसमें अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ।

यतः केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है;

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय समय पर दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा ।

2. नं-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगा ।

3. पेशगियों के मामले में छूट-प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी ।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा । उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा ।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे ।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है, तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा ।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जैसे भी मामला हो, समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा ।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शोधों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा ।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे । केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा-परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा ।

10. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा ।

11. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने और कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा । अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक-न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है ।

12. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय दिए गए निर्देशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा । प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

13. सरकार के निर्देशों के अनुसार निदेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा ।

14. न्यासी बोर्ड एक बन्धु-ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय को समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा ।

15. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्त तैयार करेगा ।

16. वित्तीय लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा ।

17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है । ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा ।

18. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा ।

19. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निदेश पर आयु कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा ।

20. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण, लूटघसूट, ग्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण होने हुई हानि को पूरा करेगा ।

21. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करे ।

22. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो ।

23. स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में किसी बात के होने पर भी यदि स्थापना के कर्मचारी के सदस्य न रहने पर या उसके अन्य स्थापनों में स्थानान्तरण होने पर उसकी उपदान और पेंशन नियम के अन्तर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि, नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित उस राशि से कम है जो उस समय प्राप्त होती जब वह उक्त स्कीम का सदस्य होता, तो नियोक्ता मुआवजे के रूप में या विशेष अंशदान के रूप में राशि का अन्तर अदा करेगा ।

24. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्चे, जिसमे लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा ।

25. स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के अंदर ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत निश्चित करें ।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा ।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है ।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों ।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है ।

[सं० एस०-35014/130/81-पी० एफ०-II]

S.O. 4693.—Whereas Messrs Usha Sales Corporation Ltd., 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi (DL/2481), (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishmnt with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner und where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government as the case may be from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses on such re-audit shall be borne by the employer.

10. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

11. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

12. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

13. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his represntative.

14. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

15. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

16. The Board shall issue an annual satement of account to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

17. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

18. The account of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

19. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer.

20. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the provident fund due to theft, burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason.

21. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time.

22. If the provident fund rules of the establishment provide forfeiture of the employers contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

23. Notwithstanding any thing contained in the rules of the Provident Fund of the establishment, if the amount payable to any member upon his ceasing to bean employee of the establishment or transferable on histransfer to any other establishment by way of employer and employees' contribution payable under the Gratuity or pension rules be less than the amount that would be payable as employe's and employee' contributions plus interest thereon if he were a member of the Provident Fund under the said Scheme, the emplover shall pay the difference to the member as compensation or special contribution.

24. The employer shall bear all the expenses of the administration of tthe provident fund including tthe maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

25. The employer in relation to the establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government may from time to time decide under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S. 35014/130/81-PF.II]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 1983

अधिसूचना

का०आ० 4694.—यत मैसर्ज ट्रेड लिंक्स (प्रा०) लिमिटेड, 17 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली (दिल्ली-1975) (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इसमें अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्र सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिये तैयार किये गये भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है;

अब इसलिए उक्त अधिनियम की 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय समय दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अन्तर्गत देय अंशदान से दर के स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगा।

3 पेशगियों के मामले में छूट प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जायगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की संभावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2(क) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जायेंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है, तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जैसे भी मामला हो, समय समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिये नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9 न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा-परीक्षा कराए और एस पी. लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

11. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने और कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिये समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

12. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय समय दिये गये निवेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जायेगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जायेगा।

13 सरकार के निर्देशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाये गये अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

14. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-वार रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

15 जमा किये गये अंशदानों, निकाले गये और प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखा तैयार करेगा।

16. वित्तीय लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी वार्षिक लेखा जारी करेगा।

17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जायगा।

18 लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जायगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परन्तु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

19 यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

20. नियोक्ता भविष्य निधि को चोरी के कारण, लूटपाट, ग़बन, गबन अथवा अन्य किसी कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

21. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

22 उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदान को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग

से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो ।

23. स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में किसी बात के होने पर भी यदि स्थापना के कर्मचारी के सदस्य न रहने पर या उसके अन्य स्थापना में स्थानान्तरण होने पर उसको उपदान और पेंशन नियमों के अन्तर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित उस राशि से कम है जो उस समय प्राप्त होती अब वह उस स्कीम का सदस्य होता, नियोक्ता मुआवजे के रूप में या विशेष अंशदान के रूप में राशि का अन्तर अदा करेगा ।

24. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्च जिसमें लेखों के रखरखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा ।

25. स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के अन्दर ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत निश्चित करे ।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होगा है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगायेगा ।

27. "समुचित सरकार स्थापना को धारा छूट पर और शर्तें लगा सकती है ।

28. यदि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अन्तर्गत दिये जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों ।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है ।

[सं० एस० 35014/265/83-पी०एफ०-II]

S.O. 4694.—Whereas Messrs Trade Links (Pvt.) Limited 17, Rajinder Place, New Delhi (DL/1975) (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter refrered to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estabilshment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government as the case may be from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accrodance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses on such re-audit shall be borne by the employer.

10. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

11. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

12. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

13. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

14. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

15. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

16. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

17. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue pass books to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

18. The account of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

19. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer.

20. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the provident fund due to theft, burglary, defalcation, misappropriation or any other reason.

21. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time.

22. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

23. Notwithstanding anything contained in the rules of the Provident Fund of the establishment, if the amount payable to any member upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment by way of employer and employees' contribution payable under the Gratuity or Pension rules be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon if he were a member of the Provident Fund under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the member as compension or special contribution.

24. The employer shall bear all the expenses of the administration of the provident fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

25. The employer in relation to the establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government may from time to time decide under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S. 35014/265/83-PF. II]

का०आ० 4695.—मैसर्स गंगा नगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान/1269) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचितरूप से की वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार/नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/201/83-पी०एफ०-2]

S.O. 4695.—Whereas Messrs Ganga Nagar Sugar Mills Ltd., Jaipur (RJ/1269) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of his to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(201)/83-PF.II]

का०आ० 4696—यतः मैसर्स थ्रिफोन लैबरोटरीज प्राइवेट लिमिटेड, 40/बी प्रिन्सेप स्ट्रीट, कलकत्ता-700072 (पश्चिम बंगाल/7221) (इसके आगे जहां कहीं भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इसमें अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध विनियम 1952 (1952 का 19) (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यतः केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त स्थापना के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमों में अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नहीं है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहां कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उसे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) में

उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नहीं है जो इस वर्ग की स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है;

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा एक के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची में वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापन को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय-समय दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत देय अंशदान का दर किसी समय भी कम न होगा।

3. वेशनियों के मामले में छूट-प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नहीं होगी।

4. उक्त स्कीम में कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमों से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहां एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) यह किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना में काम पर लगाया जाता है, तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि में आय के उचित लेखों और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेंगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निदेशों के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों को दुबारा लेखा-परीक्षा कराए और ऐसे दुबारा लेखा-परीक्षा के खर्च नियोक्ता वहन करेगा।

10. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

11. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने और कर्मचारियों के अंशदानों को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परि-स्थितियों में नियोक्ता नुकसानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

12. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

13. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

14. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-ब्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

15. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी से सम्बन्धित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

16. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पास-बुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा।

18. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परंतु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नहीं होगा।

19. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

20. नियोक्ता भविष्य निधि की चोरी के कारण, लूटखसूट, ख्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

21. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

22. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शैली पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानों को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड इस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

23. स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में किसी बात के होने पर भी यदि स्थापना के कर्मचारी के सदस्य न रहने पर या उसके अन्य स्थापना में स्थानान्तरण होने पर उसको उपदान और पेंशन नियमों के अन्तर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि नियोक्ता

और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित उस राशि से कम है जो उसे उस समय प्राप्त होती जब वह उक्त स्कीम का सदस्य होता, तो नियोक्ता मुआवजे के रूप में या विशेष अंशदान के रूप में राशि का अन्तर अदा करेगा।

24. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्चे जिसमें लेखों के रखरखाव रिटर्न प्रस्तुत किए जाने राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

25. स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा और प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के अंदर ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत निश्चित करें।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा अब भी कोई संशोधन होता है उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना को चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमें उसकी स्थापना आती है पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों में से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं. एम-35014/118/81/पी. एफ. 2]

S.O. 4696.—Whereas Messrs Griffon Laboratories Private Limited, 40/B-Prinsep Street, Calcutta-700072 (WB/7221) (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month.

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically. No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government as the case may be from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balances in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by any other qualified auditor and the expenses on such re-audit shall be borne by the employer.

10. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

11. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

12. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

13. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

14. The Board of Trustees shall maintain a script-wise register and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

15. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

16. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial accounting year.

17. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue passbooks to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptoJate by the Board on presentation by the employees.

18. The account of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

19. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer.

20. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the provident fund due to theft, burglary, defalcation mis-appropriation or any other reason.

21. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribed from time to time.

22. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contributions in case where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of Trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

23. Notwithstanding anything contained in the rules of the Provident Fund of the estabilshment, if the amount payable to any member upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment by way of employer and employees contribution payable under the Gratuity or pension rules be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon if he were a member of the Provident Fund under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the member as compensation or special contribution.

24. The employer shall bear all the expenses of the administration of the provident fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

25. The employer in relation to the establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government may from time to time decide under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act.

26. The employer shall display on the notice board of the estabilshment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appropriate Government" may lay down any frther conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhanced the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of estabilshment in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled of violation of any of the above conditions.

[No. S.35014/118/81-PF.II]

का० आ० 4697.—यत. मैसर्स टाटा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ब्लोक ए-शिवसागर ए-स्टेट्स, श्रमी बसन्त रोड, वारली, बम्बई-400018 (इसके आगे जहां कही भी उक्त स्थापना शब्द का प्रयोग हो इससे अभिप्राय उक्त स्थापना से है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

यतः केन्द्र सरकार की राय मे उक्त स्थापना के कर्मचारियो के लिए तैयार किए गए भविष्य निधि नियमो मे अंशदान की दर उक्त अधिनियम की धारा 6 मे उल्लिखित कर्मचारी अंशदान की दर से कम नही है तथा इसके कर्मचारियों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभ उक्त अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (इसके आगे जहा कहीं भी स्कीम शब्द का प्रयोग किया गया है उससे अभिप्राय उक्त स्कीम से है) मे उल्लिखित लाभों से किसी भी प्रकार से कम नही है जो इस वर्ग की स्थापनाओ मे कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध है,

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संलग्न अनुसूची मे वर्णित शर्तों के अधीन केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा उक्त स्थापना को उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता केन्द्र सरकार के द्वारा समय समय दिए गए निदेश के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) में उल्लिखित निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसे निरीक्षण प्रभार की अदायगी प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर करेगा।

2. न-छूट प्राप्त स्थापनाओ के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम और उसके अधीन सृजित उक्त स्कीम के अंतर्गत देय अंशदान के दर से स्थापना के भविष्य निधि नियमो के अन्तर्गत देय अंशदान की दर किसी समय भी कम न होगी।

3. पेशगियों के मामले मे छूट-प्राप्त स्थापना की स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 से कम हितकर नही होगी।

4. उक्त स्कीम मे कोई भी संशोधन जो स्थापना के वर्तमान नियमो से अधिक लाभकारी है उन पर अपने आप लागू किया जाएगा। उक्त स्थापना के भविष्य निधि नियमों में कोई भी संशोधन, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से उक्त स्थापना के कर्मचारियों के हित के प्रतिकूल प्रभावी होने की सम्भावना है वहां अपनी अनुमति देने से पूर्व, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा।

5. यदि स्थापना को छूट न दी जाती तो वे सभी कर्मचारी (जैसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) में निश्चित किया गया है) जो सदस्य बनने के पात्र होते, सदस्य बनाए जाएंगे।

6. जहा एक कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि (कानूनी) या किसी अन्य छूट-प्राप्त स्थापना का पहले से सदस्य है, को अपनी स्थापना मे काम पर लगाया जाता है, तो नियोक्ता उसे निधि का तुरन्त सदस्य बनाएगा और ऐसे कर्मचारी के पिछले नियोक्ता के पास भविष्य निधि लेखे में संचयों को अंतरित कराने और उसके लेखे में जमा कराने की व्यवस्था करेगा।

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा, जैसे भी मामला हो, समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए नियोक्ता न्यासी बोर्ड की स्थापना करेगा।

8. भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होगा जो अन्य बातों के होते हुए भविष्य निधि मे आय के उचित लेखो और भविष्य निधि से अदायगियों और उनकी अभिरक्षा में शेषो के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उत्तरदायी होगा।

9. न्यासी बोर्ड कम से कम 3 माह में एक बार बैठक करेगे और केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए मार्ग निदेशो के अनुसार कार्य करेंगे। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य योग्य लेखा परीक्षक से खातों की दुबारा लेखा-परीक्षा कराए और ऐसे पुनः लेखा-परीक्षा के खर्चे नियोक्ता वहन करेगा।

10. प्रत्येक वर्ष स्थापना के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक भविष्य निधि लेखों की एक प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए भविष्य निधि का वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

11. नियोक्ता प्रतिमाह भविष्य निधि के देय अपने और कर्मचारियों के अंशदानो को आगामी माह की 15 तारीख तक न्यासी बोर्ड को अंतरित कर देगा। अंशदानों की विलम्ब से अदायगी करने के लिए समान परिस्थितियों में नियोक्ता नुकशानी देने का उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार एक न-छूट प्राप्त स्थापना उत्तरदायी होती है।

12. न्यासी बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय दिए गए निदेशों के अनुसार निधि में जमा राशियों का निवेश करेगा। प्रतिभूतियां न्यासी बोर्ड के नाम पर प्राप्त की जाएंगी और भारतीय रिजर्व बैंक के जमा नियन्त्रण में अनुसूचित बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

13. सरकार के निदेशों के अनुसार निवेश न करने पर न्यासी बोर्ड अलग-अलग रूप से और एक साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए अधिक प्रभार का उत्तरदायी होगा।

14. न्यासी बोर्ड एक वस्तु-ध्यौरा रजिस्टर तैयार करेगा और ब्याज और विमोचन आय की समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

15. जमा किए गए अंशदानों, निकाले गए और प्रत्येक कर्मचारी मे सम्बन्धित ब्याज को दिखाने के लिए न्यासी बोर्ड विस्तृत लेखे तैयार करेगा।

16. वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण जारी करेगा।

17. बोर्ड प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक लेखा विवरण के स्थान पर पासबुक जारी कर सकता है। ये पास-बुकें कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेंगी और कर्मचारियों के प्रस्तुतीकरण पर बोर्ड के द्वारा इन्हें अद्यतन किया जाएगा।

18. लेखा वर्ष के पहले दिन आदि शेष पर प्रत्येक कर्मचारी के लेखे में ब्याज उस दर से जमा किया जाएगा जिसका न्यासी बोर्ड निर्णय करे परंतु यह उक्त स्कीम के पैरा 60 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर से कम नही होगा।

19. यदि न्यासी बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ब्याज की दर इस कारण से कि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से अदा करने में असमर्थ है तो इस कमी को नियोक्ता पूरा करेगा।

20. नियोक्ता भविष्य निधि को चोरी के कारण, लूटपाट, ग्यानत, गबन अथवा किसी अन्य कारण से हुई हानि को पूरा करेगा।

21. नियोक्ता और न्यासी बोर्ड, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर केंद्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित करें।

22. उक्त स्कीम के पैरा 69 की शर्तों पर किसी कर्मचारी को निधि के सदस्य न रहने पर यदि स्थापना के भविष्य निधि नियमों में नियोक्ताओं के अंशदानो को जब्त करने की व्यवस्था है तो न्यासी बोर्ड उस प्रकार जब्त की गई राशियों का अलग से लेखा तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पूर्व अनुमति से सुनिश्चित किया गया हो।

23. स्थापना के भविष्य निधि के नियमों में किसी बात के होने पर भी यदि स्थापना के कर्मचारी के सदस्य न रहने पर या उसके अन्य स्थापना में स्थानान्तरण होने पर उसको उपदान और पेंशन नियमों के अन्तर्गत अदा की जाने वाली नियोक्ता और कर्मचारी की राशि, नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित उस राशि से कम है जो उसे उस समय प्राप्त होती जब वह उक्त स्कीम का सदस्य होता, तो नियोक्ता मुआवजे के रूप में या विशेष अंशदान के रूप में राशि का अन्तर अदा करेगा।

24. नियोक्ता, भविष्य निधि के प्रशासन से सम्बन्धित सभी खर्चे, जिसमें लेखों के रखरखाव, रिटर्न प्रस्तुत किए जाने, राशियों का अन्तरण शामिल है, वहन करेगा।

25. स्थापना से सम्बन्धित नियोक्ता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा और प्रत्येक माह की समाप्ति पर 15 दिन के अंदर ऐसे निरीक्षण प्रभार अदा करेगा जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (क) के अन्तर्गत निश्चित करें।

26. नियोक्ता समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निधि के नियमों की एक प्रति तथा जब भी कोई संशोधन होता है, उसकी मुख्य बातों को कर्मचारियों के बहुमत की भाषा में अनुवाद करके स्थापना के बोर्ड पर लगाएगा।

27. "समुचित सरकार" स्थापना की चालू छूट पर और शर्तें लगा सकती है।

28. यदि उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापना वर्ग जिसमे उसकी स्थापना आती है, पर अंशदान की दर बढ़ायी जाती है, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान की दर उचित रूप में बढ़ाएगा, ताकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों से स्थापना की स्कीम के अंतर्गत दिए जाने वाले भविष्य निधि के लाभ किसी भी प्रकार से कम न हों।

29. उक्त शर्तों मे से किसी एक के उल्लंघन पर छूट रद्द की जा सकती है।

[सं एस-35014/267/83पी एफ-II]

S.O. 4697.—Whereas Messrs Tata Export Limited, Block A, Shivsagar Estates, Annie Besant Road, Worli, Bombay-400018, (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to the employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits which on the whole are not less favourable to the employees than the benefits provided under the said Act or under the Employees' Provident Funds Scheme 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) in relation to the employees in any other establishment of a similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 17 of the said Act

and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act within 15 days from the close of every month

2. The rate of contribution payable under the provident fund rules of the establishment shall at no time be lower than those payable under the said Act in respect of the unexempted establishments and the said Scheme framed thereunder.

3. In the matter of advances, the scheme of the exempted establishment shall not be less favourable than the Employees Provident Fund Scheme, 1952.

4. Any amendment to the said scheme which is more beneficial to the employees than the existing rules of the establishment shall be made applicable to them automatically No amendment of the rules of the provident fund of the said establishment shall be made without the previous approval of the Regional Provident Fund Commissioner and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees of the said establishment, the Regional Provident Fund Commissioner shall, before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

5. All employees (as defined in section 2(f) of the said Act) who would have been eligible to become members of the Provident Fund had the establishment not been granted exemption shall be enrolled as members.

6. Where an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund (Statutory) or a provident fund of any other exempted establishment is employed in h establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the fund and arrange to have the accumulations in the provident fund account of such employee with his previous employer transferred and credited to his account.

7. The employer shall establish a Board of Trustees for the management of the provident fund according to such directions as may be given by the Central Provident Fund Commissioner or by the Central Government as the case may be from time to time.

8. The provident fund shall vest in the Board of Trustees who will be responsible for and accountable to the Employees Provident Fund Organisation inter-alia for proper accounts of the receipts into and payments from the provident fund and the balnaces in their custody.

9. The Board of Trustees shall meet at least once in every three months and shall function in accordance with the guidelines that may be issued from time to time by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner shall have the right to have the accounts re-audited by another qualified auditor and the expenses on such re-audit shall be borne by the employer.

10. A copy of the audited annual provident fund accounts together with the audited balance sheet of the establishment for each accounting year shall be submitted to the Regional Provident Fund Commissioner within six months after the close of the financial year. For this purpose the financial year of the provident fund shall be from the 1st of April to the 31st of March.

11. The employer shall transfer to the Board of Trustees the contributions payable to the provident fund by himself and the employees by the 15th of each month following the month for which the contributions are payable. The employer shall be liable to pay damages to the Board of Trustees for any delay in payment of the contributions in the same manner as an unexempted establishment is liable under similar circumstances.

12. The Board of Trustees shall invest the monies in the fund as per directions that may be given by the Government from time to time. The securities shall be obtained in the name of the Board of Trustees and shall be kept in the custody of a Scheduled Bank under the Credit Control of the Reserve Bank of India.

13. Failure to make the investments as per directions of the Government shall make the Board of Trustees severally and jointly liable to surcharge as may be imposed by the Central Provident Fund Commissioner or his representative.

14. The Board of Trustees shall maintain a scriptwise register and ensure timely realisation of interest and redemption proceeds.

15. The Board of Trustees shall maintain detailed accounts to show the contributions credited, withdrawal and interest in respect of each employee.

16. The Board shall issue an annual statement of account to every employee within six months of the close of financial/accounting year.

17. The Board may, instead of the annual statement of accounts, issue passbooks to every employee. These pass books shall remain in the custody of the employees and will be brought uptodate by the Board on presentation by the employees.

18. The account of each employee shall be credited with interest calculated on the opening balance as on the 1st day of the accounting year at such rate as may be decided by the Board of Trustees but shall not be lower than the rate declared by the Central Government under para 60 of the said Scheme.

19. If the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Central Government for the reason that the return on investment is less or for any other reason, then the deficiency shall be made good by the employer.

20. The employer shall also make good any other loss that may be caused to the provident fund due to theft, burglary, defalcation, mis-appropriation or any other reason

21. The employer as well as the Board of Trustees shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner as the Central Government/Central Provident Fund Commissioner may prescribe from time to time.

22. If the Provident Fund rules of the establishment provide for forfeiture of the employers' contributions in cases where an employee ceases to be a member of the fund on the lines of para 69 of the said Scheme, the Board of trustees shall maintain a separate account of the amounts so forfeited and may utilise the same for such purposes as may be determined with the prior approval of the Central Provident Fund Commissioner.

23. Notwithstanding anything contained in the rules of the Provident Fund of the establishment, if the amount payable to any member upon his ceasing to be an employee of the establishment or transferable on his transfer to any other establishment by way of employer and employees' contribution payable under the Gratuity or pension rules be less than the amount that would be payable as employer's and employees' contributions plus interest thereon if he were a member of the Provident Fund under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the member as compensation or special contribution.

24. The employer shall bear all the expenses of the administration of the provident fund including the maintenance of accounts, submission of returns, transfer of accumulations.

25. The employer in relation to the establishment shall provide for such facilities for inspection and pay such inspection charges within 15 days from the close of every month as the Central Government may from time to time decide under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of said Act.

26. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the fund as approved by the appropriate authority and as and when amended thereto alongwith a translation of the salient points thereof in the language of the majority of the employees.

27. The "appripriate Government" may lay down any further conditions for continued exemption of the establishment.

28. The employee shall enhance the rate of provident fund contributions appropriately if the rate of provident fund contribution for the class of establishments in which his establishment falls is enhanced under the said Act so that the benefits under the Provident Fund Scheme of the establishment shall not become less favourable than the benefits provided under the said Act.

29. The exemption is liable to be cancelled for violation of any of the above conditions.

[No. S. 35014/267/83-PF.II]

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4698.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एडवांस पेपर मिल्स लि० नेशनल हाईवे नं० 8, ग्राम गुंजोल, तहसील नाथद्वारा (उदयपुर) इसकी फैक्ट्री और मुख्यालय उदयपुर रजिस्टर्ड आफिस, जयपुर तथा ब्रांच आफिस दिल्ली सहित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[संख्या एस-35019/278/83-पी० एफ०-2]

New Delhi, the 3rd December, 1983

S.O. 4698.—Whereas it appears to the Central Government the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Advance Paper Mills Limited, National Highway No. 8, Village Gunjol, Tehsil Nathdwara (Udaipur) including its Factory and Head Office in Udaipur, Registered Office in Jaipur and branch office in Delhi have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35019(278)/83-PF.II]

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4699.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चिफारो फार्मास्युटिकलस लि० हिमालय हाउस 38, चौरंगी रोड़, कलकत्ता-71 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017 (139)/83/पी० एफ-2]

New Delhi, the 6th December, 1983

S.O. 4699.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chefaro Pharmaceuticals Limited, Himalaya House, 38, Chowringhee Road, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017/139/83-PF.II]

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4700.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माडर्न मशीनरीज कारपोरेशन 11, क्लाईव रो, चौथी, मंजिल, कलकत्ता-700001 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017 (121)/83/पी०एफ-2]

New Delhi, the 7th December, 1983

S.O. 4700.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Modern Machineries Corporation, 11, Clive Row, 4th Floor, G.P.O. Box No. 10, Calcutta-700001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(121)/83-PF.II]

का० आ० 4701.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बंगाल आटो मोबाईल्स 25-बी पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16 और इसका सेल्स काउन्टर 2 जस्टिस चन्द्रा मैडहाब रोड़ कलकत्ता-20 और स्टोर 2/2 बी तिलजाला रोड़ कलकत्ता-46। नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017 (123)/83/पी० एफ-2]

S.O. 4701.—Whereas it appears to the Central Government the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bengal Automobiles, 25-B Park Street, Calcutta-16 and its Sales counter at 2, Justice Chandra Madhab Road, Calcutta-20 and Stores at 2/2-B, Tilajala Road, Calcutta-46 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S. 35017(123)/83-PF.II]

का० आ० 4702.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लिबरा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, 25, प्रिन्सप स्ट्रीट कलकत्ता-700072 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(124)/83-पी० एफ-2]

S.O. 4702.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Libra Transport Ltd., 25, Princep Street, Calcutta-700072 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(124)/83-PF.II]

का० आ० 4703.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पारस मटलोय फैब्रीकेटर्स प्रोईवेट लि० 60-बी, बोंडल रोड, कलकत्ता-19 और इस के हैड आफिस 3 बोर्ड स्ट्रीट कलकत्ता-19 में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017 (125)/83-पी० एफ-2]

S.O. 4703.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Paras Metalloy Fabricators Private Limited, 60-B, Bondel Road, Calcutta-19 including its Head Office at 3, Broad Street, Calcutta-19 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(125)/83-PF.II]

का० आ० 4704—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रभु इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, 1/1, तारपान घाट रोड, कलकत्ता-53 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(126)/83-पी० एफ०-2]

S.O. 4704.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Prabhu Engineering Industries, 1/1, Tarpan Ghat Road, Calcutta-53 have agreed that the provisions of the Emloyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(126)/83-PF.II]

का० आ० 4705.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर्ट एंड प्रीन्ट 85, बी० बी० गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-12 और आफिस 6 बी मलांगा लेन, कलकत्ता-12 में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017 (127)/83-पी० एफ-2

S.O. 4705.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Art and Print, 85, B. B. Ganguly Street, Calcutta-12 including its Office at 6B, Malanga Lane, Calcutta-12 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(127)/83-PF.II]

का० आ० 4706.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साउथ इंडिया प्रोजैक्टस लि० 5 और 6, फैरी लेन कलकत्ता-1 और इस की फैक्ट्री निमता रोड बेलघारिया में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(129)/83-पी० एफ-2]

S.O. 4706.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs South India Projects 5 & 6, Fairy Lane, Calcutta-1 including its factory at Nimta Road, Belgharia have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(129)/83-PF. II]

का० आ० 4707.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साईट प्लानटेशन लिमिटेड 16-ए ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्था को लागू करती है।

[सं० एस-35017/132/83/पी० एफ-2]

S.O. 4707.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Site Plantations Ltd., 16-A, Brabourne Road, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(132)/83-PF.II]

का० आ० 4708.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उद्योगी प्लास्टिकस (प्राईवेट) लि०, 14/2, चीना बाजार स्ट्रीट थर्ड फ्लोर रूम नं० 196 कलकत्ता और फैक्ट्री 1 चितपुर घाट लेन, कोसीपुर, कलकत्ता नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस-35017 (134)/83/पी० एफ० 2]

S.O. 4708.—Whereas it appears to the Central Government the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Udyogi Plastics (P) Limited, 14/2, China Bazar Street 3rd Floor, Room No. 196, Calcutta-1 including its factory at 1, Chitpur Ghat Lane Cossipore, Calcutta have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(134)/83-PF.II]

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4709.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्लास्टिक इलेक्टरोप्लेटर्स, 3, चान्दी घोष रोड, कलकत्ता-40 और 10, पोलोक स्ट्रीट, कलकत्ता-1 पर स्थित उसके कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(122)/83-पी० एफ-2]

New Delhi, the 8th December, 1983

S.O. 4709.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Plastic Flectroplaters, 3, Chandi Ghosh Road, Calcutta-40 and its office at 10, Pollock Street, Calcutta-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(122)/83-PF.II]

का० आ० 4710.—मैसर्स जी० डी० फारमेसेयूटिकल्स लिमिटेड, 43-राजेन्द्रनगर औद्योगिक कालोनी, डाकघर मोहन नगर, गाजियाबाद-201007 (उत्तर प्रदेश/3933) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब

उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन मे नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदो मे समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम मे किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा म संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसा का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे, उन मृतसदस्यो के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सबध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सख्या एस-35014/292/83-पी एफ 2]

S O 4710—Whereas Messrs G D Pharmaceuticals Limited, 43, Rajinder Nagar Industrial Colony, P O. Mohan Nagar, Ghaziabad-201007 (UP/3933) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of reutrns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of deafault, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased

members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(292)/83-PF.II]

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर 1983

का० आ० 4711—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 18 दिसम्बर, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला मोहिन्दरगढ़ में
राजस्व ग्राम धारूहेरा
हद बस्त नं० 299".

[संख्या एस-38013/30/83-एच. आई.]

New Delhi, the 12th December, 1983

S.O. 4711.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 18th December, 1983 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely:—

"Revenue village Dharuhera Had Bast No. 299 District Mohindergarh."

[No. S-38013/30/83-HI]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1983

का. आ. 4712.—मैसर्स डोडकन्या मैंगिनसाईट लिमिटेड, डाकघर-कडाकोला, मैसूर जिला (रजि. आफिस दि टाटा आयरन एण्ड स्टील कं लि., जमशेदपुर) के. एन 3548 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के किसी नाम के होने पर भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/219/83-पी एफ.-2]

New Delhi, the 22nd November, 1983

S.O. 4712.—Whereas Messrs Dodkanya Magnesite Mines Limited, P.O. Kadakola Mysore District, (Regd. Office The Tata Iron & Steel Co., Limited, Jamshedpur) (KN/3548) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No. S. 35014(219)/83-PF-II]

का. आ. 4713.—विडको टूल्स लिमिटेड 37-ए साइट नं. 4, इण्डस्ट्रीयल एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद-(उ प्र./5418) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/220/83-पी.एफ 2]

S.O. 4713.—Whereas Messrs Wodco Tools Limited, 37-A, Site No. 4, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad—Uttar Pradesh (UP/5413) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act):

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(220)/83-PF-II]

का. आ. 4714.—मैसर्स आगरा इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, डाकघर-आरटोनी, आगरा-282007, उत्तर प्रदेश (उ.प्र./4067), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा'।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014/213/83-पी एफ-2]

S.O. 4714.—Whereas Messrs Agra Engineering Industries, P.O. Artoni, Agra-282007, Uttar Pradesh (UP/4067) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of section 17of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(213)/83-PF-II]

का. आ. 4715.—मैसर्स श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, नं. 3, पादरा रोड, बड़ौदा-390005 (गुजरात/320) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का

संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उटा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों, से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/214/83-पी एफ-2]

S.O. 4715.—Whereas Messrs Shri Ambica Mills Limited, No. 3, Padra Road, Baroda-390005 (GJ/320) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of section 17of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(214)/83-PF-II]

का. आ. 4716.—मैसर्स गंगा नगर शुगर मिल्स लिमिटेड, धोलपुर (राजस्थान/909), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक

भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस. 35014/215/83-पी.एफ.-2]

S.O. 4716.—Whereas Messrs Ganga Nagar Sugar Mills Limited, Dholpur (RJ/909) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section(3A) of section 17of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and, when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within tht due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(215)/83-PF-II]

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1983

का.आ. 4717.—मैसर्स पोली-चेम लिमिटेड, 7-जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र/5207), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाग या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हस्ताक्षर नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/242/83-पी.एफ.-2]

New Delhi, the 24th November, 1983

S.O. 4717.—Whereas Messrs Polychem Limited, 7 Jamshedji Tata, Bombay-400020 (MH/5207) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under

the said scheme are enhanced, so that the benefit available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the bentfits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(242)/83-PF-II]

का. आ. 4718.—मैसर्स दि जनरल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, हेड-आफिस स्वास्तिक सुपर मार्केट आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात/4683), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/251/83-पी.एफ.-2]

S.O. .—Whereas Messrs The General Co-Operative Bank Limited, H.O. Swastic Super Market Ashram Road, Ahmedabad (GJ/4683), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisios Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(251)/83-PF-II]

का. आ. 4719.—मैसर्स अमृत वनस्पति को. लिमिटेड, जी. टी. रोड, अमृत नगर, गाजियाबाद-12 (उत्तर प्रदेश/251), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों

से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तरप्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तरप्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/250/83-पी.एफ.-2]

S.O. 4719.—Whereas Messrs Amrit Banaspati Co. Limited, G.T. Road, Amrit Nagar, Ghaziabad-12 (UP/251/) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts,

submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014/250)/83-PF-II]

का आ 4730.—मैसर्स दि जिला को-आपरेटिव लैण्ड डेवलेपमेंट बैंक लि., शिवपुरी (मध्य प्रदेश/1581), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पटट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कमचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोन रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/249/83-पी एफ 2]

S O 4720.—Whereas Messrs The District Co Operative Land Development Bank Ltd, Shivpuri (MP/1581) (herein after referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellanous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Reional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and proivde such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of said Act, within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accouts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(249)/83-PF-II]

का आ 4721 —मैसर्स पोलीचेम लिमिटेड, 7-जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र/9116), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे

उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट उस तारीख से रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत आते हैं, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/245/83-पी.एफ.-2]

S.O. 4721.—Whereas Messrs Polychem Limited, 7, Jamshedji Tata Road, Bombay-400020 (MR/9116) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellanous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time totime, direct under

clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(245)/83-PF-II]

का. आ. 4722 :—मैसर्स मेहसाना जिला को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूशर्स यूनियन लि., मेहसाना गुजरात (गुजरात/4827), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा-स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धो मे कोई भी सशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनमोदन क बिना नही किया जाएगा और जहा किसी सशोधन स कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सभावना हो वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने स पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने म असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय म किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा मे उन मृत सदस्यो के नाम-निर्देशिती या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो क सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध मे नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सख्या एस-35014/248/83-पी एफ -2]

S O 4722 —Whereas Messrs Mehsana District Co-operative Milk Producers Union Ltd, Mehsana Gujarat (GJ/4827) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ,

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relaiton to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3 All exepenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption hall be liable to be cancelled

10 Where for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(248)/83 PF II]

का आ 4723 —मैसर्स गोपाल कृष्ण एण्ड ब्रादर्स 14, विजय नगर कालोनी, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश (उ प्र / 4550) , (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ,

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/290/83-पी. एफ.-2]

S.O. 4723.—Whereas Messrs Gopal Krishna and Brothers, 14 Vijay Nagar Colony, Agra-282004, Uttar Pradesh (UP/4550) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relaiton to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(290)/83-PF. II]

का. आ. 4724 :—मैसर्स पोलीचेम लिमिटेड, 7-जमशेदजी टाटा रोड, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र/1490), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/247/83-पी. एफ.-2]

S.O. 4724.—Whereas Messrs Polychem Limited, 7, Jamshedji Tata Road, Bombay-400020(MH/1490) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employes.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(247)/83-PF. II]

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1983

का० आ० 4725.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 27 नवम्बर, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् —

"जिला सोनीपत के राजस्व ग्राम लिवासपुर, हद बस्त नं० 74 के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।"

[सं० एस-38013/27/83-एच०आई०]

ए० के भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 1983

S.O. 4725.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 27th November, 1983 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely :—

"The area comprised within the revenue village Liwaspur, Had Bast No. 74 of District Sonepat."

[No. S-38013/27/83-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1983

का० आ० 4726.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (च) के अनुसरण में श्री एन० वेंकटारमानी के स्थान पर श्री जी०पी० ओम्मान उपाध्यक्ष मैसर्स शा वाल्लेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड 154-थम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में विनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 850(अ), दिनांक 21 अक्तूबर 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियोजक संगठन के साथ परामर्श करके धारा 4 के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट) शीर्षक के नीचे क्रमांक 32 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री जी०पी० ओम्मान,
उपाध्यक्ष,
मैसर्स शा वाल्लेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड,
154-थम्बू चेट्टी स्ट्रीट,
मद्रास-600 001."

[संख्या यू-16012/20/83-एच०आई]

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

New Delhi, the 30th November, 1983

S.O. 4726.—Whereas the Central Government has in pursuance of clause (f) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri G. P. Oomman, Vice-President, M/s. Shaw Wallace and Company Limited, 154-Thambu Chetty Street, Madras as a member of the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri N. Venkataramani ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated under clause (f) of section 4 in consultation with organisation of the employers recognised by the Central Government for the purpose)" for serial No. 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Shri G. P. Oomman,
Vice-President,
M/s. Shaw Wallace and Company Limited,
154-Thambu Chetty Street,
Madras-600001."

[No. U-16012/20/83-HI]

CHITRA CHOPRA, Director

आदेश

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4727.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1698 तारीख 22 मई, 1965 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या 1, बम्बई के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री आर०टी० तुलपुले को 14 नवम्बर 1983 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० एल-11020/4/83-डी1(ए)]

ORDER

New Delhi, the 1st December, 1983

S.O. 4727.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court No. 1, Bombay,

constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 1698 dated the 22nd May, 1965 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. D. Tulpule, as the Presiding Officer of the said Labour Court with effect from the 14th November, 1983.

[F. No. S-11020/4/83-D.I (A)]

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4728.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि कोल उद्योग को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 4 में निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखंड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017(13)/81-डी-I (ए)]

New Delhi, the 2nd December, 1983

S.O. 4728.—Whereas the Central Government is satisfied that the Public interest requires that the Coal Industry, which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/13/81-D.I(A)]

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1983

का० आ० 4729.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 1413, तारीख 11, अप्रैल, 1967 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद के पीठासीन अधिकारी का एक पद रिक्त हुआ है;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री ईश्वर नारायण सिन्हा को 1-11-83 से उक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एस-11020/5/83-डी-I (ए) (ii)]

New Delhi, the 1st December, 1983

S.O. 4729.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment (Department of Labour and Employment) No. 1413 dated the 11th April, 1967 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Ishwar Narain Sinha as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect from the 1st November, 1983.

[No S-11020/5/83-D.I(A) (ii)]

का० आ० 4730.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1954 तारीख 30 जुलाई, 1960 द्वारा गठित श्रम न्यायालय, धनबाद के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हुआ है ।

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री ईश्वर नारायण सिन्हा को पहली नवम्बर, 1983 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एस-11020/5/83-डी I(ए)]

S.O. 4730.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court, Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1954 dated the 30th July, 1960.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri Ishwar Narain Sinha as the Presiding Officer of the said Labour Court, with effect from the 1st November, 1983.

[F. No. S-11020/5/83-D.I(A)]

आदेश

का० आ० 4731.—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 172, तारीख 16 जनवरी, 1960 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, बम्बई के पीठासीन अधिकारी का एक पद रिक्त हुआ है ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री आर० डी० तुलपुले को 14-11-83 से उक्त अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा० सं० एस-11020/4/83-डी I (ए)]

एस०एच०एस० अय्यर, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4731.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1, Bombay, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 172 dated the 16th January, 1960.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. D. Tulpule, as the Presiding Officer of the said Tribunal with effect from 14th November, 1983.

[F. No. S-11020/4/83-D.I(A)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983